Page-1_Layout 1 6/7/2025 2:36 PM Page 1

Mayank Jaiswal 62896 59891
Sanjay Jaiswal 94333 94683 79805 58790
EI
Jai Mata Di Enterprises
Deals in : E S I Core & Transformer Lemination Goods
158, LENIN SARANI, KOLKATA- 700 013
E-mail : sanjayjaiswal45176@gmail.com

MOHTA Publishing House

गंभीर समाचार

समय–समाज–संस्कृति

Mayank Jaiswal 62896 59891
Sanjay Jaiswal 94333 94683 79805 58790
EI
Jai Mata Di Enterprises
Deals in : E S I Core & Transformer Lemination Goods
158, LENIN SARANI, KOLKATA- 700 013
E-mail : sanjayjaiswal45176@gmail.com

वर्ष–11 अंक–7 द्विपाक्षिक समाचार पत्रिका कोलकाता, मंगलवार 10 जून – 24 जून 2025 मूल्यः 5 रुपये RNI No. WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata

पड़ोसी ‘दुष्टता’ का अंत करने को भारत करे बल प्रयोग : भागवत

‘हिंदू राष्ट्र आरएसएस का शाश्वत विचार’

समरेंद्र मित्रा

पूरा हिंदू समाज इस राष्ट्र का उत्तरदायी संरक्षक है। इस देश की प्रकृति और संस्कृति हिंदू हैं। इसलिए, यह एक हिंदू राष्ट्र है। संघ का जो भी कार्य होता है, वह इस विचार के आधार पर होता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यही आरएसएस का ‘शाश्वत विचार’ है। यह बात आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने संघ से जुड़े साप्ताहिक पत्रों ऑर्गेनाइज़र और पांचजन्य को दिए एक साक्षात्कार में कही। उन्होंने पड़ोसी देशों में ‘दुष्टता’ को समाप्त करने और वहां के हिंदू समाज की रक्षा के लिए शक्ति के प्रयोग की बात भी कही। ‘संघ में क्या नित्य है?’ इस पर उन्होंने कहा– बालासाहेब (देवरस) ने एक बार कहा था, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। इसके अलावा, संघ में बाकी सब कुछ क्षणिक है। पूरा हिंदू समाज इस राष्ट्र का उत्तरदायी संरक्षक है। इस देश की प्रकृति और संस्कृति हिंदू हैं, इसलिए यह एक हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस प्रमुख के अनुसार, हर कार्य इस मूल विचार को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसीलिए संघ का स्वयंसेवक जब शपथ लेता है, तो वह स्पष्ट रूप से कहता है : पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करते हुए हिंदू राष्ट्र का सर्वांगीण विकास। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि संघ में विभिन्न और विरोधी विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। जो शाश्वत है, वह संरक्षित है; जो क्षणिक है, वह समय, स्थान और संदर्भ के अनुसार बदलता है।

राष्ट्र सुरक्षा के संदर्भ में विचार

पहलगाम हमले और भारत की ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई प्रतिक्रिया के संदर्भ में भागवत ने कहा कि भारत को सद्गुण और शक्ति दोनों की पूजा करनी चाहिए। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए हमारी शक्ति का ऐसा स्वरूप होना चाहिए। जब कोई विकल्प न हो, तो दुष्टता का बलपूर्वक अंत करना आवश्यक हो जाता है। हमारे चारों ओर जो दुष्ट शक्तियां सक्रिय हैं, उन्हें देखकर हमारे पास शक्ति संपन्न होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई कार्रवाई की मोहन भागवत ने सराहना की और कहा कि ये हमले भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। (शेष पेज–10 पर)

मातम में बदला जीत का जश्न

राजा रॉय

दुनिया के तीन लोकप्रिय लीग– इंग्लिश प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, इंडियन प्रीमियर लीग। तीनों लीगों में कोई समानता नहीं है। मुख्य अंतर फुटबॉल और क्रिकेट का है। हालांकि, लोकप्रियता के मामले में तीनों लीग के वैश्विक मूल्य के बारे में कभी–कभी रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं। वहां, दुनिया के तीन कोनों की शीर्ष लीग कुछ हद तक समान हैं। लेकिन इस बार, तीनों लीग एक और कारण से समान हैं। हालांकि यह समानता खुशी नहीं, बल्कि एक दुखद क्षण पैदा करती है। सिर्फ एक हफ्ते में दुनिया के तीन कोनों में तीन दुखद घटनाएं हुईं। पहली घटना लिवरपूल के विजय जुलूस की थी। (शेष पेज 12 पर)

अराकान आतंकियों ने रची थी बंगाल को दहलाने की साजिश

♦ केंद्रीय खुफिया अधिकारियों ने राज्य के खुफिया अधिकारियों को किया आगाह

निज संवाददाता : आर्सा दिल्ली और राजस्थान में बैठकर इस राज्य में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। खुफिया अधिकारियों ने पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई की मदद से अराकान के आतंकियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया। आरोप है कि उस आतंकी संगठन के सदस्य मूल रूप से दिल्ली, राजस्थान और जम्मू के रोहिंग्याओं का ब्रेनवॉश कर रहे हैं। हाल ही में खुफिया अधिकारियों को उत्तर भारत में कम से कम 20 ऐसे रोहिंग्या मिले। और उनमें से कुछ से पूछताछ के बाद खुफिया अधिकारियों को उत्तर बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर छिपे दो और रोहिंग्या मिले। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उनकी मदद से आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। हालांकि, खुफिया सूत्रों से पता चला है कि अराकान के आतंकी संगठन आर्सा के सदस्य उत्तर भारत और

जम्मू–कश्मीर में कई जगहों पर छिपे हुए हैं और ब्रेनवॉश करने और आतंकी घटना को आंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि एआरएसए ने उन राज्यों में स्लीपर सेल स्थापित कर रखे हैं। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इस बारे में राज्य की खुफिया एजेंसियों को भी आगाह किया है। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि इस बार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अराकान उग्रवादी संगठन अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी या एआरएसए का समर्थन कर रही है। अराकान उग्रवादी संगठन एआरएसए ने पिछले साल म्यांमार में अपनी गतिविधियां शुरू की थीं। इस उग्रवादी संगठन के मुख्य सदस्य रोहिंग्या हैं। वैसे तो रोहिंग्या हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, लेकिन एआरएसए के सदस्य और नेता मुख्य रूप से दिल्ली, राजस्थान और जम्मू के रोहिंग्याओं को निशाना बनाते हैं। इनमें से कुछ म्यांमार सीमा पार कर जाते हैं तो कुछ बांग्लादेश सीमा पार कर इस राज्य और पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करते हैं। वे मुख्य रूप से काम की तलाश में इस देश में आने के बहाने उत्तरी भारतीय राज्यों में शरण लेते हैं। हालांकि एआरएसए का शीर्ष उग्रवादी नेता अताउल्लाह अबू अम्मार जुनूनी खुद रोहिंग्या है, लेकिन उसका जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था। वह मध्य पूर्व में पला–बढ़ा है। म्यांमार के रखाइन में उग्रवादी संगठन अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी का गठन किया गया। पिछले साल से अताउल्लाह अबू अम्मार जुनूनी खुद बांग्लादेश के अलग–अलग इलाकों में छिपकर उग्रवादी गतिविधियां शुरू कर चुका है। आईएसआई के अधिकारियों ने उससे संपर्क किया था। (शेष पेज–2 पर)

बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सैनानियों ने की स्वतंत्र राज्य की मांग

विश्वजीत मुखर्जी

खबर है कि बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राज्य के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कूटनीतिक हलकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। बलूच नेताओं ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि पिछले महीने पाकिस्तान के सोराब शहर पर कब्जा करने के बाद बलूच विद्रोही क्वेटा क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, बलूच कल्याण संघ के सदस्यों ने भारत और अन्य विदेशी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की पहल की है। बलूच नेता मीर यार बलूच पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक पत्र लिखकर अलग बलूचिस्तान राज्य की मांग के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को भेजने का अनुरोध कर चुके हैं। बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने दिल्ली में बलूचिस्तान दूतावास खोलने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है। (शेष पेज 10 पर)

सेना में बेटा भेजो, पेंशन लो

डॉ. सत्यवान सौरभ

एक बार एक नेता जी भाषण दे रहे थेअगर पाकिस्तान आँख उठाएगा, तो हम आँख निकाल लेंगे! एक नौजवान खड़ा हुआ और बोलाआपका बेटा कौन–सी यूनिट में है साहब? नेता जी मुस्कराए वो तो इंजीनियरिंग कर रहा है, विदेश जाना है उसे... जनता हँसी नहीं, रोई। क्योंकि देशभक्ति अब सिर्फ नारा बन गई है, नियति नहीं।देशभक्ति अगर सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाए, तो वह वोटबैंक की दुकान बन जाती है। जब तक नेता और उनका परिवार उस देशभक्ति को जीते नहीं, तब तक हमें उनके भाषणों पर तालियाँ नहीं, सवाल उठाने चाहिए। नेताओं को पेंशन से ज्यादा जिम्मेदारी चाहिए, और उनके बच्चों को भाषण से ज्यादा बूट। देश को सिर्फ जनता नहीं, नेता भी बराबर दें त्याग, परिश्रम और बलिदान।देशभक्ति भाषणों से नहीं,

भागीदारी से साबित होती है।जब तक नेताओं के बच्चे सेना की वर्दी नहीं पहनते, तब तक उनके ‘बलिदान’ के बोल खोखले लगते हैं। पेंशन कोई सम्मान नहीं, एक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए जो तभी मिले, जब परिवार भी राष्ट्र सेवा में उतरे। आम नागरिक के टैक्स पर ऐश करना बंद हो, अब बारी है नेता भी हिस्सा लें सरहद पर, ज़मीन पर, और ज़िम्मेदारी में। वर्ना जनता सिर्फ सुनती रहेगी, और देश सेवा का बोझ उठाते रहेंगे वही, जिनके पास न ताक़त है, न पहचान सिर्फ जुनून है। **(समाप्त)**

रिकार्ड तोड़ रहा आईपीएल–2025

2245 चौके और 1294 छक्कों के साथ बने 26381 रन

खास रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा	
रन–	26831
रन/ विकेट-	30.39
चौके –	2245
छक्के –	1294
200 से ज्यादा का रन स्कोर –	52
प्रति ओवर रन–	9.62

नयी दिल्ली : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 18 साल लंबे इंतजार के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 18 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा किया। आईपीएल 2025 सिर्फ आरसीबी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे आईपीएल इतिहास के लिए सबसे खास सीजन रहा, क्योंकि इस सीजन कई खास रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं, जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। आइए आईपीएल के उन रिकॉर्ड पर डालते हैं एक नजर।

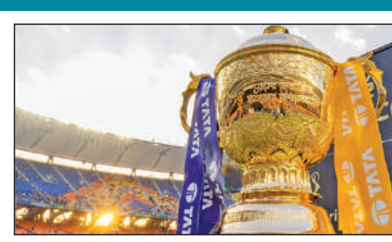

एक नजर आईपीएल 25 की फाईनल पर

आईपीएल 2025 फाइनल में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी रजत पाटीदार की कप्तानी वाली ने बिना किसी खिलाड़ी के अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 190 रन बोर्ड पर लगाए। विराट कोहली 43 रनों के साथ टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहे। पंजाब के लिए काइल जैमिसन और अर्शदीप सिंह ने 3–3 विकेट चटकाए। 191 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स को सधी हुई शुरुआत मिली। प्रभसिमरन सिंह और प्रयांश आर्या ने पहले विकेट के लिए 5 ओवर में 43 रन जोड़े। इसके बाद जोश इंग्लिस ने 39 रन बनाए। मगर जैसे ही कप्तान श्रेयस अय्यर आउट हुए तो पूरी टीम कॉन्फिडेंस खो बैठी। शशांक सिंह ने जरूर 30 गेंदों में 61 रन बनाए, मगर उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी और ने 6 रन से मैच जीतकर 18 साल बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

Page-2_Layout 1 6/7/2025 2:37 PM Page 1

शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

धमकी मिली तो पुलिस देगी सुरक्षा

निज संवाददाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। यह फैसला उनके द्वारा कथित रूप से मुस्लिम समुदाय और पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में लिया गया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर पनोली को उनकी पोस्ट को लेकर कोई धमकी मिलती है, तो राज्य पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। यह मामला उस समय गरमाया जब पनोली ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में इंस्टाग्राम और एक्स पर कथित आपत्तिजनक वीडियो साझा किया था। इस पर भारी विरोध होने के बाद उन्होंने वीडियो डिलीट कर माफी भी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद बीते 15 मई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बीते 17 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया।शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट में पेश एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने बताया कि पनोली गिरफ्तारी से बच रही थीं और बिना राज्य की जानकारी के बाहर से पकड़ी गईं। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सरकार ने तर्क दिया कि जब कोई शिकायत संज्ञेय अपराध को दर्शाती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह ने पनोली की ओर से दलील दी कि यह मामला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है और उन्होंने विवादित वीडियो को अगले ही दिन हटा दिया और माफी भी मांग ली थी। उन्होंने यह भी कहा कि ब्लास्फ़ेमी (धार्मिक अपमान) भारतीय कानून में कोई अपराध नहीं है और पनोली केवल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र को जवाब दे रही थीं।न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पनोली के कॉलेज का पता और व्यक्तिगत जानकारी शिकायत में उजागर कर दी गई, जिससे उन्हें जान का खतरा हो सकता है। अदालत ने माना कि अब और पूछताछ की जरूरत नहीं है और उन्हें जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने पनोली को बॉन्ड भरने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। साथ ही, यह भी कहा कि अगर उन्हें धमकियां मिलें तो राज्य पुलिस उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करे।मालूम हो कि शर्मिष्ठा पनोली पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है और वह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है। उनकी सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है। शर्मिष्ठा के फॉलोवर्स में एक पाकिस्तान से भी है। इस पाकिस्तानी फॉलोअर ने पहलगाम हमले के बाद शर्मिष्ठा से सवाल पूछा था। साथ ही पहलगाम हमले के आतंकियों का बचाव कर रहा था। पाकिस्तान के इस यूजर का जवाब देते हुए शर्मिष्ठा ने बीते 14 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। लेकिन इस वीडियो में शर्मिष्ठा ने बॉलीवुड एक्टरों की चुप्पी को लेकर एक विशेष धर्म को लेकर टिप्पणी की थी। जिसके बाद वो विवादों में घिर गई थी।

बेटी हुई तो पिता ने नवजात को अपनाने से किया इनकार

●जोड़ाबागान थाने में मामले की शिकायत दर्ज

निज संवाददाता : कोलकाता समेत राज्य के कई थानों में वधू के उत्पीड़न की शिकायतें लगभग हर दिन दर्ज होती रहती हैं। लेकिन क्या यह ऐसी घटना है, जिसमें पति अपनी पत्नी से बेटी के पिता बनने की खबर मिलने के बाद साफ तौर वह उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है?

शुभम चौधरी नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ ऐसी ही शिकायत है। गृहिणी ने जोड़ाबागन थाने में अपने पति, ससुर और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।उत्तर कोलकाता के बीडन स्ट्रीट निवासी शुभम ने राजस्थान के चुरू की एक युवती से शादी की थी। दोनों की शादी डेढ़ साल पहले हुई थी। आरोप है कि ससुराल वालों ने दुल्हन से दहेज के तौर पर लाखों रुपये, सोने-चांदी के जेवरात लिए। पीड़ित वधू का यह भी दावा है कि शादी के बाद उस पर और पैसे और जेवरात के लिए दबाव डाला गया। आरोप यह भी है कि उस पर अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ता गया। इसी बीच दुल्हन को पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद चौधरी परिवार उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग को लेकर परेशान हो गया! वे यह जानने के लिए बेचैन हो गए कि संतान लड़की है या लड़का। इस बीच राजस्थान की युवती का दावा है कि उसके ससुराल वाले उसे लगातार कहते रहे कि लिंग निर्धारण प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध और दंडनीय अपराध है। इसलिए वह परीक्षण कराने से कतरा रही थी। वधू ने पुलिस में शिकायत की कि इसके बाद उसके पति ने उससे साफ कह दिया कि अगर वह बेटे को जन्म देती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मां और बच्चे दोनों की देखभाल की जाएगी। लेकिन अगर लड़की पैदा हुई तो परिवार में कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आरोपों के मुताबिक, युवती के लिंग निर्धारण परीक्षण से इनकार करने पर अत्याचार शुरू हुआ। उसे ठीक से खाना नहीं खाने दिया गया। उसे ठीक से दवा भी नहीं दी गई। इसके साथ ही पैसे और जेवर की मांग कर प्रताड़ना का स्तर भी बढ़ा दिया। अंत में वधू ने रवींद्र सारणी के एक अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। उसने अपने पति को फोन किया। लेकिन पति का जवाब सुनकर वह हैरान रह गई। उसके पति ने साफ कह दिया, क्या यह लड़की है? वह लड़की मेरी नहीं है। युवती ने आरोप लगाया कि वह अपने पिता के पास राजस्थान लौट आई, क्योंकि उसका पति बालिग था और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था। उसका घर राजस्थान के चुरुर बिदासर थाना क्षेत्र में है। उसने बिदासर थाने में शिकायत दर्ज कराई। चूंकि उसका ससुराल कोलकाता में है, इसलिए इस बार जोड़ाबागान थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस जांच में जुट गई है।

बॉर्डर पर बांग्लादेशियों का तांडव

♦बीएसएफ जवान को केले के पेड़ के साथ बांधकर पीटा

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर पिछले दिनों एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान को बांग्लादेशी नागरिकों के समूह द्वारा जबरन सीमा पार खींच लिया गया। यह घटना सूती थाना क्षेत्र के चांदनी चौक बॉर्डर आउटपोस्ट के पास घटी, जहां 71वीं बटालियन के जवान श्री गणेश सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रहे थे। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जवान संदिग्ध घुसपैठियों का पीछा करते हुए अनजाने में बांग्लादेशी सीमा में प्रवेश कर गया था। हालांकि, बाद में बीएसएफ द्वारा की गई जांच में साफ हो गया कि जवान भारतीय सीमा में ही मौजूद था जब उसे जबरन सीमा पार खींचा गया।घटना के दौरान श्री गणेश को बांग्लादेश के चपाई नवाबगंज जिले के सत्राशिया गांव में स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि जवान को एक केले के पेड़ से बांधा गया था और कुछ लोग उसे गालियां दे रहे थे। वीडियो में कुछ लोग उस पर हाथ उठाते भी दिख रहे हैं। हालांकि वहां मौजूद कुछ अन्य लोगों ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की और बाद में उसे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (बीजीबी) को सौंप दिया गया। करीब चार घंटे बाद बीएसएफ और बीजीबी के बीच फ्लैग मीटिंग के बाद जवान को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। बीएसएफ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जवान को किसी प्रकार की गंभीर शारीरिक चोट नहीं आई है और वह सुरक्षित है।बीएसएफ के एक अधिकारी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा जवान मानवीय दृष्टिकोण अपना रहा था और उसने बांग्लादेशी नागरिकों को सामान्य ग्रामीण समझकर पास आने दिया। लेकिन वे अपराधी निकले और उन्होंने जवान को घेरकर जबरदस्ती बांग्लादेश में घसीट लिया। यह एक सुनियोजित हरकत थी। अधिकारी ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। बीएसएफ और बीजीबी के बीच हुई फ्लैग मीटिंग में आपसी सहयोग और सूचना साझा करने को लेकर भी चर्चा हुई। इस घटना ने सीमा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्सर भारतीय जवान मानवीय व्यवहार के तहत स्थानीय नागरिकों के साथ नरमी बरतते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग अपराधी तत्वों द्वारा किया जाना चिंताजनक है।

अराकान आतंकियों ने बनायी थी...

पेज- 1 का शेष

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अताउल्लाह का संगठन एआरएसए इस देश में हिंसा का समर्थन कर रहा है। अगर हिंसा अज्ञात चेहरे रोहिंग्याओं द्वारा की जाती है, तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो सकता है। वह योजना अच्छी तरह से बनाई गई है। इससे पहले, आतंकवादियों ने बोधगया में हिंसा के लिए रोहिंग्याओं का इस्तेमाल किया था। इसलिए, अताउल्लाह के आदेश पर एआरएसए के आतंकवादियों ने जम्मू, कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अवैध रूप से ठिकाने बनाकर उन राज्यों में रहने वाले रोहिंग्याओं का ब्रेनवॉश करना शुरू कर दिया। उनकी मदद से स्लीपर सेल स्थापित करने का काम शुरू हुआ। मार्च के मध्य में अताउल्लाह को आरएबी ने बांग्लादेश के नारायणगंज से पांच साथियों के साथ पकड़ा। इनके कैंप से भारी मात्रा में डॉलर, बांग्लादेशी टका और विदेशी मुद्राएं बरामद की गई हैं। इनसे पूछताछ के बाद आरएबी को पता चला कि आईएसआई के आदेश पर रोहिंग्याओं का इस्तेमाल कर देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की योजना बनाई जा रही है। हिंसा फैलाने की योजना इस राज्य और पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में चल रही है। खुफिया टीम को यह जानकारी मिलने के बाद खुफिया टीम ने राजस्थान, दिल्ली और जम्मू में अभियान चलाकर कम से कम 20 रोहिंग्याओं की पहचान की, जिनका ब्रेनवॉश किया गया था। इनसे पूछताछ के बाद दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया और उत्तर बंगाल के हिली बॉर्डर समेत कई जगहों पर उनसे पूछताछ की गई। खुफिया अधिकारियों ने बताया कि वे इन रोहिंग्याओं से पूछताछ कर रहे हैं और अराकान उग्रवादी संगठन एआरएसए के नेताओं की तलाश कर रहे हैं।

प्राइवेट स्कूलों की तरफ छात्रों का बढ़ रहा झुकाव

केंद्र ने पत्र लिखकर राज्यों को चेताया

निज संवाददाता : हाल ही में आई केंद्र की एक रिपोर्ट ने देश की शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति को उजागर किया है। इसके मुताबिक सिर्फ एक-दो राज्य नहीं, बल्कि ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति है। जिसके कारण छात्र अस्थिरता छोड़कर प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था की ओर झुक रहे हैं। केंद्र ने इस बारे में राज्यों को चेताया है।केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसके समानांतर प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि देश के सभी राज्यों में प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की संख्या सरकारी स्कूलों से कम है। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति शर्मनाक है। केंद्र ने खास तौर पर तीन राज्यों को लेकर चिंता जताई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की संख्या सरकारी स्कूलों से आधी है, लेकिन छात्रों की संख्या दोगुनी है। केंद्र का गणित कहता है कि फिलहाल आंध्र प्रदेश में कुल सरकारी स्कूलों की संख्या 45 हजार यानी 73 फीसदी है। इनमें से 15 हजार 262 निजी स्कूल हैं। हालांकि, सरकारी स्कूलों में सिर्फ 46 फीसदी छात्र ही पढ़ते हैं। 52 फीसदी छात्र निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। तेलंगाना में 42,901 स्कूलों में से 70 फीसदी सरकारी हैं। जबकि कुल छात्रों में से 62 फीसदी निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। उत्तराखंड में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। इन तीन राज्यों के साथ ही केंद्र ने सभी राज्यों को निजी स्कूलों में खतरनाक बढ़ोतरी को लेकर पत्र लिखा है। राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मंर सरकारी स्कूलों की जगह निजी स्कूलों में दाखिले का चलन बढ़ रहा है। मिड-डे मील की समीक्षा रिपोर्ट में भी छात्रों की संख्या में खतरनाक तरीके से कम दिखाई गई है। जानकार सूत्रों के मुताबिक देश के लगभग सभी राज्यों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है ऐसे में अभिभावकों को मजबूरन निजी शिक्षा का सहारा लेना पड़ रहा है। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार को सबसे पहले स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा।

मुंबई से 5 साल में नहीं पहुंचा ऑक्सीमीटर

पैसे गंवाने के बाद पुलिस से गुहार

निज संवाददाता : पिछले पांच सालों में कोरोना की लहर कई बार आ चुकी है। 2020 में जब पहली बार कोरोना की लहर आई थी, तब कोलकाता के एक कारोबारी ने मुंबई की एक कंपनी से ऑक्सीमीटर मंगवाया था। इसके लिए उसने कंपनी को चार लाख रुपये एडवांस भी दिए थे। तब से कोरोना इस राज्य समेत देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। हालांकि, मुंबई से कोलकाता तक ऑक्सीमीटर नहीं पहुंच पाए हैं। हाल ही में कारोबारी ने इस घटना को लेकर दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में शिकायत दर्ज कराई है।पुलिस ने बताया कि कोलकाता के कारोबारी का ऑफिस भवानीपुर के चक्रबेरिया नॉर्थ रोड पर है। 2020 में कोरोना काल में जब ऑक्सीमीटर की मांग चरम पर थी, तब मुंबई के कुर्ला ईस्ट की एक कंपनी के अधिकारियों ने भवानीपुर के कारोबारी से संपर्क किया। कंपनी ने बताया कि उसने ऑक्सीमीटर की सप्लाई की है। पहले तो भवानीपुर के कारोबारी ने ऑक्सीमीटर लेने से मना कर दिया। लेकिन एक हजार रुपये का ऑक्सीमीटर चार सौ रुपये में बिक रहा था, यह जानते हुए व्यवसायी ने ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए हामी भर दी। मुंबई की कंपनी ने फोन और व्हाट्सएप पर कई बार उससे संपर्क किया। दस लाख रुपये की जगह चार लाख रुपये में एक हजार ऑक्सीमीटर दिए जाने की बात मुंबई की कंपनी ने कही। चूंकि उस समय यात्री परिवहन पूरी तरह बंद था, इसलिए कोलकाता का व्यवसायी मुंबई भी नहीं जा सकता था। उस समय ज्यादातर कारोबार ऑनलाइन ही हो रहा था। ऐसे में मुंबई की कंपनी ने कोलकाता के व्यवसायी से कहा कि बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए पैसा भेजते ही ऑक्सीमीटर भवानीपुर के पते पर पहुंच जाएगा। इसके मुताबिक उसने भवानीपुर के शरत बोस रोड स्थित एक सरकारी बैंक की शाखा से मुंबई के एक निजी बैंक में चार लाख रुपये भेज दिए। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बावजूद ऑक्सीमीटर नहीं पहुंचा। इसके बाद से व्यवसायी कई बार मुंबई की कंपनी से संपर्क करता रहा। कई बार कोरोना की लहर आई। लेकिन ऑक्सीमीटर कोलकाता नहीं पहुंचा। उसने चार लाख रुपये रिफंड मांगे तो नहीं मिले। इस साल कोरोना का प्रकोप फिर से शुरू होने के बाद कारोबारी ने मुंबई की कंपनी से संपर्क किया। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। पांच साल तक इंतजार करने के बाद कारोबारी ने मुंबई की कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मुंबई की कंपनी के मालिक को तलब करने की तैयारी की जा रही है।

Page-3_Layout 1 6/7/2025 1:52 PM Page 1

नवान्न ने सभी विभागों से मांगा ब्यौरा, कहा–

डीए पाने वालों की संख्या कितनी?

♦ सरकार ने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की पहल

निज संवाददाता : गत 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के महंगाई भत्ते (डीए) मामले में राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया डीए का 25 प्रतिशत चुकाने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश के छह सप्ताह के भीतर बकाया राशि चुकानी होगी। हाल ही में राज्य के वित्त विभाग ने पूछा है कि राज्य के सभी विभागों में कितने डीए पाने वाले हैं। इस कदम से माना जा रहा है कि नवान्न ने कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत चुकाने की तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ढाई लाख से कुछ अधिक है।

इसके अलावा राज्य में स्कूली शिक्षकों की संख्या करीब 3 लाख 80 हजार है। विभिन्न पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों और अन्य सरकार प्रायोजित स्वायत्त संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या करीब एक लाख है। कुल मिलाकर करीब आठ लाख कर्मचारी बकाया डीए पाने के पात्र हैं। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी डीए पाने वालों की सूची में हैं। विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों का दावा है कि कुल संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। ऐसे में सभी विभागों को डीए पाने वालों की संख्या अलग-अलग बताने को कहा गया है। ऐसे में न सिर्फ वर्तमान में कार्यरत कितने कर्मचारी डीए पाने के पात्र हैं, बल्कि कितने सेवानिवृत्त कर्मचारी उस डीए के दायरे में आते हैं, इसकी भी सभी सरकारी विभागों को रिपोर्ट देनी होगी। क्योंकि, 2009 में बुद्धदेव भट्टाचार्य के मुख्यमंत्री रहते हुए पांचवें वेतन आयोग के तहत जारी आरओपीए 2019 में समाप्त हो गया था।

2019 के बाद पश्चिम बंगाल में सरकारी सेवा में लगे किसी भी सरकारी कर्मचारी को यह 25 प्रतिशत डीए नहीं मिलेगा। जो लोग 2009 या उससे पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या थे, उन्हें ही इस 10 साल की अवधि के दौरान बकाया डीए का लाभ मिलेगा। साथ ही, 2009 के बाद के 10 वर्षों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को भी उनकी अवधि के आधार पर इस डीए का लाभ मिलेगा। 2016 एसएससी पैनल में नौकरी पाने वाले सभी शिक्षकों की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नौकरी चली गई है। नवान्न सूत्रों के अनुसार बेरोजगार शिक्षकों को यह डीए नहीं मिलेगा। सीपीएम समर्थित सरकारी कर्मचारियों के संगठन समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर बकाया डीए का 25 प्रतिशत तत्काल भुगतान करने की मांग की है। समन्वय समिति के नेता विश्वजीत दत्तचौधरी ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों को उनके बकाया डीए से वंचित कर रही है।

इसलिए, हम अदालत का दरवाजा खटखटाने और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लड़ने के लिए मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि कुल बकाया डीए का 25 प्रतिशत दिया जाना चाहिए। सरकार ने उस आदेश के बाद से कोई कार्रवाई नहीं की है। अब हमें नहीं पता कि राज्य सरकार कहां और क्या ढूंढ़ रही है। दूसरी ओर, तृणमूल समर्थित राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के संयोजक प्रताप नाइक ने कहा कि महासंघ उस निर्णय का समर्थन करेगा जो हमारे मुख्यमंत्री कानूनी रूप से बकाया डीए के संबंध में लेंगे।

भाजपा सांसद की पत्नी के मिले दो वोटर कार्ड

♦ भाजपा बचाओ मंच ने जेपी नड्डा से की शिकायत

♦ इससे पार्टी का गुटीय संघर्ष भी सामने आया

निज संवाददाता : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की पत्नी कोयल मजूमदार के दो वोटर कार्ड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इससे पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। इसको लेकर पार्टी का गुटीय संघर्ष भी सामने आया। भाजपा बचाओ मंच के एक सदस्य ने पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सुकांत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि एक तरफ जब बंगाल भाजपा मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के अलग-अलग जगह नाम को लेकर मुखर है और इसको लेकर पार्टी बार-बार चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है, वैसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी का नाम मतदाता सूची में दो जगह रहने का मामला प्रकाश में आने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। नतीजतन, इस तरह की मतदाता सूची को जारी कर राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी को निशाने पर लेने आई भाजपा अब खुद व्यावहारिक रूप से दबाव में आ गई है। भगवा खेमे का एक वर्ग पूछ रहा है कि कोयल मजूमदार का नाम अब तक क्यों नहीं हटाया गया? अब दो जगहों पर मतदाताओं के नाम की शिकायत करके सत्ताधारी पार्टी को किस तरह निशाना बनाया जा सकता है? बेशक, बंगाल भाजपा में सुकांत विरोधी खेमा इस मुद्दे पर मैदान में उतर आया है। बंगाल भाजपा का गुटीय संघर्ष एक बार फिर सामने आ गया है। भाजपा बचाओ मंच के सदस्य शम्सुर रहमान ने इस मुद्दे पर पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र भी लिखा है। शमशुर ने नड्डा को लिखा कि भाजपा इस बात से असहज है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी के पास दो जगहों पर वोटर कार्ड है। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव आयोग में आरोप लगाया गया था कि सुकांत की पत्नी कोयल का नाम दो जगहों बालुरघाट और जलपाईगुड़ी की मतदाता सूची में है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने शिकायत प्राप्त होते ही जांच के आदेश दे दिये। तृणमूल ने मांग की है कि सुकांत मजूमदार जवाब दें कि उनकी पत्नी का नाम दो जगहों पर मतदाता सूची में कैसे हो सकता है। बालुरघाट से भाजपा सांसद ने इस संबंध में सफाई दी–यह राज्य प्रशासन की मंशा या अनजाने में हुई ला-परवाही के कारण हुआ होगा।

वर्षा के पहले ही राज्य में डेंगू का आतंक, प्रशासन सतर्क

निज संवाददाता : राज्य भर में प्री मानसून की वर्षा शुरू हो गयी है। बारिश के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसमें पीड़ितों की संख्या भी बढ़ रही है। इस स्थिति में डेंगू भी सिर चढ़ कर बोल रहा है। कुल(मिलाकर राज्यवासी काफी परेशान हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वर्तमान में हालात नियंत्रण में है। इसको लेकर डरने की कोई बात नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कुल 16 जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। इनमें सबसे उपर हावड़ा है। यहां पीडितों की संख्या 154 है। उत्तर 24 परगना में डेंगू पीड़ितों की संख्या 140 है। तीसरे स्थान पर हुगली है। यहां पीड़ितों की संख्या 120 है। जबकि मुर्शिदाबाद में संक्रमितों की संख्या 113 है। आंकड़ों के हिसाब से कोलकाता का स्थान पांचवा है। यहां 82 लोग पीड़ित है। मालदा में पीड़ितों की संख्या 74 है। दक्षिण 24 परगना में डेंगू से 72 लोग ग्रसित हैं। बांकुड़ा में 69 लोग इस रोग की चपेट में हैं। नवें स्थान पर नदिया है। यहां संक्रमितों की संख्या 48 है। पूर्व बर्दवान में डेंगू से पीड़ित की संख्या 44 है। पश्चिम बंगाल के साथ ही प्रत्येक वर्ष वर्षा के समय उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तामिलनाड़ु में डेंगू फैलता है। डेंगू का लक्षण कहा जाए तो ठंड के साथ बुखार, हाथ-पैर में दर्द, उल्टी आदि है। पिछले मानसून में डेंगू पीड़ित अधिकांश लोगों में सांस की तकलीफ भी देखने को मिला था। किसी-किसी में इस समस्या ने भयावह रूप धारण किया था। कोरोना पीड़ितों में आम लक्षण ही सांस की तकलीफ था। हालांकि अभी तक डेंगू ने वैसा भयावह प्रभाव नहीं डाला है। इस कारण प्रशासन का दावा है कि किसी प्रकार से डरने की बात नहीं है।

टॉप 10 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज पूर्वी भारत में नंबर 1

निज संवाददाता : कोलकाता मेडिकल कॉलेज देश में टॉप 10 में है, बंगाल का यह सौ साल पुराना मेडिकल कॉलेज पूर्वी भारत में भी नंबर 1 है। केंद्रीय स्वैच्छिक संगठन आईआईआरएफ या 'भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' कुल सात कारकों के आधार पर रैंक देता है। अपने सर्वेक्षण में, कोलकाता मेडिकल के ताज में एक नया पंख लगा है। केंद्रीय स्वैच्छिक संगठन भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' जिन सात कारकों पर रैंक देता है, उनमें शामिल हैं – संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता, अभ्यास के अवसर, शिक्षण पद्धतियाँ, शोध गतिविधियाँ, उद्योग इंटरफ़ेस यानी स्वास्थ्य संस्थान इंटर्नशिप में कितना सहयोग करता है। यह स्वास्थ्य संस्थान की प्लेसमेंट रणनीति को भी देखता है। 2023 में, कोलकाता मेडिकल कॉलेज को 12वें स्थान पर रखा गया था, इस साल कोलकाता मेडिकल कॉलेज ने शीर्ष 10 में प्रवेश किया है। यह सूची में 9 वें नंबर पर है। रैंकिंग के मुताबिक, दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नंबर 1 पर है। आईआईआरएफ रैंकिंग में, एसएसकेएम अखिल भारतीय रैंक में 29 वें नंबर पर है, कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज 36वें नंबर पर है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज 38वें नंबर पर है। इस साल, कोलकाता मेडिकल कॉलेज को राज्य में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का खिताब मिला। सर्वश्रेष्ठ को केंद्रीय संगठन आईसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) द्वारा मान्यता दी गई थी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अनुसंधान में पूर्वी भारत में सर्वश्रेष्ठ के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला स्थान पीजी अस्पताल या एसएसकेएम अस्पताल था। अनुसंधान के लिए 5 एमबीबीएस छात्रों को 50 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान दिया गया।मेडिकल कॉलेज को 10 में से 8 मूल्य मिले।

वामपंथी बुद्धिजीवियों ने की कविता अकादमी के कामकाज की जांच की मांग

निज संवाददाता : कविता अकादमी द्वारा आयोजित कविता महोत्सव के बंद होने को लेकर कवि और वाचक समुदाय में तरह-तरह के सवाल उठ रहे थे। इस संबंध में कई कवियों, वाचकों और सांस्कृतिक हस्तियों ने हाल की एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुला पत्र लिखा। करीब 60 लोगों ने खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वालों में से कई राजनीतिक रूप से वामपंथी माने जाते हैं। इस सूची में रवींद्र भारती के पूर्व कुलपति पवित्र सरकार, पूर्व सीपीएम सांसद मालिनी भट्टाचार्य, एकराम अली, रंगकर्मी कुंतल मुखर्जी और कवियित्री मंदाक्रांता सेन के नाम शामिल हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस राज्य में देश की पहली कविता अकादमी स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ममता को धन्यवाद दिया और कहा कि हम चाहते हैं कि अकादमी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो ताकि भविष्य में पश्चिम बंगाल कविता अकादमी का कविता महोत्सव और अन्य गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकें। खुले पत्र का यही बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है, जो लोग इस मांग से सहमत हैं, कृपया इस पत्र को ऊपर दिए गए नाम के साथ संलग्न करें और इसे अपनी टाइमलाइन पर पोस्ट करें। मालूम हो कि पिछली बार कविता महोत्सव वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था। यह महोत्सव हर वित्तीय वर्ष में जनवरी से मार्च के बीच आयोजित किया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसा नहीं हुआ था। कवियों और वाचकों के एक वर्ग ने कहा कि कुछ लोगों के काम को लेकर अकादमी के भीतर गुस्सा है। कुछ साल पहले, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पुरस्कार विजेताओं के नामों की सूची को लेकर अपने करीबी लोगों में अपना गुस्सा जाहिर किया था। उस समय उन्होंने मामले से सरकार के शीर्ष स्तर को अवगत कराने का अभियान शुरू किया था। कुछ लोगों का अनुमान है कि इतने गुस्से में आए कुछ लोगों ने प्रशासनिक स्तर पर शिकायत दर्ज कराई होगी। हालांकि इस बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहना चाहता था। यहां तक कि अकादमी के अध्यक्ष कवि सुबोध सरकार ने भी इस बारे में कोई धुआं साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लिखित में कोई विशिष्ट प्रश्न भेजा जाता है, तो वे लिखित में जवाब देंगे। हालांकि सवाल उन्हें सोमवार को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कविता अकादमी की एक सदस्य वाचक ब्रताती बनर्जी ने भी साफ तौर पर कहा कि उनके मन में भी सवाल है कि इसे क्यों बंद किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि समिति की आखिरी बैठक पिछले साल जून-जुलाई के आसपास हुई थी। ब्रताती ने इसमें संभवतः शब्द जोड़ दिया। मुख्यमंत्री को लिखे खुले पत्र में उस मामले का भी जिक्र है। इसमें लिखा है, कविता अकादमी की प्रबंधन समिति के एक सदस्य ने कहा कि इस अकादमी की आखिरी बैठक पिछले साल (2024) जून-जुलाई के आसपास हुई थी। यह अकादमी के लिए भी ठीक नहीं है।'प्रख्यात लोगों ने मुख्यमंत्री को लिखा-'मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मांगों पर ध्यान देंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।'

गंभीर समाचार
Classifieds/ Display/ Notice/ Others
Get Your Advertisement Noticed
Book Your Space
9874882045 9831113679
09830045693 09830011017
E-mail-gambheersamachar@gmail.com

इतिहास के शुद्धिकरण अभियान में जुड़ा अहिल्याबाई का नाम

संघ ने दिए पाठ्यक्रम में शामिल कराने के संकेत

- न केवल असम सरकार, बल्कि भारत सरकार भी इसमें पहल कर रही
- इस बार संघ परिवार का ध्यान अहिल्याबाई के प्रचार पर

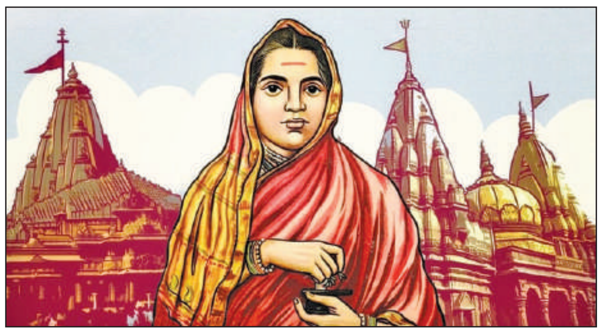

रामाशीष

मुगलों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा दिखाने वाले प्रत्येक शासक को भाजपा-आरएसएस 21वीं सदी के भारत में प्रासंगिक बनाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इस सूची में नवीनतम नाम महारानी अहिल्याबाई होल्कर का है। मई महीने के आखिर में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती थी। भाजपा पूरे देश में इसकी त्रिशताब्दी मना रही है। संघ परिवार भी अहिल्याबाई की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हालांकि, इन ऐतिहासिक पात्रों की उपस्थिति इन कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रहेगी। ऐसे संकेत हैं कि इतिहास के पाठ्यक्रम में भी उनका प्रभाव बढ़ रहा है। यानी संघ ने अहिल्याबाई को पाठ्यक्रम में शामिल कराने के संकेत दिए हैं। छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप लंबे समय से भारत की राष्ट्रवादी राजनीति में पूजे जाते रहे हैं। क्योंकि वे मुगल शासकों के प्रतिद्वंद्वी थे। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिस्पर्धियों की सूची लंबी होती जा रही है। एक ओर, संघ समर्थक शिक्षाविद् इतिहास के पाठ्यक्रम में मुगल काल के महत्व को कम करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, समकालीन मुगल भारत में स्वतंत्र अस्तित्व के साथ जीवित बचे या प्रमुखता प्राप्त करने वाले हिंदू शासकों को प्रकाश में लाने का प्रयास बढ़ रहा है। अहोम (असम) साम्राज्य के सेनापति लाचित बरफुकन की वीरता के कारण मुगल सेना ब्रह्मपुत्र में डूब गई थी। पूर्वोत्तर भारत में पैर जमाने की मुगलों की इच्छा समाप्त हो गयी। लाचित हमेशा असम में कैद रहा है। लेकिन उनकी वीरता की कहानी को असम के बाहर प्रचार नहीं मिला। 2022 में लाचित की 400वीं जयंती के आसपास, पूरे देश ने लाचित की उपलब्धियों का प्रचार करना शुरू कर दिया। न केवल असम सरकार, बल्कि भारत सरकार भी इसमें पहल कर रही है। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी का प्रचलन भी योजनानुसार बढ़ाया गया। सबसे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया। उसके बाद संभाजी की वीरता की प्रथा का विभिन्न स्तरों पर विस्तार हुआ। इस वर्ष की शुरुआत में संभाजी पर छावा नामक एक बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी। वामपंथी इतिहासकारों के एक वर्ग ने कहा है कि फिल्म के कथानक में 'इतिहास को विकृत किया गया है।' लेकिन भाजपा-आरएसएस ने इतिहासकारों के उस वर्ग के बयानों का खंडन करने का सक्रिय प्रयास किया। इस बार संघ परिवार का ध्यान अहिल्याबाई के प्रचार पर है। इंदौर की इस महारानी और राजमाता का जन्म 31 मई, 1725 को हुआ था। उनका जन्म वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। लेकिन मराठा सूबेदार मल्हारराव होल्कर के बेटे से विवाह करने के कारण वह होल्कर साम्राज्य की शासक बन गईं। उस समय मुगल साम्राज्य पतन की ओर था और कमजोर था। लेकिन पश्चिमी भारत में कुछ स्थानीय शासकों के विद्रोह ने अहिल्याबाई को युद्ध का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सभी लड़ाइयां जीत लीं और राज्य पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि, उनका सबसे बड़ा योगदान वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के रूप में याद किया जाता है। विश्वनाथ मंदिर पर आखिरी बार हमला औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद अहिल्याबाई ने इसका पुनर्निर्माण कराया। वाराणसी में वर्तमान विश्वनाथ मंदिर की मुख्य संरचना अहिल्याबाई द्वारा निर्मित की गई थी। दरअसल, पाठ्यक्रम में अहिल्याबाई को शामिल कराना ही संघ का वास्तविक लक्ष्य है। यह बात भारतीय शिक्षण मंडल (बीएसएम) के अखिल भारतीय संगठन सचिव बीआर शंकरानंद के शब्दों में और भी स्पष्ट हो जाती है। यह एक ऐसा संगठन है जो आरएसएस के सहयोगी के रूप में शिक्षा नीति और शिक्षा प्रणाली पर साल भर काम करता है। शंकरानंद ने बताया-'हमें अपनी शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम विकसित करके और विश्वविद्यालयों में विशेष चेयर स्थापित करके लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन और विचारों के बारे में समाज में एक मजबूत आख्यान स्थापित करने की आवश्यकता है।' सिर्फ अहिल्याबाई ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में प्रकाश में आए लगभग सभी अन्य ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का उल्लेख शंकरानंद ने किया है। वह कहते हैं-'चाहे अहिल्याबाई हों या लाचित बरफुकन, संभाजी राजे, राजा शशांक, बीर विक्रम किशोर माणिक्य - सभी महान आत्माओं के नाम को जीवित रखना राष्ट्रीय पुनरुत्थान का कार्य है।' उन्होंने यह भी कहा-'एक अखिल भारतीय शिक्षा संगठन के रूप में, हम इस विचार को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' वर्ष 2020 की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' तैयार करने में संगठन की सिफारिशों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कहा गया कि संगठन के शीर्ष नेता की पाठ्यक्रम विकास के संबंध में टिप्पणियां संकेतक थीं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार भी इन ऐतिहासिक पात्रों के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि, मंत्री पद के दायित्वों के कारण वह पाठ्यक्रम पर टिप्पणी करने में सतर्क हैं। सुकांत ने कहा-'एक कांग्रेस सांसद ने भी हमारे देश में पढ़ाए जाने वाले इतिहास पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। वह दक्षिण भारत से सांसद हैं।' वह कह रहे थे-'हमारा इतिहास उत्तर भारत के शासकों का इतिहास है।' दक्षिण भारत के शासकों की भी कई महान उपलब्धियां हैं। दक्षिण भारत में महिला शासक थीं जिन्होंने मुगलों को हराया। लेकिन इतिहास में उनका उल्लेख नहीं है।

राज्य सरकार ने जमीन दाताओं को नोटिस भेजना किया शुरू

गंगासागर पुल निर्माण

- राज्य में नदी पर बनने वाला 4.85 किलोमीटर सबसे लंबा पुल

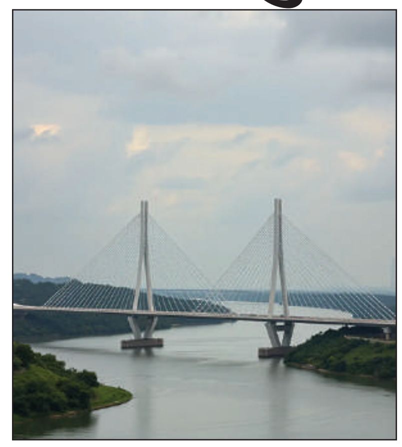

निज संवाददाता : राज्य सरकार ने गंगासागर में पुल निर्माण परियोजना में जमीन देने वाले लगभग 150 भूमि स्वामियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। ये भूस्वामी पुल के निर्माण के लिए अपनी जमीन देने के लिए सहमत हो गए हैं। इस पुल के निर्माण से गंगासागर जाने वाले तीर्थयात्रियों को मुरीगंगा नदी पार करने के लिए किसी जहाज का इंतजार करने के बजाय सीधे कोलकाता से गंगासागर पहुंचा देगा। मालूम हो कि राज्य में नदी पर बनने वाला सबसे लंबा 4.85 किलोमीटर लंबा यह पुल नदी पार करने में लगने वाले समय को घटाएगा। इसके तहत नाव से नदी पार करने में लगने वाले 45 मिनट का समय घटकर पांच मिनट से थोड़ा अधिक हो जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत ₹1,438.62 करोड़ है। पुल के निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी, राज्य लोक निर्माण विभाग ने पिछले साल निविदा जारी की थी। कुछ विस्तारों के बाद कंपनियों के लिए बोलियां जमा करने की वर्तमान समय सीमा 24 जून तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि कई इंजीनियरिंग दिग्गज बोली-पूर्व बैठक में शामिल हुए और प्रश्नों के साथ कई ईमेल भेजे। पुल को चालू करने की समय सीमा काम शुरू होने से चार साल है। कोलकाता से गंगासागर पहुंचने के लिए अब किसी वाहन से काकद्वीप लॉट नंबर 8 तक जाना पड़ता है। वहां से जहाज उन्हें सागर द्वीप पर कचुबेरिया ले जाता है। काकद्वीप से सागर द्वीप तक कारों को ले जाने के लिए बजरे उपलब्ध हैं, लेकिन ये सेवाएं अक्सर नहीं मिलती हैं। कचुबेरिया पहुंचने के बाद कार और बसें पर्यटकों को गंगासागर ले जाती हैं, जो सागर द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह बंगाल में भूमि के सबसे दक्षिणी हिस्सों में से एक है। हर साल, लाखों तीर्थयात्री गंगासागर आते हैं। राज्य सरकार के अधिकारी ने कहा-फ्लाईओवर चालू हो जाने के बाद लोगों को काकद्वीप से सागर द्वीप तक पहुंचने में केवल पांच से सात मिनट लगेंगे, जबकि अभी वहां तक पहुँचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। पुल से सागर द्वीप के निवासियों को भी लाभ होगा, जो मुख्य भूमि पर आने के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं। राज्य सरकार के अधिकारी ने कहा-कोलकाता में आपातकालीन परिवहन की आवश्यकता वाले मरीज़ इस पुल का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें नदी पार करने के लिए जहाजों के चलने के लिए उच्च ज्वार का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। परियोजना के लिए राज्य सरकार लगभग 12 एकड़ ज़मीन खरीदेगी। दक्षिण 24-परगना के जिला मजिस्ट्रेट सुमित गुप्ता ने कहा-हमने उन लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिनसे सरकार पुल के निर्माण के लिए ज़मीन खरीदेगी। उनके साथ पहले ही चर्चा की गई थी और उन्होंने अपनी ज़मीन देने के लिए सहमति दे दी है। लगभग 12 एकड़ ज़मीन खरीदी जाएगी और मालिकों को बाज़ार मूल्य के अनुसार भुगतान किया जाएगा। पुल से गंगासागर और काकद्वीप के बीच संचार तेज़ और आसान हो जाएगा। इससे गंगासागर जाने वाले तीर्थयात्रियों को मदद मिलेगी। पुल से सागर द्वीप के निवासियों को भी मदद मिलेगी, जिन्हें अब काकद्वीप पहुंचने के लिए नदी पार करने के लिए जहाज़ का इंतज़ार करना पड़ता है। एक वरिष्ठ इंजीनियर ने कहा कि पुल का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण काम था। इंजीनियर ने कहा-अधिकतम जल स्तर और पुल के डेक के बीच पर्याप्त निकासी होनी चाहिए ताकि बड़े जहाजों और जहाजों के मार्ग में बाधा न आए। खंभों के बीच एक निश्चित मात्रा में अंतर होना चाहिए। नदी का तल जल स्तर से 30 मीटर नीचे है। तल के नीचे कम से कम 70 मीटर की खुदाई करके पाइलिंग की जाएगी। इंजीनियर ने कहा-नदी पर ऐसा करना एक चुनौतीपूर्ण काम है।

पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बोले राज्यपाल

मैं कहीं नहीं जा रहा

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार के साथ तकरार को लेकर चर्चा में आए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बीते दिनों खुद को राज्यपाल पद से हटाए जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं। वह राज्य की ''खोई प्रतिष्ठा'' को बहाल करने और इसे हिंसा मुक्त बनाने की अपनी कोशिशों में नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। हृदय संबंधी बीमारी के कारण महीने भर अस्पताल में रहने के बाद 29 मई को कोलकाता स्थित राजभवन में कार्यभार संभालने वाले राज्यपाल बोस ने कहा कि वह जल्द ही राज्य के ग्रामीण इलाकों का दौरा शुरू करेंगे, जिसमें मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा प्रभावित क्षेत्र भी शामिल हैं, ताकि अलग - अलग समुदायों के बीच सौहार्द की भावना वापस लाई जा सके। राज्यपाल बोस ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा, 'बंगाल ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं यहां के गांवों में जाकर अलग-अलग समुदायों के बीच भाईचारा और दोस्ती स्थापित करने को लेकर काम करूंगा और हिंसा के खिलाफ सख्ती से लड़ूंगा। मेरे पास करने के लिए अभी बहुत काम है। 74 साल के राज्यपाल बोस ने माना कि पद से हटाए जाने से जुड़ी इस तरह की अटकलों से वो 'थोड़े परेशान' जरूर हो गए थे, लेकिन 'दिल्ली में जिम्मेदार लोगों' ने उन्हें इन अटकलों को नजरअंदाज करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, 'मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे दिल्ली में जिम्मेदार लोगों का फोन आया था। उन्होंने मुझे ऐसी अफवाहों को पूरी तरह नजरअंदाज करने और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। मुझे यहां पर शुरू किए गए अपने मिशन में पूरी ताकत से आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है। राज्यपाल बोस ने जोर देकर कहा, 'मेरा मिशन पश्चिम बंगाल के लोगों से लगातार मिलना और उनकी तकलीफों का समाधान करना है। मेरा मकसद हिंसा मुक्त बंगाल की स्थापना को लेकर अपना अथक प्रयास करना है। तबीयत को लेकर राज्यपाल बोस ने कहा कि वे अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, हालांकि डॉक्टरों की ओर से उन्हें कुछ दिनों तक काम के बोझ से खुद को मुक्त रखने की सलाह भी दी गई है। उन्होंने कहा, 'डॉक्टरों ने मुझे धीरे-धीरे आगे बढ़ने की सलाह दी है। लेकिन यह सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है।

कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तृणमूल ने दिवंगत विधायक की बेटी को बनाया उम्मीदवार

19 जून को होंगे उपचुनाव

निज संवाददाता : हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्य में एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की थी। नदिया के कालीगंज विधानसभा क्षेत्र में 19 जून को उपचुनाव होंगे। बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस ने उस मुकाबले के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। तृणमूल कांग्रेस ने कालीगंज उपचुनाव के लिए युवा चेहरे अलीफा अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है। मालूम हो कि वे दिवंगत विधायक नसीरुद्दीन अहमद की बेटी हैं। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अलीफा के पिता के निधन के कारण खाली हुए स्थान को भरने के लिए उन पर भरोसा जताया है। इस वर्ष 2 फरवरी को कालीगंज के तत्कालीन तृणमूल विधायक नसीरुद्दीन अहमद उर्फ लाल को नदिया के पलाशी स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। 71 वर्षीय विधायक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नसीरुद्दीन ने 2011 और 2021 के विधानसभा चुनावों में कालीगंज निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। उनके निधन के कारण कालीगंज सीट रिक्त हो गयी थी। वहां नियमानुसार उपचुनाव हो रहे हैं। 19 जून को देश की कई अन्य सीटों के साथ बंगाल की इस सीट पर भी नया जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जंग होगी। उस लड़ाई में राज्य की सत्ता-धारी पार्टी ने दिवंगत विधायक की बेटी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि खबर है कि विपक्षी खेमे में अभी तक किसी उम्मीदवार पर चर्चा नहीं हुई है।

बदलाव की बयार में तृणमूल शिविर ने 2011 में कालीगंज विधानसभा सीट का लालगढ़ छीन लिया था। 2016 में यहां सत्तारूढ़ खेमा पराजित हो गया था। 2021 में तृणमूल ने पुराने उम्मीदवार नसीरुद्दीन अहमद को फिर से मैदान में लाकर जीत का स्वाद चखा। अब ममता बनर्जी की पार्टी ने उनकी मृत्यु के बाद अधूरे कामों का बोझ उनकी बेटी अलीफा के कंधों पर डाल दिया है। उम्मीद है कि अलीफा यहां विपक्ष को हराकर बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कालीगंज को नया विधायक मिल जाएगा।

स्थानीय खबरें

कलकत्ता विश्वविद्यालय की कॉलेजों को सलाह-

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान करें कक्षा का आयोजन

कॉलेज को यह तय करना होगा कि कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी या व्यक्तिगत रूप से

निज संवाददाता : कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने संबद्ध कॉलेजों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कक्षाएं आयोजित करने की सलाह दी है-ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से। पिछले साल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में सत्र की देरी से शुरुआत के बाद विश्वविद्यालय को लगा कि पर्याप्त संख्या में कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं, इसलिए एक नोटिस जारी किया गया था। पिछले दिनों विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कॉलेज के प्रिंसिपलों को बीते 29 मई से शुरू हुए और 30 जून तक चलने वाले अवकाश के दौरान कक्षाएं आयोजित करने के लिए कहा है। कॉलेज को यह तय करना होगा कि कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी या व्यक्तिगत रूप से। रजिस्ट्रार देवाशीष दास द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया है-नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आपको सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि कॉलेजों की कक्षाएं 30 जून तक जारी रहेंगी। इसे कॉलेजों के लिए एक सलाह के रूप में लिया जाना चाहिए। कॉलेज को यह तय करना होगा कि कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी या व्यक्तिगत रूप से। दास ने बताया-चूंकि पर्याप्त संख्या में कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकीं, इसलिए पाठ्यक्रम अधूरा है। इसलिए, हमने कॉलेजों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कक्षाएं आयोजित करने की सलाह दी है। वे ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। पिछले साल, मई की शुरुआत में प्लस-2 के परिणाम प्रकाशित होने के डेढ़ महीने बाद केंद्रीकृत प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुरू हुआ था। आखिरकार अगस्त में कक्षाएं शुरू हुईं। सीयू के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाखों स्नातक सीटें खाली रहने के बाद, कॉलेजों ने नवंबर के अंत तक कई चरणों में अपने दम पर छात्रों को प्रवेश दिया। अधिकारी ने कहा-नवंबर तक प्रवेश जारी रहने के कारण पर्याप्त संख्या में कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकीं। एक सेमेस्टर में, कम से कम तीन महीने के लिए कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यदि अवकाश के दौरान कक्षाएं नहीं लगती हैं, तो पाठ्यक्रम अधूरा रह जाएगा। न्यू अलीपुर कॉलेज के प्रिंसिपल जयदीप सारंगी ने कहा कि वे यह समझने में विफल रहे कि विश्वविद्यालय पहले सलाह क्यों नहीं दे सका। उन्होंने कहा-अगर सलाह पहले जारी की गई होती, कम से कम एक पखवाड़ा पहले, तो कॉलेजों को कक्षाओं की योजना बनाने का समय मिल जाता। यह अचानक घोषणा इसे मुश्किल बनाती है। आशुतोष कॉलेज के प्रिंसिपल मानस काबी ने कहा कि कई शिक्षकों ने पहले ही ब्रेक के दौरान अपनी छुट्टियों की योजना बना ली है। काबी ने कहा-विश्वविद्यालय को कॉलेज प्रमुखों से बात करनी चाहिए थी ताकि पता चल सके कि कक्षाओं की कमी हुई है या नहीं। लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज की प्रिंसिपल सिउली सरकार ने कहा कि कुछ सरकारी कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन अवकाश मई की शुरुआत में शुरू हो गया था। सरकार ने कहा-हमने यह शिक्षकों पर छोड़ दिया है कि वे कॉलेज आकर कक्षाएं लेना चाहते हैं या नहीं। हमने इसे अनिवार्य नहीं बनाया है। सीयू के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने छात्रों के हित में सलाह जारी की है। अधिकारी ने कहा-कक्षाओं की कमी के बारे में हमें पक्की जानकारी है। प्रिंसिपल भी इसे जानते हैं। 2023-24 शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तहत, यदि पर्याप्त संख्या में कक्षाएं नहीं लगती हैं, तो छात्रों को नुकसान होगा। यह प्रिंसिपलों को तय करना है कि वे छात्रों की मदद के लिए काम करेंगे या नहीं।

केंद्र से बकाया राशि लाने को दिल्ली में कार्यालय खोलेगी तृणमूल

समरेंद्र मित्रा

जून महीने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्तावित दिल्ली सफर को लेकर चर्चा जोरों पर है। इसी महीने दिल्ली के 20, राजेंद्र प्रसाद रोड पर तृणमूल कांग्रेस के सदर कार्यालय का उद्घाटन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मौजूद रह सकती हैं। जून में आमतौर पर कोई अधिवेशन नहीं है। साधारणतः दिल्ली में संसद चलने के दौरान ही ममता को वहां अधिक देखा जाता है। वे खुद संसदीय पार्टी कार्यालय में जाती हैं। इसके साथ ही अन्य पार्टी के नेताओं व सांसदों के साथ मुलाकात करती हैं। लंबे समय से तृणमूल सुप्रीमो ने दिल्ली में अपना कदम नहीं रखा है। कुछ महीनों के भीतर ही बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर व्यस्तता शुरू हो जायेगी। इसलिए इस समय को उन्होंने चुना ऐसी जानकारी है। राजनीतिक सूत्रों की मानें तो ममता के दिल्ली आने का मुख्य कारण राज्य के लिए बकाया रुपये को लेकर आवाज उठाना है।

राज्य का दावा है कि विभिन्न योजना में 1 लाख 75 हजार रुपये केंद्र पर राज्य का बकाया है। हाल ही में बकाया महंगाई भत्ते का 25 फीसदी देने का सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने पर बड़ा दबाव पड़ने जा रहा है। निर्देश अनुसार जिस रुपये का जुगाड़ राज्य सरकार को करना होगा, उसका परिमाण 10 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं से आर्थिक मंजूरी को कांटछांट कर महंगाई भत्ते के लिए प्रदेय राशि जुगाड़ करने का रास्ता तो है परंतु चुनाव से पहले उस रास्ते पर चलना तृणमूल सरकार के लिए संभव नहीं है। अपितु आगामी विधानसभा चुनाव के पहले लक्खी भंडार जैसी परियोजना के लिए रुपये बढ़ाने को लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है। राजनीतिक शिविरों का कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ आमने-सामने बैठकर बकाये रुपये को देने के लिए मुख्यमंत्री उनसे आवेदन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 100 दिन का कार्य एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो रुपया राज्य को मिलना चाहिए, उससे केंद्र सरकार लगातार वंचित कर रही है। केंद्र पर बंगाल का एक लाख 75 हजार रुपये बकाया तो है ही, इसके अलावा चार वर्षों से रास्ते का विकास का रुपया भी केंद्र ने नहीं दिया है। आंकड़ा पेश करते हुए तृणमूल सुप्रीमो ने कहा है कि बंगाल में ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए मंजूर किए गये 2841 करोड़ रुपये केंद्र ने रोक रखा है।

11 वर्ष की सफलता के प्रचार में उतरी भाजपा

निज संवाददाता : इसी महीने नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11वें वर्ष में कदम रखा। आगामी एक महीने सरकार की सफलता को पूरे देश के समक्ष पेश करने की योजना को लेकर भाजपा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। 5 जून देश में आपातकाल लागू करने के 50 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन प्रत्येक जिले में सम्मेलन, परिचर्चा का आयोजन कर आपातकाल के दौरान किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की गयी थी, उसे पेश करने के लिए पार्टी को निर्देश दिया गया था। आपातकाल का विषय सामने रख कर कांग्रेस को पीछे ढकेलने की रणनीति भाजपा ने स्वीकार की है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रत्येक जिले में वृक्षारोपण कर सरकार की सफलता को सामने रख प्रत्येक जिले में प्रदर्शनी, चर्चा सभा की गयी। सरकार की सफतला को उजागर करने के लिए जून के पहले सप्ताह भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संवाददाता सम्मेलन किया। जून महीने में ही जिला स्तर पर पार्टी को सरकार के कामकाज को सामने रखकर संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने को कहा गया है। प्रत्येक शहर में, मुहल्ले में तथा गांव में विकसित भारत के निर्माण के दिशा में संकल्प लेने को कहा गया है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा इलाके में एक बार कई अस्थायी केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है। सरकारी परियोजनाओं के माध्यम से किस प्रकार सुविधा मिलेगी, उसका दिशा-निर्देश उन केंद्रों से देने को कहा गया है। आयुष्मान योजना का लाभ सभी को मिल सके, इसलिए अगले एक महीने तक घर-घर उन परियोजना के लिए नाम सूचीबद्ध करने का निर्देश भाजपा कर्मियों को दिया गया है।

एसएससी अधिसूचना पर विपक्ष का विस्फोटक आरोप, कहा

नई परीक्षा में भी भ्रष्टाचार की बू

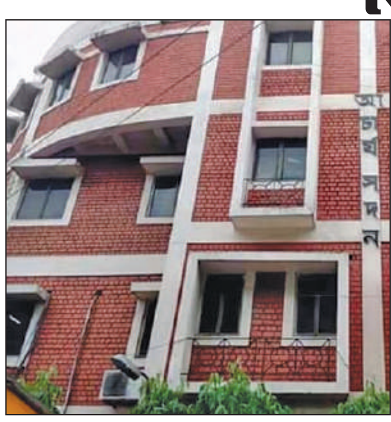

निज संवाददाता : कोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी सरकार को 2016 की एसएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को फिर से लेने के लिए अधिसूचना जारी करने पर मजबूर होना पड़ा। और जैसे ही वह अधिसूचना प्रकाशित हुई, विपक्ष को नए भ्रष्टाचार की बू आने लगी। उनका दावा है कि नई परीक्षा के अंकों को चालाकी से विभाजित किया गया है ताकि पैसे लेकर नौकरी पाने वाले लोगों को फिर से नौकरी मिल सके। एसएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की अधिसूचना विगत शुक्रवार को प्रकाशित हुई। नौकरी चाहने वालों को 60 लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा, 10 अंक शैक्षणिक योग्यता के लिए, 10 अंक शिक्षण अनुभव के लिए, 10 अंक साक्षात्कार के लिए और 10 अंक कक्षा शिक्षण कौशल के लिए आवंटित किए गए हैं। और यहीं से विपक्ष को फिर से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्योंकि 2016 की परीक्षा में लिखित परीक्षा के लिए 55 अंक, शैक्षणिक योग्यता के लिए 35 अंक और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए 10 अंक आवंटित किए गए थे।

यानी शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित अंकों को 35 से घटाकर 10 कर दिया गया है। यहीं से सवाल उठता है। बंगाली शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी संघ के नेता स्वप्न मंडल ने कहा कि इन नियमों से उन लोगों को लाभ होगा, जिनकी पहचान भ्रष्टाचार के जरिए नौकरी पाने वाले के रूप में नहीं की गई है। इन नियमों के तहत नई नौकरी चाहने वालों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर साक्षात्कार और शिक्षण कौशल में अधिक अंक देने का अवसर मिलता है, तो धोखाधड़ी की संभावना है। सरकार चाहे तो किसी को कम अंक या किसी को अधिक अंक दे सकती है। हमें समझ में नहीं आता कि सरकार कोई नई कानूनी जटिलताएं आमंत्रित कर रही है या नहीं। वकील फिरदौस शमीम ने कहा कि नए नियमों में पिछले नियमों से काफी बदलाव किया गया है। शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित अंकों को 35 से घटाकर 10 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कम शैक्षणिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर बार-बार उलझनें पैदा कर रही है। क्योंकि यह राज्य सरकार नौकरियां देना नहीं चाहती है। राज्य सरकार का बजट पूरी तरह से खाली है। यह सरकार शिक्षण कौशल और साक्षात्कार में अंक बढ़ाकर योग्य लोगों के साथ अयोग्य लोगों को भी नौकरी देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अयोग्य लोगों ने पैसे दिए हैं।

4 दिन में अस्पताल ने बनाया 12 लाख का बिल! फिर मरीज की हुई मौत!

निज संवाददाता : शहर के एक निजी अस्पताल ने 12 लाख रुपये का बिल बनाया है। स्वास्थ्य आयोग इस अभूतपूर्व घटना का गवाह रहा। प्रणब रॉय चौधरी ने अपने 73 वर्षीय पिता पल्लव रॉय चौधरी को 13 अप्रैल को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया था। फिर 17 अप्रैल को उनकी तीन न्यूरो सर्जरी हुई। इसके बाद 17 अप्रैल को परिवार ने फैसला किया कि निजी अस्पताल का भारी खर्च संभव नहीं है, इसलिए वे राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत मरीज का इलाज करेंगे। हालांकि, 18 अप्रैल की सुबह प्रणब रॉय चौधरी की ब्रेन डेथ से मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि इस निजी अस्पताल ने महज चार दिन में 12 लाख का बिल बना दिया। परिवार ने इस घटना की शिकायत स्वास्थ्य आयोग से की। आयोग ने एक जांच समिति गठित की है। राज्य स्वास्थ्य निदेशक समेत तीन सदस्यीय समिति में स्वास्थ्य आयोग के सचिव अरसद हसन वारसी और राज्य स्वास्थ्य आयोग के सदस्य डॉ. माखन साहा शामिल थे। समिति जांच करेगी कि रॉयचौधरी परिवार पर इतने बिल क्यों हैं। 6 लाख रुपए स्थायी जमा के तौर पर रखे जाएं। जांच समिति जो फैसला लेगी, उसे जरूरत पड़ने पर ब्याज सहित मृतक की पत्नी को लौटाया जाएगा। परिवार का यह भी आरोप है कि ब्रेन डेथ के बाद मृतक के परिवार पर अंगदान के लिए दबाव बनाया गया। दो डॉक्टरों ने दबाव बनाया। आयोग ने सिफारिश की है कि वे दोनों डॉक्टर माफी मांगें और मृतक की पत्नी को पत्र लिखें। मरीज के परिवार को इलाज में लापरवाही के लिए मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है।

MOHTA Publishing House

Mohta Publishing House
28/5, Convent Road, Moulali,
Kolkata-700014
Phone : 98300-45693
E-Mail : gambheersamachar@gmail.com

Page-6_Layout 1 6/7/2025 1:57 PM Page 1

संपादकीय

देशहित पर भारी पड़े दलगत स्वार्थ

आखिरकार शशि थरूर के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने और आपरेशन सिंदूर का औचित्य बताने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल अपने एक और नेता सलमान खुर्शीद पर भी हमला बोल दिया। जैसे थरूर ने ऐसे नेताओं का नाम न लेते हुए उन्हें जवाब दिया, वैसे ही खुर्शीद ने भी। इसी के साथ उन्होंने अपनी पीड़ा का बयान करते हुए यह प्रश्न भी किया कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन है? यह केवल एक प्रश्न नहीं, पीड़ा भी है। इस पीड़ा का अनुभव कांग्रेसजन भी कर रहे होंगे, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि थरूर और खुर्शीद पर हमले पार्टी नेतृत्व के करीबी कर रहे हैं। थरूर और गांधी परिवार के रिश्ते शायद तबसे ठीक नहीं चल रहे, जबसे उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। राहुल गांधी के अति विश्वासपात्र जयराम रमेश ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा था, 'कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में' फर्क होता है। लोकसभा चुनाव का टिकट न मिलने पर पाला बदलने और अब खुद को कांग्रेस का सिपाही कहने वाले उदितराज की समझ से थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता बन गए हैं। अतीत में नरेन्द्र मोदी और शशि थरूर एक-दूसरे की आलोचना कर चुके हैं। बाद में कुछ मौकों पर दोनों ने एक-दूसरे की प्रशंसा भी की। थरूर ने आपरेशन सिंदूर को भारत की उचित प्रतिक्रिया बताते हुए ट्रंप पर भी निशाना साधा। थरूर के विपरीत सलमान खुर्शीद गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। वह पहले भी भाजपा के आलोचक रहे हैं और अब भी हैं। उन्होंने कहा भी, 'क्या यहां मैं सरकार का विरोध करने आया हूं? यदि ऐसा करना होगा तो भारत जाकर करूंगा। यहां तो मैं भारत के पक्ष में बोलने आया हूं।' यह वही खुर्शीद हैं, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि हिंदुत्व इस्लामिक स्टेट और बोको हराम जैसा है। तब उनकी आलोचना इसी स्तंभ में की गई थी। खुर्शीद पर इसलिए निशाना साधा गया, क्योंकि इंडोनेशिया में उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनु. 370 हटाने को सही बताया। ध्यान दें कि इस अनुच्छेद को हटाने के फैसले का समर्थन करने वाले कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। यह राहुल गांधी और उनके करीबी ही बता सकते हैं कि थरूर के साथ खुर्शीद को निशाने पर लेने से कांग्रेस या फिर देश के कौन से हित सध रहे हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए इसे समझना कठिन है। क्या कांग्रेस नेतृत्व यह बुनियादी बात भी नहीं समझता कि मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार और भारत में अंतर है? आम तौर पर अपने ही नेता की आलोचना गुटबाजी, उसके बढ़ते कद या फिर नेतृत्व की उससे नाराजगी के चलते की जाती है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के ऐसे नेता नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा गया। अपने देश में दूसरे दलों और उनके नेताओं पर सही-गलत आरोप लगाने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इसका भी एक समय होता है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे विश्व में भारत की बात कहने से ज्यादा जोर एक्स पोस्ट के जरिये कांग्रेस पर हमला करने में दे रहे हैं। हैरानी है कि सरकार और भाजपा की ओर से कोई उनसे यह क्यों नहीं कह रहा कि दुबे जी, जरा थम जाएं, देश लौटकर कांग्रेस का कच्चा-चिट्ठा खोलिएगा और अभी उस पर ध्यान दें, जिसके लिए विदेश गए हैं।

फेसबुक या फूहड़बुक

डिजिटल अश्लीलता का बढ़ता आतंक और समाज की गिरती संवेदनशीलता

प्रियंका सौरभ

जब सोशल मीडिया हमारे जीवन में आया तो उम्मीद थी कि यह विचारों को जोड़ने, संवाद को मज़बूत करने और जन-जागरुकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। लेकिन आज, 2025 में विशेषकर फेसबुक जैसे मंच पर जिस तरह से अश्लीलता और फूहड़ता का आतंक फैलता जा रहा है, वह न केवल चिंत-ाजनक है, बल्कि सभ्यता की चादर में लिपटे हमारे समाज की मानसिक पतनशीलता को भी उजागर करता है।

अश्लील वीडियो की वायरल संस्कृति : मनोरंजन या मानसिक विकृति?

आज फेसबुक पर एक महिला या किसी व्यक्ति की निजता से खिलवाड़ करती हुई अश्लील वीडियो अगर गलती से अपलोड हो जाती है तो उसके रिपोर्ट और हटने से पहले ही लाखों लोग उसे डाउनलोड, साझा और एक-दूसरे से माँग लेते हैं। यह सिलसिला इतना भयावह और संगठित रूप में होता है कि लगता है जैसे सभ्य समाज नहीं, किसी डिजिटल भेड़िया झुंड में रह रहे हों। सबसे अधिक विचलित करने वाली बात यह है कि यह सब पढ़े-लिखे, संस्कारी दिखने वाले, प्रोफ़ाइल पर तिरंगा, ॐ या गीता का श्लोक डालने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा करते हैं। तो फिर सवाल उठता है क्या यही हमारी वास्तविक मानसिकता है? क्या हम दोहरे चरित्र वाले समाज के प्रतिनिधि हैं जो मंच पर नैतिकता की बात करता है और अकेले में अश्लीलता का उपभोग करता है?

समाज की चुप्पी : एक और अपराध

इन वीडियो को रिपोर्ट करना, विरोध करना और हटवाना तो दूर की बात, लोग इन्हें चुपचाप देखते हैं, सहेजते हैं और निजी संदेशों में साझा करते हैं। जो कृत्य समाज में निंदा के योग्य होना चाहिए, वह मनोरंजन और मोबाइल संदेशों का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में समाज केवल अपराधी का साथ नहीं देता, बल्कि वह खुद अपराध का भागीदार बन जाता है।

पीड़िता नहीं, समाज शर्मसार हो

हर बार जब कोई महिला किसी वीडियो में जबरन या धोखे से दिखा दी जाती है, तो समाज उसे कोसने लगता है जबकि असली दोषी वह नहीं, वह व्यक्ति होता है जिसने उसका वीडियो बनाया और वे लोग होते हैं जो उसे साझा करते हैं। वास्तव में शर्म तो उस समाज को आनी चाहिए जो दूसरों की पीड़ा को क्लिकबेट और मज़ा समझता है।

हम, समाज और हमारी भागीदारी

अब प्रश्न यह है कि क्या हम केवल फेसबुक को दोष देकर अपने दामन को पाक-साफ़ मान सकते हैं? बिलकुल नहीं। जब हम स्वयं ऐसे सामग्री को देख रहे हैं, साझा कर रहे हैं या मौन हैं, तो हम भी अपराध में साझेदार बन जाते हैं। हमारे बच्चों, बहनों, पत्नियों और समाज की महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून से नहीं होगी बल्कि हमारी मानसिकता से होगी। और अगर हम वही मानसिकता पालें जो अपराधियों की होती है दूसरों की निजता को ताकना, उन्हें वस्तु समझना, उन्हें मानवता से नीचे गिराना तो फिर हम भी किसी से कम दोषी नहीं हैं।

समाधान की दिशा में कुछ सुझाव :

1. डिजिटल नैतिक शिक्षा : विद्यालयों, महाविद्यालयों और नौकरी के प्रशिक्षण केंद्रों में डिजिटल आचार संहिता पर विशेष कक्षाएँ होनी चाहिए। **2. कड़ा कानून और डिजिटल सतर्कता :** अश्लील वीडियो को साझा करने वालों पर सख्त साइबर कानून लागू हों और समय पर कार्रवाई हो। **3. सोशल मीडिया मंचों की जवाबदेही :** फेसबुक जैसी कंपनियों को भारत सरकार के अधीन विशेष निगरानी प्रकोष्ठ में जवाबदेह बनाया जाए। **4. जन-जागरुकता अभियान:** स्वयंसेवी संस्थाओं, लेखकों, पत्रकारों और जागरूक नागरिकों को मिलकर डिजिटल शुचिता पर अभियान चलाने चाहिए।सोच बदलनी होगी सभ्यता केवल तन से नहीं होती, मन से होती है। शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। अगर हम अपने ही समाज की बहनों की पीड़ा में लज्जा नहीं, मज़ा ढूंढने लगें तो यह गिरावट नहीं, मानवता की हत्या है। इसलिए यह समय है जब हमें फेसबुक को भी आईना दिखाना होगा और खुद को भी। नहीं तो फेसबुक जल्द ही फूहड़बुक में बदल जाएगा, और हम सब उसमें एक-एक कर डूब जाएंगे बिना किसी पश्चाताप के।

मध्यप्रदेश में खुद महिलाएं लिख रही हैं बदलाव की इबारत

अजय कुमार मोहता
(संपादक, गंभीर समाचार)

कभी समाज की चुप्पियों में खोई, अवसरों से दूर और सवालों से घिरी स्त्री शक्ति, आज मध्यप्रदेश में बदलाव की इबारत खुद लिख रही है। एक समय था जब सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार को लेकर महिलाओं के मन में असमंजस था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। मध्यप्रदेश अब केवल योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि एक नई सोच, नई दिशा और नए आत्मविश्वास का पर्याय बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को केवल नीति या योजना नहीं, बल्कि 'जन आंदोलन' मानकर चल रही है। 'नारी शक्ति मिशन' इसी सोच की परिणति है, जिसके तहत महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का वो मंच दिया जा रहा है जिसकी वे वर्षों से हकदार थीं।

कामकाजी महिलाओं का 'अपना ठिकाना'

काम के लिए घर से दूर रहने वाली महिलाओं के लिए अब सुरक्षित और सुविधाजनक हॉस्टल किसी सपने से कम नहीं। इंदौर और भोपाल में 250-250 बेड वाले तीन वर्किंग वुमन हॉस्टल पहले से संचालित हैं। अब 'स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स' के अंतर्गत आठ नए हॉस्टलों को मंजूरी मिली है, जिनमें से चार महिला एवं बाल विकास विभाग और चार उद्योग विभाग द्वारा संचालित होंगे। सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम और झाबुआ में हॉस्टल निर्माण के लिए 40.59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

जब ज़िंदगी मुश्किल हो, तब साथ देता है 'वन स्टॉप सेंटर'

कभी किसी संकट में फंसी महिला अकेली न रहे, इस सोच को साकार कर रहे हैं प्रदेश के वन स्टॉप सेंटर। घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न या सामाजिक शोषण से जूझ रही महिलाओं को 57 केंद्रों के माध्यम से अब तक 1.27 लाख से अधिक महिलाएं राहत पा चुकी हैं। 2024-25 में 31,763 महिलाओं को सहायता मिली और अब आठ नए केंद्रों को मंजूरी दी गई है।

'लाड़ली बहना योजना' सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता का मेल

हर महीने 1.27 करोड़ बहनों के खातों में 1551.86 करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक सहायता भेजी जा रही है। इस योजना ने महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता दी है, बल्कि उन्हें डिजिटल सा-क्षरता का हिस्सा बनाकर भविष्य के लिए तैयार भी किया है। मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 2024-25 में 2.73 लाख बालिकाओं का पंजीकरण हुआ और 223 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति सीधे वितरित की गई। अब तक 50 लाख से अधिक बेटियां इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं।

मातृत्व को सम्मान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

मातृत्व को गरिमा देने वाली इस योजना के अंतर्गत 2024-25 में 6.30 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई है। यह योजना एक माँ के संघर्ष को सशक्त समर्थन देती है। महिलाएं अब सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि व्यापार और रोज़गार की धुरी बन रही हैं। अब तक 30,264 महिला समूहों और 12,685 महिला उद्यमियों को कम ब्याज पर ऋण और 2% ब्याज अनुदान के रूप में 648.67 लाख रुपये दिए गए हैं।

संकट में सुरक्षा की छांव 'शक्ति सदन'

बेहद कठिन हालात में फंसी महिलाओं और बच्चियों के लिए 13 जिलों में 14 शक्ति सदन सक्रिय हैं। 2024-25 में 1824 महिलाएं और 461 बच्चे इन केंद्रों से लाभान्वित हुए। आगे चलकर सभी संभागीय मुख्यालयों में शक्ति सदन स्थापित किए जाएंगे। 11 हजार से अधिक बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण मिला है। इनमें से 156 बालिकाओं का चयन विभिन्न सरकारी पदों पर हुआ है। इसके साथ ही 2.6 लाख महिलाएं सुरक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूक हुई हैं।

'हम होंगे कामयाब'

100 दिवसीय इस जागरुकता अभियान के तहत प्रदेश में जेंडर संवाद, बाल विवाह, साइबर सुरक्षा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, डिजिटल साक्षरता जैसे मुद्दों पर महिलाओं को जागरूक किया गया। यह अभियान न केवल जानकारी देने का माध्यम बना, बल्कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाया। मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब सरकारी घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखाई देने वाला सामाजिक परिवर्तन बन चुका है। गांव-गांव, घर-घर नारी शक्ति की नई चेतना पनप रही है। आत्मनिर्भरता, सम्मान और समानता की दिशा में उठाए गए ये कदम ना केवल महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, बल्कि एक मजबूत और समावेशी राष्ट्र की नींव भी रख रहे हैं।मध्यप्रदेश की यह यात्रा बताती है कि जब राज्य संकल्प ले, तो परिवर्तन अवश्य होता है और नारी शक्ति उसका सबसे मजबूत स्तंभ बनती है।

जुलाई में हो सकती है भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा- ऐसा रास्ता निकाला, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद

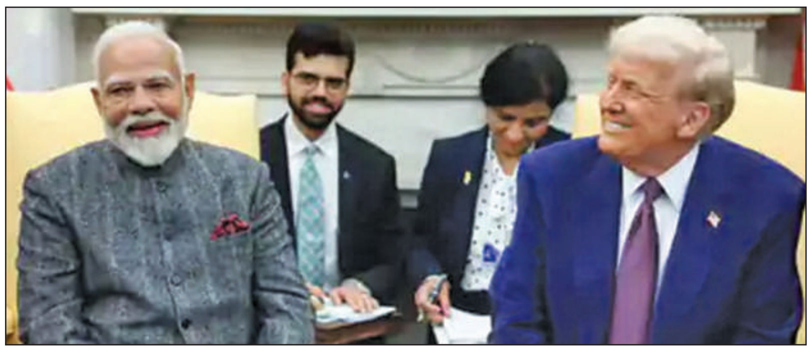

नई दिल्ली : भारत और अमेरिका के बीच जुलाई तक ट्रेड डील साइन होने की संभावना है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने बीते दिनों कहा, भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द ट्रेड डील हो जाएगी, क्योंकि दोनों देशों ने ऐसा रास्ता खोज लिया है जो दोनों के लिए फायदेमंद है। लुटनिक ने यह बात वॉशिंगटन में -इंडिया स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप फोरम के लीडरशिप समिट में कही। पिछले दिनों भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि दोनों देश एक-दूसरे के कारोबार को प्राथमिकता देना चाहते हैं और टीमों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। इसके साथ ही अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा जब दोनों तरफ सही लोग टेबल पर बैठे, तो हम सही दिशा में आगे बढ़े। अब डील में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सूत्रों के मुताबिक 8 जुलाई से पहले दोनों देश एक अंतरिम समझौते पर पहुंच सकते हैं।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से दोनों देश ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। ये टैरिफ भारत पर 8 जुलाई से लागू होंगे। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था अमेरिका और भारत ने ट्रेड डील के लिए शर्तों को फाइनल कर दिया है। इसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अप्रैल में अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने 22 अप्रैल को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक इवेंट में यह जानकारी दी थी। जेडी वेंस ने कहा था 'मेरा मानना है कि यह राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह फाइनल डील का एक रोडमैप तैयार करेगा।'

2 अप्रैल 2025 को ट्रम्प ने 'लिबरेशन डे' का नाम देते हुए दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों से आने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उनका दावा था कि ये टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और उन देशों को सबक सिखाएंगे जो अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं और ज्यादा बेचते हैं। हालांकि बाद में चीन को छोड़कर बाकी देशों पर टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। ट्रम्प के टैरिफ के जवाब में चीन ने भी टैरिफ लगाया था। इसी वजह से चीन को टैरिफ से राहत नहीं दी गई थी। चीन का टैरिफ बढ़ाकर 145 फीसदी कर दिया गया था। बातचीत के बाद चीन पर से भी टैरिफ को कम कर दिया गया।

कट्टरपंथियों के आगे झुके मोहम्मद यूनुस

बांग्लादेशी करेंसी नोटों से हटाई गई बंगबंधु की तस्वीर

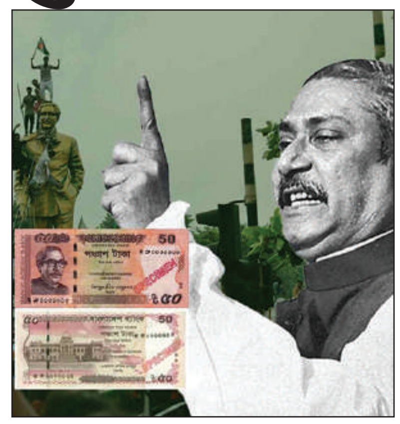

निज संवाददाता : मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। कट्टरपंथियों की मांग के आगे झुकते हुए बांग्लादेश की करेंसी से राष्ट्रपिता बंगबंधु मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। बांग्लादेश रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों इस नोट को आधिकारिक तौर पर जारी किया तो चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठता है कि यूनुस 1971 के इतिहास को मिटाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? बैंक द्वारा इस नोट को आधिकारिक तौर पर जारी किए जाने के बाद बांग्लादेश बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने कहा-नोटों की इस नई सीरीज में लोगों की कोई तस्वीर नहीं होगी। इसमें केवल बांग्लादेश की वास्तुकला, ऐतिहासिक स्थानों और प्रकृति की तस्वीरें होंगी। बैंक की ओर से कुल तीन नोट जारी किए गए हैं। ये 20, 50 और 1000 रुपए के हैं। 20 रुपए के नोट पर जहां हिंदू मंदिर की तस्वीर है, वहीं 50 रुपए के नोट पर मुस्लिम वास्तुकला की तस्वीर है और 1000 रुपए के नोट पर बौद्ध मंदिर की तस्वीर है। बांग्लादेश बैंक ने कहा है कि बाद के नोटों के डिजाइन में भी चरणबद्ध तरीके से बदलाव किया जाएगा। गौरतलब है कि 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिलने के बाद से ही बंगबंधु मुजीबुर रहमान की तस्वीर बांग्लादेशी करेंसी पर रही है। हालांकि पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, को अपदस्थ कर दिया गया था। जब उन्होंने भारत में शरण ली तो मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में सलाहकार सरकार का मुखिया बना दिया गया। दूसरी ओर, 1971 के इतिहास को मिटाने के लिए देश भर में कट्टरपंथी दल सक्रिय हो गए। आखिरकार यूनुस की सरकार ने सुर बदल दिए। हालांकि बांग्लादेश का एक बड़ा तबका यूनुस की इस हरकत से नाराज है। आरोप हैं कि सलाहकार सरकार को हटाने के लिए चुनाव की मांग उठने लगी है। हालांकि यूनुस बिना चुनाव के ज्यादा समय तक सत्ता का लुत्फ उठाना चाहते हैं। इसलिए कट्टरपंथियों को खुश करना अब यूनुस के लिए आसान रास्ता बन गया है। एक के बाद एक उस लक्ष्य की ओर गतिविधियां चल रही हैं।

नवान्न ने किया प्रशासन के कई शीर्ष पदों में फेरबदल

निज संवाददाता : नवान्न ने एक और प्रशासनिक फेरबदल किया है। कई आईपीएस अधिकारियों को नए पदों पर भेजा गया है। कई को संयुक्त जिम्मेदारी दी गई है। कई अधिकारियों को नए पद दिए गए हैं। डीजी पद का प्रभार संभाल रहे आईपीएस राजीव कुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स) के पद पर कार्यरत थे। मंगलवार को नवान्न द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में अनूप कुमार अग्रवाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स) की जिम्मेदारी दी गई है। वे सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव, जलपाईगुड़ी मंडल आयुक्त के पद पर काम करेंगे। राजीव कुमार राज्य पुलिस के डीजी बने रहेंगे। एडीजी और आईजीपी (एसटीएफ) विनीत गोयल को अतिरिक्त प्रभार के साथ एडीजी और आईजीपी (प्रशासन) बनाया गया है। एडीजी और आईजीपी (नीति) दमयंती सेन को एडीजी और आईजीपी (एपी) का प्रभार दिया गया है। जेल विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार को जन शिक्षा विस्तार एवं पुस्तकालय सेवाएं का सचिव बनाया गया है। इस विभाग का प्रभार संभाल रहे अपर मुख्य सचिव हृदेश मोहन को जेल विभाग का प्रभार दिया गया है। साथ ही डीजी सीजी (होमगार्ड) का पद संभाल रहे संजय सिंह को डीजी आईजी (साइबर सेल) बनाया गया है। एडीजी आईजी (प्रशासन) अजय मुकुंद रानाडे को एडीजी सीजी (होमगार्ड) बनाया गया है। एडीजी साइबर सेल हरिकिशोर कुसुमाकर को एडीजी आईजी (तटीय सुरक्षा) बनाया गया है। एडीजी (कानूनी) आनंद कुमार इस जिम्मेदारी के साथ-साथ नीति की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। आईजीपी-2 (सीआईडी) शंखशुभ चक्रवर्ती अतिरिक्त रूप से साइबर सेल की जिम्मेदारी संभालेंगे।

राज्य ने अडानी से अनुबंध लिया वापस

अधर में लटका ताजपुर बंदरगाह का भविष्य

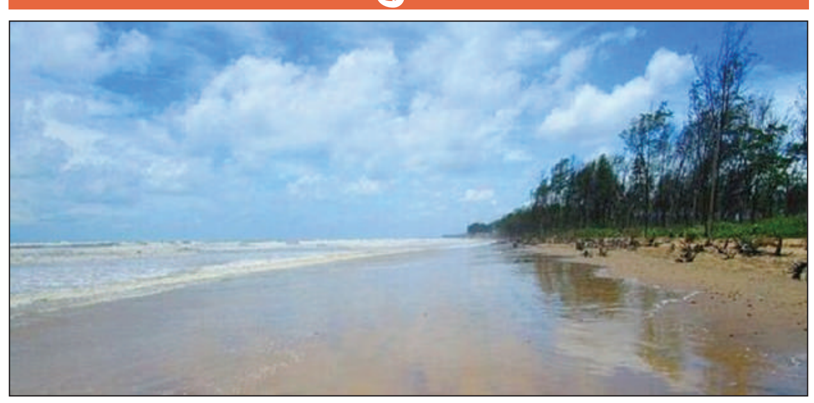

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने अडानी पोर्ट कंपनी से ताजपुर बंदरगाह के निर्माण की जिम्मेदारी वापस ले ली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विगत सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इस फैसले की घोषणा की। बताया गया है कि टेंडर मिलने के बावजूद काम शुरू न होने की वजह से अनुबंध रद्द किया गया है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं। 2020 में राज्य सरकार ने पूर्व मिदनापुर के ताजपुर में गहरे समुद्र में बंदरगाह के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि फरवरी 2022 थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अक्टूबर 2022 में न्यू टाउन में एक सरकारी बैठक में बंदरगाह के निर्माण का ठेका अडानी समूह को सौंप दिया।

इसके बाद आरोप है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी अडानी समूह ने ताजपुर बंदरगाह के निर्माण में कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। इसके उलट हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में धन शोधन का आरोप है। विपक्ष भी लगातार अडानी समूह की भाजपा से नजदीकी पर सवाल उठाता रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे असहज स्थिति 2024 में उपहार के बदले सवाल कांड में बनी थी।

उस कांड में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मैत्रा पर हीरानंदानी समूह से पैसे और उपहार लेकर अडानी समूह के खिलाफ सवाल उठाने का आरोप लगा था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक साथ अडानी समूह के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन सवाल यह उठता है कि उन्होंने ताजपुर बंदरगाह बनाने की जिम्मेदारी अडानी समूह को क्यों दी? तब यह स्पष्ट हो गया था कि अडानी ताजपुर बंदरगाह का ठेका खोने जा रहा है। आखिरकार ममता बनर्जी सरकार ने उस फैसले से आधारशिला रख दी। और इसके साथ ही बंगाल के औद्योगीकरण की एक और संभावना और अनिश्चितता में डूब गई।

हटाया जा सकता है 12% जीएसटी स्लैब

कुछ वस्तुओं की बढ़ सकती है कीमतें

निज संवाददाता: जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में 12% टैक्स स्लैब हटाने जा रही है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर के कुल चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) हैं। हालांकि, अगर 12% स्लैब हटा दिया जाता है, तो केवल तीन स्लैब ही बचेंगे। इस बीच, 12% स्लैब में दैनिक उपयोग के उत्पादों को 5% स्लैब में ले जाया जा सकता है। और गैर-आवश्यक उत्पादों को 18% स्लैब में रखा जा सकता है। अधिकारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि 12% स्लैब अब अप्रासंगिक हो गया है। जीएसटी का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना है और राजस्व को प्रभावित नहीं करना है। इस संदर्भ में, एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह (12% स्लैब हटाना) सबसे यथार्थवादी दृष्टिकोण है, लेकिन अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में मछली के अंडे से बना गाढ़ा दूध, कैवियार, 20 लीटर की बोतलों में पैक किया गया पीने का पानी, वॉकी-टॉकी, टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, कॉन्टैक्ट लेंस, पनीर, खजूर और सूखे मेवे, फ्रोजन सब्जियां, सॉसेज, पास्ता, जैम और जेली, फलों के रस से बने पेय, भुजिया सहित नमकीन, करी पेस्ट, मेयोनेज़, टूथ पाउडर, दूध पिलाने की बोतलें, कालीन, छाते, टोपी, साइकिल, कुछ घरेलू सामान, बेंत या लकड़ी से बने फर्नीचर, पेंसिल और क्रेयॉन, जूट या कपास से बने हैंडबैग और शॉपिंग बैग, 1,000 रुपये से कम कीमत के जूते, डायग्नोस्टिक किट और संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक शामिल हैं।विभिन्न रिपोर्टों में दावा किया गया है कि डिटर्जेंट, प्लास्टिक उत्पाद 12 से 18 प्रतिशत स्लैब में जा सकते हैं। यानी इन सभी उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। और मसाले और केरोसिन जैसे उत्पाद 5 प्रतिशत स्लैब के अंतर्गत आ सकते हैं। यानी जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण इन सभी उत्पादों की कीमतों में कमी आ सकती है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जून-जुलाई 2025 में होने की उम्मीद है। इसमें केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद रहेंगे। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक दिसंबर 2024 में हुई थी। इस लिहाज से यह पहली बार है कि इस साल जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। गौरतलब है कि जीएसटी को सरल बनाने के लिए सितंबर 2021 में मंत्रियों का समूह बनाया गया था।

12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में मछली के अंडे से बना गाढ़ा दूध, कैवियार, 20 लीटर की बोतलों में पैक किया गया पीने का पानी, वॉकी-टॉकी, टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, कॉन्टैक्ट लेंस, पनीर, खजूर और सूखे मेवे, फ्रोजन सब्जियां, सॉसेज, पास्ता, जैम और जेली, फलों के रस से बने पेय, भुजिया सहित नमकीन, करी पेस्ट, मेयोनेज़, टूथ पाउडर, दूध पिलाने की बोतलें, कालीन, छाते, टोपी और संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक शामिल हैं।

हार्वर्ड में ट्रंप के फैसले से भारत-पाकिस्तान के छात्र परेशान

♦ट्रंप ने किया अंतरराष्ट्रीय छात्र-छात्राओं को दाखिला देने का अधिकार रद्द
♦हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका

निज संवाददाता : श्रेया मिश्रा रेड्डी बताती हैं कि हार्वर्ड कई भारतीयों की पहली पसंद है। उन्होंने बताया कि हार्वर्ड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, जिसमें हर भारतीय स्टूडेंट दाखिला लेना चाहता है। श्रेया रेड्डी की ग्रेजुएशन लगभग पूरी होने वाली थी लेकिन अब उन्हें और उनके परिवार को बुरी ख़बर सुनने को मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय छात्र-छात्राओं को दाख़िला देने का अधिकार रद्द कर दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर किया है। बॉस्टन में दायर मुक़दमे में यूनिवर्सिटी ने प्रशासन की कार्रवाई को क़ानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया। ट्रंप प्रशासन के अनुसार, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क़ानून का पालन करने में नाकाम रही है।

श्रेया रेड्डी हार्वर्ड में लगभग 6,800 अंतरराष्ट्रीय छात्र-छात्राओं में से एक हैं। हार्वर्ड में 27 फ़ीसदी स्टूडेंट विदेश से आए हैं। ये विदेशी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की कमाई का एक अहम स्रोत हैं। इस संख्या में एक तिहाई छात्र चीन से हैं। श्रेया रेड्डी जैसे 700 से अधिक छात्र-छात्राएं भारतीय हैं। ये सभी स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हार्वर्ड ने अमेरिकी सरकार के इस क़दम को गैरकानूनी बताया है। ट्रंप प्रशासन के इस फ़ैसले को अब क़ानूनी चुनौती का सामना करना है। लेकिन इस बीच छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। इनमें चाहे गर्मियों में दाख़िला लेने के लिए इंतज़ार करने वाले हों या इस वक़्त कॉलेज में पढ़ाई करने वाले। जो इस वक़्त पढ़ रहे हैं उनकी नौकरियां वीज़ा मिलने पर टिकी हुई हैं। हार्वर्ड में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को अमेरिका में रहने और अपना वीज़ा बरकरार रखने के लिए दूसरे अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ेगा। श्रेया रेड्डी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हार्वर्ड हमारा साथ देगा और कोई समाधान निकाला जा सकेगा। विश्वविद्यालय ने कहा है कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विद्वानों की मेजबानी करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये लोग 140 से अधिक देशों से आते हैं। ये सभी अमेरिका और यूनिवर्सिटी को अहम योगदान देते हैं।

हार्वर्ड के खिलाफ उठाए गए इस क़दम का अमेरिका में रहने वाले लगभग दस लाख अंतरराष्ट्रीय छात्र-छात्राओं पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका के जिन शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर फ़लस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ ट्रंप प्रशासन ने कड़ा रुख़ अपनाया है। ऐसे दर्जनों संस्थानों को जांच का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सरकार इन संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया में सुधार करने और उनके संचालन के तरीके को नया स्वरूप देने की कोशिश कर रही है। व्हाइट हाउस ने पहली बार अप्रैल में हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने की धमकी दी थी। उस समय हार्वर्ड ने अपनी नियुक्ति, दाख़िले और शिक्षण पद्धतियों में बदलाव करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार ने संघीय अनुदान में से लगभग तीन बिलियन डॉलर की राशि पर रोक लगा दी थी। हार्वर्ड ने अदालत में इस रोक को चुनौती दी है। अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार विभाग, होमलैंड सिक्युरिटी की मंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि हार्वर्ड में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाख़िले पर रोक यहूदी विरोध और हिंसा को बढ़ावा देने की वजह से लगाई जा रही है।

पाकिस्तान से हार्वर्ड पढ़ने आए अब्दुल्लाह शाहिद सियाल कहते हैं कि हार्वर्ड में दाख़िला उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। ग्रेजुएशन के दूसरे साल में पढ़ रहीं चीनी छात्रा कैट झी ट्रंप प्रशासन के फ़ैसले से स्तब्ध हैं। कैट झी ने बताया कि मैं प्रतिबंध लगाने वाली धमकी को लगभग भूल ही गई थी और फिर गुरुवार को वाकई में इसकी घोषणा हो गई। लेकिन कैट ने कहा कि वो पहले ही किसी भी हालात से निपटने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने पिछले कुछ सप्ताह अमेरिका में रहने के बारे में पेशेवर सलाह लेने में बिताए हैं। उन्हें इस बारे में जो भी सलाह मिली है वो काफ़ी महंगी और जटिल है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन छात्र-छात्राओं को रखना चाहती है तो उसे कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इनमें बीते पांच वर्षों में बाहर से आए सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स साझा करना शामिल है। होमलैंड सिक्युरिटी की मंत्री नोएम ने हार्वर्ड से कैंपस में गैर-आप्रवासी छात्र-छात्राओं की अवैध और ख़तरनाक या हिंसक गतिविधियों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वीडियो या ऑडियो सौंपने की भी मांग की है।

ट्रंप प्रशासन ने चीन को भी निशाना बनाया

नोएम ने अपने बयान में हार्वर्ड पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय करने का आरोप लगाया। चीन ने अमेरिका पर शिक्षा के राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। चीन ने कहा कि इस क़दम से अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुक़सान होगा। चीन ने अमेरिका से इस प्रतिबंध को जल्द से जल्द हटाने की भी मांग की है। पाकिस्तान के 20 वर्षीय अब्दुल्ला शाहिद सियाल हार्वर्ड में पढ़ते हैं और वे एक मुखर छात्र कार्यकर्ता हैं। सियाल ने बताया कि हम ये सब झेलने के लिए यहाँ नहीं आए थे। साल 2023 में पाकिस्तान से दो ही छात्र हार्वर्ड आए थे। सियाल उन्हीं में से एक हैं। वे गणित और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं। अपने परिवार से विदेश में पढ़ने वाले वह पहले व्यक्ति हैं। सियाल कहते हैं कि हार्वर्ड में दाख़िला मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ा क्षण था। सियाल मौजूदा स्थिति को हास्यास्पद और अमानवीय बताते हैं। श्रेया रेड्डी और सियाल दोनों ने कहा कि विदेशी स्टूडेंट अमेरिकी कॉलेजों में इसलिए आते हैं क्योंकि यहां उनका बढ़िया स्वागत होता है और अमेरिका में उन्हें बहुत सारे अवसर मिलते हैं।

सरकार चलाने में 'विफल' डॉ. यूनुस ने कुर्सी बचाने के लिए रचा इस्तीफ़े का 'ड्रामा'

अमीनुल इस्लाम

मुख्य सलाहकार और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉ. मुहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चलाने में 'पूरी तरह विफल' रहे हैं। राष्ट्रीय सहमति की बात करने के बावजूद वे राजनीतिक दलों को न्यूनतम सहमति का रास्ता दिखाने में विफल रहे हैं। अंतरिम सरकार के शासन से सेना भी खुश नहीं है। चुनावों में देरी से अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी नाराज़ है। उनकी विफलताएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। कई लोगों का मानना है कि वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए 'इस्तीफ़े का ड्रामा' कर रहे हैं। अवामी लीग की नेता शेख हसीना ने अपने समर्थकों से धैर्य रखने को कहा है। स्थिति जल्द ही बदल जाएगी। एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया ने अपने समर्थकों को देश में लोकतंत्र वापस लाने का प्रयास करने का निर्देश दिया है।डॉ. यूनुस के तीन फ़ैसलों के कारण उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले, वे म्यांमार के विद्रोहियों के कब्ज़े वाले रखाइन राज्य के लिए 'मानवीय गलियारा' प्रदान करना चाहते हैं। बांग्लादेश के आम लोग इसे स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। इस संबंध में सेना प्रमुख जेबरेल वकार-उज-जमान ने कहा-यह निर्णय निर्वाचित सरकार से आना चाहिए और इसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करके लिया जाना चाहिए। दूसरे, विपक्ष ने चटगांव बंदरगाह के सबसे अधिक परिचालन और लाभप्रद न्यू मूरिंग टर्मिनल को विदेशी कंपनियों को पट्टे पर देना शुरू कर दिया है। कथित तौर पर डॉ. यूनुस की अंतरिम सरकार बड़ी रकम के बदले में देश के हितों को विदेशियों को बेच रही है। तीसरे, बीएनपी नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि बीएनपी नेता इशराक हुसैन को ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन का मेयर बनने से रोकने वाले अदालती आदेश से सरकार का फासीवादी चरित्र उजागर होता है। बीएनपी राष्ट्रीय स्थायी समिति के सदस्य गायेश्वर चंद्र रॉय ने डॉ. यूनुस पर हमला करते हुए कहा-आपकी चाल सभी समझ गए हैं, केवल आप नहीं समझ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अवमानना के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ यहां से जाएं। उन्हें लोगों के अधिकार वापस दें। बीएनपी की ओर से दो सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इस्तीफे की मांग तथा एनसीपी की ओर से तीन सलाहकारों के इस्तीफे की मांग ने राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। डॉ. यूनुस के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। जबरन वसूली बढ़ गई है। इसलिए, ढाका चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीसीसीआई) ने कहा है-असुरक्षित वातावरण, जबरन वसूली, धोखाधड़ी वाली ऑनलाइन गतिविधियों, उत्पाद परिवहन में जोखिम और प्रशासनिक कमजोरियों के कारण छोटे और मध्यम उद्यमियों का व्यापार और निवेश में विश्वास कम हो रहा है। दरअसल, डॉ. यूनुस पर बहुत दबाव है। इसीलिए वे कथित तौर पर इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं। उस रणनीति के तहत वे खुद इस्तीफा देने की बजाय नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के संयोजक नाहिद इस्लाम के जरिए इस्तीफे की बात कहकर लोगों के मन की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि डॉ. यूनुस के बिना बांग्लादेश में कोई गति नहीं है। इसीलिए उनके जरिए नाहिद को बताया गया है कि वे (डॉ. यूनुस) इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। नाहिद ने आगे कहा कि डॉ. यूनुस ने उनसे कहा-मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। इसलिए, राजनीतिक दल, अगर आप सभी एक जगह नहीं पहुंच सकते हैं। चुनावों को लेकर डॉ. यूनुस पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सलाहकार सत्ता खोने के डर से अभी चुनाव नहीं चाहते हैं। जमात भी इस अस्थिर सरकार को सत्ता में बनाए रखना चाहती है और अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। कट्टरपंथी भी चाहते हैं कि उनकी कठपुतली सरकार बची रहे। दरअसल, डॉ. यूनुस के कई सलाहकार अभी चुनाव नहीं चाहते हैं। ऐसे में बीएनपी नेता गायेश्वर चंद्र रॉय ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सड़ने लगी है। चुनावों के बारे में बीएनपी नेता सलाहुद्दीन अहमद ने डॉ. यूनुस से कहा-''आप न्याय और सुधार के नाम पर बांग्लादेश के लोकतंत्र को अनंत काल तक कांटा नहीं मारते रहेंगे।'' बीएनपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इस साल दिसंबर तक राष्ट्रीय चुनाव नहीं हुए तो अंतरिम सरकार के लिए समर्थन बनाए रखना ''मुश्किल'' होगा। डॉ. यूनुस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल में आम लोगों की मौलिक स्वतंत्रता को कमज़ोर किया जा रहा है। न्यूयॉर्क स्थित इस अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने 12 मई को जारी अवामी लीग पर ''अस्थायी'' प्रतिबंध की कड़ी आलोचना की है। एशिया के लिए एचआरडब्ल्यू की उप निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा-''शेख हसीना की सरकार राजनीतिक विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए कानूनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब उनकी पार्टी अवामी लीग अपने समर्थकों के खिलाफ़ उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, जो उन्हीं मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करेंगे।'' संक्षेप में कहें तो अंतरिम सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि डॉ. यूनुस इस्तीफ़ा देकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

आखिरी नागरिक तक न्याय पहुंचाना ही न्यायपालिका का मौलिक कर्तव्य: सीजेआई गवई

निज संवाददाता भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने कहा कि भारतीय संविधान लागू होने की 75 साल की यात्रा में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने देश की एकजुटता के लिए संविधान को श्रेय दिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि देश पर जब भी संकट आया है उसने मजबूती और एकजुटता के साथ उसका सामना किया और इसका श्रेय संविधान को दिया जाना चाहिए।सीजेआई बीआर गवई ने यह बात इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 680 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर भवन और मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीजेआई गवई ने कहा-''न्यायपालिका का मौलिक कर्तव्य देश के उस आखिरी नागरिक तक पहुंचना है जिसे न्याय की जरूरत है और विधायिका और कार्यपालिका का भी यही कर्तव्य है।''मुख्य न्यायाधीश ने कहा-''मेघवाल जी (केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री) ने कहा कि (सीएम) योगी जी इस देश के सबसे शक्तिशाली और मेहनती सीएम हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद शक्तिशाली लोगों की भूमि है। उन्होंने कहा-''जब भी संकट आया, भारत एकजुट और मजबूत रहा। इसका श्रेय संविधान को दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान लागू होने की 75 साल की यात्रा में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने में बड़ा योगदान दिया है।1973 से पहले उच्चतम न्यायालय का विचार था नीति निर्देशक सिद्धांत (डायरेक्टिव प्रिंसिपल) और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति बनेगी तो मौलिक अधिकार ऊपर होगा। लेकिन, 1973 में 13 न्यायाधीशों का निर्णय आया कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है और इसके लिए वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके पास संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने का अधिकार नहीं है।''कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा-''अधिवक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार सतत प्रयासरात है। इस दिशा में सात जनपदों में परिसर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए 1,700 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।''मुख्यमंत्री ने कहा-''सरकार ने अधिवक्ता निधि की राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है और इसके पात्र अधिवक्ताओं की आयु सीमा भी 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। इसके लिए भी 500 करोड़ रुपये की निधि दी गई है।'' प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में उच्च न्यायालय की भूमिका रेखांकित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा-प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन इतना सफल इसलिए हो सका क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसी परियोजना पर रोक नहीं लगाई।''उद्घाटन समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय भी मौजूद थे।बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निर्मित मल्टीलेवल पार्किंग में 3,835 वाहनों की पार्किंग क्षमता है और साथ ही 2,366 चैंबर बनाए गए हैं। इस 14 मंजिला भवन के भूमिगत तल और भूतल सहित पांच मंजिल पार्किंग के लिए आरक्षित हैं। वहीं, छह मंजिल अधिवक्ताओं के चैंबर के लिए समर्पित हैं। इस भवन में 26 लिफ्ट, 28 एस्कलेटर और चार ट्रैवलेटर्स बनाए गए हैं।

Page-9_Layout 1 6/7/2025 2:05 PM Page 1

स्वास्थ्य

पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण सबकी नैतिक जिम्मेदारी

नूपुर मित्रा

सदियों से सभ्यता के उदय से ही लोगों ने हमेशा एक सुंदर वातावरण की चाहत की है जिसे जीवित रहने और उसे जीवित रखने का एक अचूक प्रयास कहा जा सकता है। प्राकृतिक संपदा से सजे सौम्य वातावरण में प्रकृति, मनुष्य और पशु एक दूसरे को एक समान प्राणी मानते थे, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ-साथ हम धीरे-धीरे यांत्रिक सभ्यता से खतरे में पड़े वातावरण से आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान आधारित सभ्यता के अभिशाप से पीड़ित आज की पीढ़ी और भी भयानक दिनों का इंतजार कर रही है। शहरी विकास के सहारे पर्यावरण प्रदूषण की राह पर चल पड़ा है। मनुष्य और पशुओं को एक सीमित प्रदूषित वातावरण में रहना पड़ रहा है, जिसने दुनिया के अनगिनत लोगों को खतरनाक स्थिति में डाल दिया है। मनुष्य प्रकृति को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए सक्रिय हो गया है। प्रकृति वास्तव में मनुष्य के लिए एक अमूर्त विचार मात्र है। सभ्यता की प्रगति का अर्थ है विभिन्न विकास। जो था, जो है, उससे आगे सुधार की ओर बढ़ना ही मनुष्य का धर्म है। स्वभाव से मनुष्य विकास चाहता है। विकास और प्रयासों के माध्यम से उसकी आदिम अवस्था समाप्त हो गई है। पर्यावरण का विकास से अटूट संबंध है। जिस प्रकार विकास के परिणामस्वरूप पर्यावरण में सुधार होता है, उसी प्रकार कई मामलों में विकास पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है। विज्ञान और तकनीक में दिन-प्रतिदिन अविश्वसनीय प्रगति हो रही है, लेकिन यह सफलता कई मामलों में फिर से संकट को गहरा कर रही है। अंत में पर्यावरण को ही नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन विकास की गति को पूरी तरह रोककर पर्यावरण की रक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। या तो विकास या पर्यावरण? आज हमें यह सोचना होगा कि विकास और पर्यावरण के बीच सामंजस्य कैसे और किस तरह से कायम रह पाएगा। विकास के साथ-साथ हमें पर्यावरण की रक्षा पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश, दुनिया और लोगों को बचाने के लिए पर्यावरण की रक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। संतुलित और सुंदर पर्यावरण ही हमारी सुंदर दुनिया की रक्षा कर सकता है। पर्यावरण बचेगा तो जैव विविधता बचेगी, लोग बचेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। इसलिए हम सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए और अधिक सक्रिय और सक्रिय होना होगा। पर्यावरण जीवन का वाहक है, प्राणशक्ति का वाहक है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण करना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि यह पर्यावरण संकट सम्पूर्ण मानव जाति की जिम्मेदारी है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित विश्व बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करें। हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए कि पर्यावरण के अनुकूल बनना इच्छा की बात नहीं, बल्कि कर्तव्य की बात है। बच्चों को मोबाइल फोन छोड़कर पर्यावरण से प्रेम करना सिखाएं, तथा खेलते समय पर्यावरण के प्रति जागरूक बनें। जैव विविधता के प्रति करुणा पैदा करें। पर्यावरण और प्रकृति को भविष्य के संपर्क में रहने दें, छोटे-छोटे कदमों से पर्यावरण के अनुकूल वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करें।

> **मनुष्य प्रकृति को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए हो गया है सक्रिय**

बदलती जीवनशैली में बच्चों का पोषण

सही खानपान से ही होगा मानसिक और शारीरिक विकास

रश्मि बियानी
(न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाइल कोच)

आज की बदलती जीवनशैली बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। शहरीकरण, तकनीकी विकास और व्यस्त दिनचर्या ने बच्चों की दिनचर्या बदली है। अब बच्चे अधिकतर समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं। पोषण का सीधा संबंध बच्चों की सेहत से होता है। उनका मानसिक, शारीरिक विकास सही खानपान से ही संभव है। यदि शुरू से ध्यान ना दिया जाए तो समस्याएं बढ़ती हैं। यही कारण है कि सही पोषण की जरूरत बढ़ गई है। बच्चों के खानपान में सबसे बड़ी चुनौती आदतें हैं। बच्चों को फास्ट फूड, तले-भुने आइटम ज्यादा पसंद आते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थ आकर्षक होते हैं। मगर इनमें पोषक तत्वों की भारी कमी पाई जाती है। ये चीजें सिर्फ स्वाद देती हैं, पोषण नहीं देतीं। लगातार ऐसे खाने से बच्चों में बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। मोटापा, सुस्ती, पाचन समस्याएं आम तौर पर देखी जाती हैं। इससे इम्यूनिटी कमजोर होती है और शरीर सुस्त बनता है। बच्चे एक्टिव नहीं रहते और जल्दी थक जाते हैं। इस स्थिति में सही खानपान देना अत्यंत आवश्यक बनता है।

सही पोषण में क्या शामिल होना चाहिए?

सही पोषण का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता। इसका उद्देश्य शरीर को ज़रूरी तत्व समय पर देना है। प्रोटीन, विटामिन, आयरन और फाइबर आवश्यक माने जाते हैं। इनकी पूर्ति के लिए संतुलित भोजन बेहद जरूरी होता है। बच्चों के आहार में दूध, फल, सब्ज़ियां अनिवार्य होने चाहिए। साथ ही, अंडा, दालें और सूखे मेवे भी जरूरी हैं। यह तत्व शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करते हैं। बच्चे तेज़ी से सीखते हैं जब पोषण पूरा मिलता है। उनके सोचने, समझने की क्षमता भी बेहतर बनती है। आजकल बच्चों का भोजन समय पर नहीं होता है। देर रात तक जागने और सुबह देर से उठने की आदत है। इससे नाश्ता छूट जाता है। दिनभर बच्चों को एनर्जी के लिए पोषण मिलना चाहिए। समय पर खाना न खाने से गैस और थकावट होती है। इसलिए भोजन का समय निर्धारित होना बहुत जरूरी है। बच्चों को दिन में तीन बार संतुलित आहार देना चाहिए। उनके खानपान में नियमितता से आदतें भी सुधरती हैं। इससे उनकी दिनचर्या भी संतुलित रहती है।

माता-पिता और स्कूल की भूमिका

माता-पिता और स्कूल की भूमिका इसमें अहम मानी जाती है। माता-पिता को खुद सही खानपान की आदत अपनानी चाहिए। बच्चे वही करते हैं जो घर में देखकर सीखते हैं। यदि अभिभावक पौष्टिक आहार खाएं, तो बच्चे भी खाएंगे। स्कूल में भी बच्चों के लिए हेल्दी टिफिन का नियम होना चाहिए।

कैरियर

स्कूल शिक्षा विभाग में बदलेंगे भर्ती के नियम

21 से 40 साल वाले कर सकेंगे आवेदन

नयी दिल्ली : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवा हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी परीक्षा देते हैं। हालांकि, पिछले कुछ सालों में एसएससी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण कई विवाद सामने आए हैं। साल 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएसएससी) का भर्ती घोटाला काफी चर्चित है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। इस फैसले ने कई लोगों की नौकरियां छीन लीं, लेकिन नए नियमों के तहत प्रभावित कर्मचारियों को फिर से मौका देने की व्यवस्था की गई है। इस वजह से एसएससी शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव भी किया गया है। उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है और प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश भी की जा रही है। 2016 में डब्ल्यूबीएसएससी ने कक्षा 9-12 के लिए सहायक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों (ग्रुप सी और डी) की भर्ती के लिए स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट (एसएलएसटी) आयोजित किया था। 23 लाख उम्मीदवारों ने 24,640 रिक्तियों के लिए आवेदन किया, लेकिन 25,753 नियुक्तियां की गईं। इससे पता चलता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में हेराफेरी की गई थी। सीबीआई की जांच में सामने आया कि ओएमआर शीट्स में हेरफेर, रैंक में बदलाव और पैनल की वैधता समाप्त होने के बाद नियुक्तियां की गईं।

एसएससी शिक्षक भर्ती के नए नियम

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तीन महीने के अंदर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। नए नियम इस प्रकार हैं-

दोबारा परीक्षा देने का अवसर: जिन कर्मचारियों की नौकरियां रद्द हुईं, वे नई भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बस शर्त यही है कि वे 'दागी' न पाए गए हों। कोर्ट ने 6,000 से अधिक उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया था, जो ओएमआर हेरफेर या रैंक में बदलाव में शामिल थे। ये उम्मीदवार दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते हैं। **पारदर्शिता :** नई भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूबीएसएससी को निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों की सूची और अंक सार्वजनिक किए जाएं। **आयु छूट :** प्रभावित कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। इससे वह आसानी से नई परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस बार 21 से 40 वर्ष के लोग आ-वेदन कर सकेंगे।

सेना में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका

नयी दिल्ली : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने देशभर के युवाओं के लिए एनडीए/एनए-2 और सीडीएस-2 2025 परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी कर दी है जो उम्मीदवार भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in या upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एनडीए और सीडीएस के लिए चयनित उम्मीदवारों को इंडियन मिलिट्री अकादमी, देहरादून, एयर फोर्स अकादमी, हैदराबाद, इंडियन नेवल अकादमी, एझिमाला, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई और नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए-2 कोर्स) में प्रवेश मिलेगा।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन की अंतिम तिथि : **17 जून 2025 (शाम 6 बजे तक)**

परीक्षा तिथि : 14 सितंबर 2025

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि : अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में संभावित। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 453 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें इंडियन मिलिट्री अकादमी (आईएमए), एयरफोर्स अकादमी (एएफए), इंडियन नेवल अकादमी (आईएनए), ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) और नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे।

मुख्य अकादमियां :

इंडियन मिलिट्री अकादमी (आईएमए), देहरादून। इंडियन नेवल अकादमी (आईएनए), एझिमाला। एयरफोर्स अकादमी (एएफए), हैदराबाद। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए), चेन्नई। नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए), पुणे

आवेदन शुल्क :

जनरल और ओबीसी वर्ग: 200 रुपए

एससी/एसटी वर्ग और सभी महिला उम्मीदवार: शुल्क मुक्त (कोई फीस नहीं)

उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या बैंक चालान के जरिए शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

योग्यता मानदंड :

एनडीए/एनए-2 परीक्षा के लिए :

आयु सीमा : उम्मीदवार की उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता :

सेना विंग के लिए: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास।

वायुसेना और नौसेना के लिए: 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स अनिवार्य।

सीडीएस-2 परीक्षा के लिए :

आयु सीमा: 19 से 25 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता:

आईएमए और ओटीए के लिए : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन.

आईएनए के लिए : इंजीनियरिंग में डिग्री।

एएफए के लिए: फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12वीं और ग्रेजुएशन में फिजिक्स/मैथ्स/इंजीनियरिंग डिग्री.

परीक्षा पैटर्न

दोनों परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप (बहुविकल्पीय) होंगी।

एनडीए/एनए परीक्षा : गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण (जीएटी)

सीडीएस परीक्षा : इंग्लिश, जनरल नॉलेज और इलेमेंट्री मैथ्स (केवल आईएमए, आईएए, एएफए के लिए)

सभी प्रश्न पत्र ऑफलाइन मोड (पेन-पेपर आधारित) में आयोजित किए जाएंगे।

कैसे करें आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं।

"Online Application for Various Examinations of UPSC" लिंक पर क्लिक करें.

NDA/NA II या CDS II 2025 के लिंक पर क्लिक करें। सभी जरूरी जानकारी भरें, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट आउट ले लें।

मालदा कॉलेज ने पश्चिम बंगाल इतिहास संसद के साथ मिलाया हाथ

जिला स्तर पर धर्मनिरपेक्ष इतिहास अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

निज संवाददाता : जिला स्तर पर विज्ञान आधारित और धर्मनिरपेक्ष इतिहास अभ्यास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल इतिहास संसद और मालदा कॉलेज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता ज्ञापन बीते 31 मई को पश्चिम बंगाल इतिहास संसद के कार्यालय में हस्ताक्षरित किया गया। पश्चिम बंगाल इतिहास संसद के सचिव विमान समद्दार ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों संस्थाएं मालदा और उत्तर बंगाल के अन्य जिलों में क्षेत्रीय स्तर पर इतिहास अभ्यास को बढ़ावा देने, जिले के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में लोकप्रिय बनाने और संयुक्त कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करने की पहल करेंगी। पश्चिम बंगाल इतिहास संसद के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष आशीष कुमार दास ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन के अनुसार आगामी 2-3 अगस्त को मालदा कॉलेज में बंगाल के चल रहे सामाजिक और आर्थिक-राजनीतिक परिवर्तन शीर्षक से एक अंतरराष्ट्रीय चर्चा श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश-विदेश के कई प्रसिद्ध इतिहासकार मौजूद रहेंगे।

इस चर्चा बैठक में पढ़े गए लेखों को बाद में एक पुस्तक में प्रकाशित किया जाएगा। यह जानकारी इतिहास संसद द्वारा दी गई है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल इतिहास संसद का 40वां वार्षिक अधिवेशन इस वर्ष की शुरुआत में (17-19 जनवरी) जलपाईगुड़ी के ऐतिहासिक प्रसन्न देव महिला महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। इस वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रसिद्ध प्रोफेसर आनंद गोपाल घोष ने किया था। उद्घाटन मुख्य भाषण प्रोफेसर अरविंद सामंत ने दिया, जिन्होंने अपने मुख्य भाषण में आधुनिक समय में ऐतिहासिक शोध की प्रासंगिकता को बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। सत्र के विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता प्रोफेसर प्रजीत पालित, डॉ. स्वाति विश्वास, प्रोफेसर अचिंत्य दत्ता और डॉ. सोमा मारिक ने की। इस सत्र में अब्दुल वहाब महमूद स्मृति चर्चा श्रृंखला आयोजित की गई। इस वर्ष के व्याख्यान प्रोफेसर हितेंद्र पटेल, मधुपर्णा रॉयचौधरी और राजकुमार चक्रवर्ती ने दिए। इस सत्र का सबसे उल्लेखनीय पहलू लगभग चार सौ शोधकर्ताओं, शिक्षकों और युवा इतिहासकारों की सहज भागीदारी थी। इस वर्ष कार्यकारिणी समिति के लिए चुनाव का वर्ष था। कुल पंद्रह उम्मीदवार - निवर्तमान सचिव प्रोफेसर आशीष कुमार दास, प्रोफेसर अरुण बनर्जी, प्रोफेसर अरविंद सामंत, प्रोफेसर सुसनात दास, प्रोफेसर विमान समद्दार, प्रोफेसर अपर्णा बनर्जी, प्रोफेसर सुभ्रांशु रॉय, और कुल पंद्रह सदस्य सदस्यों के वोट से कार्यकारी समिति के लिए चुने गए। कार्यकारी समिति की पहली बैठक में संसद के नए सचिव चुने जाने के बाद विमान समद्दार ने कहा कि पश्चिम बंगाल इतिहास संसद राज्य के विभिन्न हिस्सों में धर्मनिरपेक्ष वस्तुनिष्ठ इतिहास अभ्यास की प्रवृत्ति को फैलाने का प्रयास करेगी और आने वाले दिनों में स्कूली शिक्षकों के साथ कार्यशालाओं और जूनियर रिसर्च स्कॉलर सेमिनार आयोजित करने की पहल करेगी।

भारत की अनुमानित विकास दर 6.20 फीसदी होने की संभावना

बढ़ी है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खपत

एस सान्याल

देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खपत बढ़ी है। मई महीने के आंकड़े तो यही कहते हैं। पिछले महीने के मुकाबले इस साल मई में इन सभी ईंधनों की खपत लगभग सभी मामलों में बढ़ी है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी किसी देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की खपत को काफी महत्व दिया जाता है। वर्तमान में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी माना जाता है। उदाहरण के लिए इन सभी ईंधनों की खपत में वृद्धि अंततः देश की परिवहन व्यवस्था में सुधार, पर्यटन के विकास, कृषि के विस्तार, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि की ओर इशारा करती है, यानी एक शब्द में कहें तो यह समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विकास की ओर इशारा करती है। आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2024 के मुकाबले मई 2025 में देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की मांग लगभग सभी मामलों में बढ़ी है। मई 2024 में देश में पेट्रोल की कुल खपत 3.46 मिलियन टन थी, जो मई 2025 में बढ़कर 3.78 मिलियन टन हो गई। यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 8.77 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। डीजल के मामले में पिछले साल मई में 8.41 मिलियन टन का इस्तेमाल हुआ था, जो मई 2025 में बढ़कर करीब 8.57 मिलियन टन हो गया। यानी डीजल की खपत में 1.89 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। हालांकि कुछ का दावा है कि डीजल की खपत में बढ़ोतरी का मुख्य कारण मानसून का जल्दी आना है, जिसने इस बार मई में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए देश में डीजल की मांग कुछ हद तक बढ़ा दी है एलपीजी के मामले में मई 2024 में देश में 2.46 मिलियन टन का इस्तेमाल हुआ था, जो मई 2025 में बढ़कर करीब 2.79 मिलियन टन हो जाएगा। यानी 13.43 फीसदी की बढ़ोतरी।

आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश में एलपीजी का इस्तेमाल घरेलू और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ा है। एक निजी स्रोत के मुताबिक, सिर्फ एक साल में घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की संख्या में करीब 68 हजार का इजाफा हुआ है। एटीएफ या विमानन ईंधन के मामले में मई 2024 में देश में 0.74 मिलियन टन का इस्तेमाल हुआ था, जो मई 2025 में बढ़कर 0.77 मिलियन टन हो जाएगा। याद रखने वाली बात है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद मई 2025 में देश के 30 महत्वपूर्ण हवाई अड्डे और कई उड़ान सेवाएं कई दिनों के लिए बंद कर दी गई थीं और अगर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ती है, तो देश में मुद्रास्फीति की प्रबल संभावना है। उस स्थिति में, आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर उपभोक्ता खर्च की मात्रा कम हो जाएगी।

देश की घरेलू मांग पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन कम हो सकता है। देश की बैंकिंग प्रणाली प्रभावित हो सकती है। पूरी अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। इसलिए, इन मुद्दों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए, एक तरफ, पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि देश के विकास की विशेषता हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ, अगर आप सावधान नहीं हैं तो यह खतरनाक हो सकता है। इसलिए, सरकार का अतिरिक्त मांग पर नियंत्रण जरूर होगा। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपूर्ति ज्यादातर दूसरे देशों पर निर्भर है। इसलिए, आपूर्ति या मूल्य वृद्धि जैसे मुद्दों पर सरकार का सीधा नियंत्रण बहुत अधिक नहीं होगा। उस स्थिति में, बढ़ी हुई मांग अंततः देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति काफी स्पष्ट हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि 9.20 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर थी। हालांकि, 2024-25 में आर्थिक वृद्धि 6.50 फीसदी रही, जो कि बहुत बड़ी कमी है।

यह याद रखना चाहिए कि आईएमएफ के अनुसार, 2025 में दुनिया की आर्थिक वृद्धि 2.80 फीसदी अनुमानित है और 2026 में अनुमानित वृद्धि दर केवल 3 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की विकास दर को लेकर काफी आशावादी हैं। उनके अनुसार, भले ही भारत की अनुमानित विकास दर घट जाए, यह 6.20 फीसदी के आसपास होगी, जो निस्संदेह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सूची में शीर्ष पर ला खड़ा करेगी।

पिनाकी मिश्रा के साथ महुआ ने की नई जिंदगी की शुरुआत

- बर्लिन के एक महल में रचायी शादी
- महुआ ने लंबे समय तक अमेरिकी निवेश फर्म जेपी मॉर्गन एंड चेस के लिए काम किया

निज संवाददाता: पिछले कुछ सालों से दोस्ती चल रही है। उनके करीबी लोग भी जानते थे कि चार हाथ एक होंगे। बीते शुक्रवार को कृष्णानगर से तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने पुरी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से जर्मनी के बर्लिन महल की छत पर शादी की। 65 वर्षीय पिनाकी और 51 वर्षीय महुआ दोनों की यह दूसरी शादी है। खिलाड़ियों, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की विदेश में या देश के किसी प्राचीन महल-किले में डेस्टिनेशन वेडिंग कोई नई बात नहीं है। लेकिन दो घरेलू राजनेताओं की यह शादी देश में दुर्लभ है। हालांकि इसे उस मायने में डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं कहा जा सकता। जोड़े के करीबी लोगों का कहना है कि भीड़ से बचने के लिए बर्लिन को चुना गया। इससे पहले 2019 में तृणमूल के लिए बशीरहाट लोकसभा सीट जीतने के बाद नुसरत जहां तुर्की के बोडरम में निखिल जैन के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग करने गई थीं। जिसके कारण उन्हें सांसद के रूप में शपथ लेने में देरी हुई। नुसरत एक अभिनेत्री हैं। वह पूरी तरह से राजनीतिज्ञ नहीं थीं। महुआ शुरू से ही राजनीतिज्ञ थीं। पिनाकी भी वही हैं। वह पेशे से वकील हैं।महुआ ने लंबे समय तक अमेरिकी निवेश फर्म जेपी मॉर्गन एंड चेस के लिए काम किया। वह कंपनी की उपाध्यक्ष भी बनीं। उस दौरान महुआ का डेनमार्क के फाइनेंसर लार्स ब्रॉसन से रिश्ता था। दोनों ने शादी कर ली। बाद में यह रिश्ता खत्म हो गया। महुआ से तलाक के बाद लार्स ने दूसरी शादी कर ली। उनका एक बच्चा भी है। वहीं पिनाकी ने पहली शादी ओडिशा की संगीता मिश्रा से की थी। उनका एक बेटा और एक बेटी है। पिनाकी और संगीता का तलाक हुए कई साल हो चुके हैं।पहले महुआ सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राय की करीबी दोस्त थीं। हालांकि शुरुआत में दोनों के बीच मधुरता थी, लेकिन बाद में उनका रिश्ता कड़वाहट में बदल गया। पालतू जानवर रखने को लेकर जय-महुआ की लड़ाई पुलिस थाने तक पहुंच गई थी। लोकसभा में पिछले कार्यकाल के दौरान महुआ पर गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े उपहारों और एहसानों के बारे में संसद में सवाल उठाने का आरोप लगा था। जिसके आधार पर संसद की आचार समिति की सिफारिश पर महुआ को पिछले कुछ महीनों के लिए निष्कासित करना पड़ा था। उस आरोप को सामने लाने वालों में महुआ के पूर्व मित्र जय भी थे। उनके साथ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी थे। जय और पिनाकी के बीच दूरी के बाद महुआ की पिनाकी से नजदीकियां दोस्ती के अगले स्तर पर पहुंच गईं। दोनों पिछले साल यूरोप की यात्रा पर भी गए थे। संयोग से महुआ और पिनाकी दोनों ने ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। हालांकि महुआ बहुत कम समय के लिए कांग्रेस में रहीं, लेकिन पिनाकी पहली बार 1996 में कांग्रेस के टिकट पर पुरी से सांसद बने। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजू जनता दल में शामिल हो गए हालांकि बीजद के शीर्ष नेता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया था।

पड़ोसी 'दुष्टता' का अंत...

पेज-1 का शेष

उन्होंने कहा कि इसने पूरे देश का आत्म-सम्मान और मनोबल बढ़ाया।बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के बारे में उन्होंने कहा-हिंदुओं की चिंता तभी होगी जब वे खुद मजबूत होंगे। हिंदू समाज और भारत एक-दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए जब हिंदू समाज गौरवशाली बनेगा, तब भारत भी गौरवशाली बनेगा। ऐसा सशक्त हिंदू समाज ही उन लोगों को साथ लेकर चलने का आदर्श प्रस्तुत कर सकता है जो खुद को हिंदू नहीं मानते, क्योंकि कभी वे भी हिंदू थे।भागवत के अनुसार, यदि भारत का हिंदू समाज सशक्त होगा तो वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की स्थिति भी सुदृढ़ होगी। यह कार्य जारी है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह स्थिति बन रही है। इस बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को लेकर जो पीड़ा प्रकट की गई है, वह अभूतपूर्व है। अब स्थानीय हिंदू भी कहते हैं, हम भागेंगे नहीं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। भागवत ने कहा-अब हिंदू समाज की आंतरिक शक्ति बढ़ रही है। संगठन के विस्तार का प्रभाव स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा। तब तक हमें संघर्ष जारी रखना होगा।

बलूचिस्तान के स्वतंत्रता...

पेज 1 का शेष

हालांकि, केंद्र सरकार ने फिलहाल इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, अगर भारत इस समय सीधे तौर पर बलूचों का समर्थन करता है, तो पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत पर देश के विभाजन में मदद करने का आरोप लगा सकता है। पाकिस्तान 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के टूटने के बाद बांग्लादेश में हुए युद्ध का उदाहरण देकर भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा करना चाहेगा। इसलिए, उनका मानना है कि भारत सरकार इस समय बलूचिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता पर कड़ी नज़र रख रही है। सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या दिल्ली में बलूचिस्तान सांस्कृतिक केंद्र खोलने की अनुमति दी जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के विभिन्न देशों में सात टीमें भेजीं, जहां वर्तमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं। एक स्वतंत्र बलूच राज्य की भविष्य की मान्यता के लिए इन सुरक्षा परिषद देशों का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान की वर्तमान समग्र स्थिति को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलकों का मानना है कि बलूच को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ऐसा सोचने का क्या कारण है? सबसे पहले, एक स्वतंत्र बलूच राज्य के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 में से कम से कम 9 देशों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, पांच स्थायी सदस्य देशों के अलावा, पाकिस्तान सहित कुल दस देश हैं, जो अस्थायी सदस्य हैं। इस वर्ष 1 जनवरी को पाकिस्तान के मुनी अकरम को दो वर्ष के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नामित किया गया था। इसके अलावा अन्य अस्थायी सदस्य देश अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, कोरिया, सिएरा, स्लोवेनिया और सोमालिया हैं। नतीजतन, यदि प्रारंभिक चरण में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो अगले चरण में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देशों के दो तिहाई वोट मिलने पर ही बलूचिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए देश के रूप में मान्यता देने पर विचार किया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह कार्य इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान वर्तमान में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है।

Page-11_Layout 1 6/7/2025 2:10 PM Page 1

जब कुएं का पानी बन गया समस्या का कारण

बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर के राज्य में किसान रहता था। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए कुएं की तलाश में था। एक दिन जब वह खेत के आसपास घूम रहा था तो उसे अपने खेत के समीप एक कुआं नजर आया। कुआं दिखते ही किसान खुश हो गया। उसे लगा अब उसकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद किसान खुशी-खुशी अपने घर चला गया। अगले दिन किसान उस कुएं के पास पानी लेने के लिए पहुंच गया लेकिन जैसे ही उसने कुएं में बाल्टी डाली तो वहां एक आदमी आ गया और किसान से कहा कि यह उसका कुआं है। उसने किसान से कहा कि, तुम मेरे कुएं से पानी नहीं ले सकते हो। अगर तुम्हें कुएं से पानी चाहिए तो तुम्हें कुएं को खरीदना पड़ेगा। आदमी की बात सुनकर किसान पहले तो निराश हुआ। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं यह कुआं खरीद लूं तो पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और मुझे पानी के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। किसान ने कुआं खरीदने के लिए हां कर दी और इसके बाद दोनों के बीच एक रकम भी तय हो गई। लेकिन किसान के पास उतने पैसे नहीं थे। फिर भी किसान ने सोचा मैं एक दिन में किसी तरह इस रकम को जुटा लूंगा। इस तरह से किसान ने आदमी को अगले दिन तय रकम देने का वादा किया और घर चला गया। किसान ने किसी तरह से रकम जुगाड़ की और अगले दिन बिना देर किए कुआं खरीदने चला गया। किसान उस आदमी के घर पहुंचा और उसे तय रकम दे दी. इसके बाद किसान बहुत खुश हो गया और उसने कुएं से पानी निकालने में तनिक भी देरी नहीं की और तुरंत बाल्टी उठा ली. जैसे ही किसान कुएं में बाल्टी डालने जा रहा था, तो आदमी ने फिर उसे रोक दिया और कहने लगा तुम इस कुएं से पानी नहीं

अकबर-बीरबल की कहानी

निकाल सकते। क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ अपना कुआं बेचा है कुएं का पानी नहीं। आदमी की बात सुनकर किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए बादशाह अकबर के दरबार में गुहार लगाई। बादशाह अकबर ने किसान की पूरी बात सुनी और फिर कुआं बेचने वाले आदमी को भी दरबार में बुलाया। बादशाह का फरमान सुनते ही आदमी तुरंत दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे पूछा, जब तुमने किसान को अपना कुआं तय रकम पर बेच दिया तो इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे। आदमी ने कहा, महाराज! मैंने तो इसे सिर्फ अपना कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। आदमी की बात सुनकर अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम बात को पते की कह रहे हो कि कुआं बेचा है पानी नहीं। जब अकबर काफी देर तक सोच-विचार करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। क्योंकि अकबर जानते थे कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान है। इसलिए अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल दरबार में आए और दोनों की बात विस्तार से सुनी। बीरबल को तुरंत मामला समझ आ गया और बीरबल ने उस आदमी से कहा ठीक है अगर तुमने कुआं बेचा पानी नहीं तो फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? अगर कुआं तुम्हारा नहीं है तो फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल की बात सुनकर वह समझ आ गया कि बीरबल के आगे उसकी चालाकी नहीं चलने वाली है। उस आदमी ने तुरंत बादशाह से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और किसान को कुएं के साथ पानी का भी अधिकार सौंप दिया। इसके बाद हमेशा की तरह बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना भी लगाया।

बिल्ली दूध नहीं पीती

किस्सा

एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने सुना कि उनके नगर में चूहों ने आतंक फैला रखा है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए महाराज ने एक हजार बिल्लियां पालने का निर्णय लिया। महाराज का आदेश होते ही एक हजार बिल्लियां मंगवाई गयी। उन बिल्लियों को नगर के लोगों में बांटा जाना था। जिसे बिल्ली दी गयी उसे साथ में एक गाय भी दी गयी ताकि उसका दूध पिलाकर बिल्ली को पाला जा सके।चूहों से सभी लोग परेशान थे, अतः जब बिल्लियाँ बंट रही थी तो लोगों की लंबी-लंबी कतारें लग गयी थीं। इस अवसर पर तेनालीरामन भी एक कतार में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आयी तो उसे भी एक बिल्ली और साथ में एक गाय दे दी गई। बिल्ली को घर ले जाकर उसने गरमागरम एक कटोरा दूध उसे पीने को दिया। बिल्ली भूखी थी। बेचारी ने जैसे ही कटोरे में मुंह मारा तो गर्म दूध से उसका मुहँ बुरी तरह जल गया। इसके बाद बिल्ली के आगे जब दूध रखा जाता ,चाहे वह ठंडा ही क्यों न हो, बिल्ली वहां से भाग खड़ी होती। गाय का सारा दूध अब तेनालीराम व उसके परिवार के अन्य सदस्य ही पी जाते। बेचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में इतनी कमजोर हो गयी कि उसमे चूहे पकड़ने की ताकत भी नहीं रही। 3 माह बाद महाराज ने बिल्लियों की जांच करवाई। गाय का दूध पी -पीकर सभी की बिल्लियां मोटी-तगड़ी हो गयी थी, परन्तु तेनालीराम की बिल्ली सूखकर कांटा हो चुकी थी। वह सब बिल्लियों के बीच में अलग पहचानी जा रही थी। महाराज ने जब तेनालीराम की बिल्ली की हालत देखी तब वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही तेनालीराम को हाजिर करने का आदेश दिया। तेनालीराम के आने पर वे गरजते हुए बोले, तुमने बिल्ली का यह क्या हाल बना दिया है? क्या तुम इसे दूध नहीं पिलाते ?'' 'महाराज ! मै तो रोज इसके सामने दूध भरा कटोरा रखता हूँ, अब यह दूध पीती ही नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है ?'

महाराज को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अविश्वास भरे स्वर में बोले, ''क्यों झूठ बोल रहे हो ? बिल्ली दूध नहीं पीती ? मै तुम्हारी झूठी बातों में आने वाला नहीं। 'परन्तु महाराज यही सच है। यह बिल्ली दूध नहीं पीती।' महाराज झल्लाकर बोले, 'ठीक है। यदि तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हे सौ स्वर्ण मुद्राएँ दी जाएँगी। अन्यथा सौ कोड़ों की सजा मिलेगी।'' मुझे मंजूर है! तेनालीराम शांत भाव से बोला। तुरंत ही महाराज ने एक सेवक से दूध का भरा कटोरा लाने का आदेश दिया। सेवक जल्द ही दूध से भरा कटोरा ले आया। अब महाराज ने तेनालीराम की बिल्ली को हाथों में उठाया और उसका सिर सहलाते हुए दूध के कटोरे के पास छोड़ते हुए कहा, 'बिल्ली रानी दूध पियो!' बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में रखा दूध देखा, वह म्याऊं-म्याऊं करती हुई वहां से भाग निकली। ''महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। लाइए अब मुझे सौ स्वर्ण मुद्राएं दीजिये।'' तेनालीराम ने कहा। ''वह तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार उस बिल्ली को ध्यान से देखना चाहता हूँ।''यह कहकर महाराज ने एक कोने में छिप गयी बिल्ली को पकड़कर लाने का आदेश दिया।

बिल्ली को अच्छी तरह देखने पर उन्होंने पाया की उसके मुँह में जले का एक बड़ा सा निशान है। वह उसी क्षण समझ गए कि बिल्ली मुँह जल जाने के डर से दूध पीने से कतराती है। वे तेना-लीराम की तरफ देखते हुए बोले। 'अरे निर्दयी! तुमने इस बिल्ली को जानबूझकर गर्म दूध पिलाया ताकि यह दूध न पी सके। ऐसा करते हुए हुए तुम्हे शर्म नहीं आयी।''तेनालीराम ने उत्तर दिया, 'महाराज!, यह देखना तो राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में बिल्लियों से पहले मनुष्य के बच्चो को दूध मिलना चाहिए।'' इस बात पर महाराज हँस दिए। उन्होंने तेनालीराम को तुरंत ही एक हजार स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और बोले, 'तुम्हारा कहना ठीक है, परन्तु मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम बेजुबान पशुओं के साथ दुष्टता नहीं करोगे।''

एक चतुर टोपी-विक्रेता

लघु कथा

एक बार एक टोपी विक्रेता था। वह गाँव-गाँव अपनी टोपियां बेचने जाता था। एक बार जब वह एक गाँव पहुंचा तो बहुत थक गया। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और पेड़ के नीचे सो गया। वृक्ष पर कुछ बंदर थे। बंदर नीचे आये और उसकी टोपियां ले गये। थोड़ी देर के पश्चात् टोपी विक्रेता जाग गया, लेकिन उसे अपनी टोपियाँ नहीं मिलीं। उसने जब ऊपर देखा तो उसकी टोपियां बंदरों के पास थी। उसने एक योजना सोची। उसने अपनी टोपी पहनी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने टोपियाँ एकत्र की। वह चला गया। वह बहुत प्रसन्न था।

शिक्षा : कभी हिम्मत मत हारो।

बूझो तो जानें

इन पहेलियों को हल करके आप अपनी मनोशक्ति को मजबूत कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी चुनौती दे सकते हैं। तो आइए, इन मनोरंजक हिंदी पहेलियों का आनंद लें और अपनी बुद्धि को चुनौती दें!

1. सोने की वह चीज है, पर बेचे नही सुनार। मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार।

2. ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की है लेकिन सुनार की दुकान पर नहीं मिलती?

3. न काशी, न काबा धाम, बिन जिसके हो चक्का जाम। पानी जैसी चीज है वह झट से बताओ उसका नाम।

4. ऐसा कौन सा फल है जो कभी पेड़ पर नहीं लगता?

5. ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती?

6. वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही छोटा होता जाता है?

7. ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक ही तरह से लिखा जाता है?

उत्तर : 1.चारपाई, 2. तकिया और चारपाई, 3. पेट्रोल, 4. तर्क, 5. परछाई, 6. पेंसिल, 7 mom

अभिभावकों के विशेष अनुरोध और बच्चों के शिक्षाप्रद मनोरंजन के लिए हम यह विशेष पन्ना शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है इससे पाठकों का भरपूर मनोरंजन होगा।

हंसी के फव्वारे

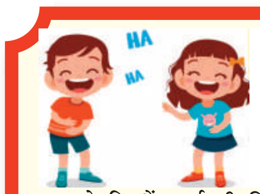

इतवार के दिन बैंक कर्मचारी की बीबी- उठो, जागो.. देखो मेरे मम्मी पापा आए हैं।
आदमी- उनको कहो लाइन में लगें, और आईडी साथ में रखें।

♦♦♦♦♦♦♦

टीचर- लड़कियां अगर पराया धन होती है तो लड़के क्या होते है??
गप्पू- सर चोर होते है!
टीचर वो कैसे?
गप्पू- क्योकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पर होती है।

♦♦♦♦♦♦♦

पत्नी की खूबसूरती हसबैंड-डार्लिंग तुम खुबसूरत होती जा रही हो।
पत्नी किचन से- तुमने कैसे जाना ?
हसबैंड- तुम्हें देखकर तो अब रोटियां भी जलने लगी हैं।

♦♦♦♦♦♦♦

डेट और तारीख का अंतर
टीचर- डेट और तारीख में क्या अंतर है ? सारी क्लास रूम चुप
गप्पू- सर, डेट में गर्लफ्रेंड के साथ जाते है और तारीख में वकील के साथ।

♦♦♦♦♦♦♦

सास- बहू कहां हो तुम? बहू- होटल में हूं, बहुत तेज बहुत भूख लग रही थी है इसलिये यहां खाना खा रही हूं,
आप कहां हो सासू मां?
सास- लंगर में... तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ी हूं, खीर मेरे लिए भी ले लेना।

♦♦♦♦♦♦♦

हसबैंड- आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे।
पत्नी- हमारे यहां भैंस का दूध आता है नागिन का नहीं।

♦♦♦♦♦♦♦

पप्पू- रात भर मुझे नींद नहीं आई...!
गप्पू- क्यों..?
पप्पू- रात भर मैंने सपने में देखा कि मैं जाग रहा हूं...!

♦♦♦♦♦♦♦

संता मोबइल कंपनी में इंटरव्यू देने गया पहले सवाल पर ही उसे भगा दिया गया...
सवाल- सबसे मशहूर नेटवर्क कौन सा है?
संता- कार्टून नेटवर्क।

♦♦♦♦♦♦♦

सोनू - मां ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?
मां - बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू।
सोनू (मन ही मन सोचता हुआ) बोला- कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग आ रही है।

माथापच्ची-6

	1							
	4			7	5	9		
9	8		6					7
7		2	1				3	8
4				8				6
8	6				9	5		2
1					2		8	9
		9	5	3			4	
							2	

उत्तर अगले अंक में

माथापच्ची 5 का हल

3	2	6	8	4	5	1	7	9
4	8	7	6	1	9	5	2	3
9	1	5	7	2	3	6	8	4
7	9	2	5	6	8	4	3	1
6	4	8	3	9	1	7	5	2
1	5	3	4	7	2	8	9	6
2	6	1	9	5	7	3	4	8
8	7	4	2	3	6	9	1	5
5	3	9	1	8	4	2	6	7

Page-12_Layout 1 6/7/2025 2:37 PM Page 1

मनोरंजन

मैं भी एक इंसान हूँ : रश्मिका

मुंबई : इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 4 सालों में रश्मिका मंदाना नेशनल क्रश बन गई हैं। उन्होंने इस दौरान बहुत ज्यादा फिल्में तो नहीं की लेकिन कम फिल्मों में ही अपनी अपीयरेंस से ना सिर्फ फैंस का दिल जीता है बल्कि उन्होंने डायरेक्टर्स का भरोसा भी जीता है। रश्मिका मंदाना पहले साउथ फिल्मों का ही हिस्सा थीं, लेकिन पुष्पा फिल्म के बाद से एक्ट्रेस की किस्मत ही पलट गई। आज उनके चाहनेवालों की कमी नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग करियर के भी 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर रश्मिका मंदाना ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने करियर और स्ट्रगल्स के बारे में बातें की हैं। रश्मिका ने कहा- रश्मिका मंदाना ने हालिया इंटरव्यू के दौरान कहा कि- जैसा कि मैं अपने करियर के 9वें साल में एंट्री मार रही हूं मैं खुद को एक एक्ट्रेस और एक इंसान के तौर पर और विकसित करना चाहती हूं। मैं लगातार सीखते रहना चाहती हूं क्योंकि मुझे लंबा रास्ता तय करना है। अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो पाती हूं कि मेरी जर्नी इतनी भी आसान नहीं रही है लेकिन इस दौरान मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मगर अभी भी मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। मुझे भरोसा है कि मुझे करियर में आगे भी ग्रो करने के और अनुभव हासिल करने के अवसर मिलेंगे। मैं बस आगे चलते रहने को अग्रसर हूं बाकि देखते हैं कि मेरा ये सफर कहां तक जाता है।रश्मिका मंदाना को उनके इन 8 साल के करियर के दौरान तारीफ तो खूब मिली है साथ ही एक्ट्रेस को आल-ोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा है। एक्ट्रेस ने इसके जवाब में कहा- इन बीते सालों में मुझे क ॉन्स्ट्र क्टिव क्रिटिसिज्म और नॉइस के बारे में फर्क समझ में आ गया है। खासकर जब बात मेरे क्राफ्ट की होती है तब मैं इस बात का ज्यादा ध्यान रखती हूं। कई मौके ऐसे होते हैं जब मेरे बारे में कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे पढ़कर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रश्मिका ने आगे कहा- मैं भी एक इंसान हूं और कभी कभी मुझपर भी क्रिटिसिज्म का असर पड़ता है लेकिन फिर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मैं उन लोगों के बारे में सोचकर बहुत अच्छा महसूस करती हूं जिन्होंने इस सफर के दौरान मेरा उत्साह बढ़ाया। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। ना तो मैंने कभी भी एक्ट्रेस बनने का सोचा था। लेकिन मुझे लोगों का सपोर्ट मिलता गया और मैं आगे बढ़ती गई।

पीके- 2 में आमिर खान फिर बनेंगे एलियन

- साथ होंगे रणबीर कपूर
- सुपरहीरो फिल्म की भी तैयारी

मुंबई : बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनस्टि आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के तीन साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उनकी सितारे जमीन पर इसी महीने 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। लगता है कि आमिर एक के बाद एक धमाकेदार फिल्मों की बाढ़ लाने वाले हैं। बीते दिनों खबर आई कि इसके बाद वह राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में दादासाहेब फाल्के की बायोपिक की तैयारी में जुट जाएंगे। अब, एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि आमिर खान पीके 2 में एलियन बनकर लौटने वाले हैं। यही नहीं, इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर भी हो सकते हैं। इसके अलावा आमिर गुलशन कुमार की बायोपिक और एक सुपरहीरो फिल्म करने पर भी जोर लगा रहे हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, राजकुमार हिरानी के साथ दादासाहब फाल्के की बायोपिक पर काम शुरू करने से पहले आमिर खान ने कम से कम 10 नई स्क्रिप्ट पर गौर फरमाया है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है, आमिर खान और राजकुमार हिरानी ने मिलकर भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के पर फिल्म बनाने का सपना देखा था और इसकी स्क्रिप्ट पर काफी समय से काम चल रहा था। जब राजू, दादा साहब फाल्के पर काम कर रहे थे, तब आमिर इसके अलावा भी कई स्क्रिप्ट पर गौर फरमा रहे थे। बताया जाता है कि आमिर ने अपने तीन साल के ब्रेक में जिन 10 स्क्रप्टि पर चर्चा की है, उनमें राजकुमार संतोषी की दो फिल्में चार दिन की जिंदगी और अंदाज अपना अपना 2 शामिल हैं। इसके अलावा दिनेश विजान के साथ वह वकील उज्ज्वल निकम की बायोपिक, अनुराग बसु के साथ किशोर कुमार की बायोपिक और राकेश ओमप्रकाश मेहरा के साथ भी एक फिल्म पर भी चर्चा हुई है।

गुलशन कुमार की बायोपिक करेंगे आमिर खान!

रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से आगे कहा गया है कि आमिर खान ने डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी और भूषण कुमार से भी मुलाकात की है। इस दौरान तीनों के बीच गुलशन कुमार की बायोपिक पर चर्चा हुई। हालांकि, इन फिल्मों को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

खबरें

अमित शाह का सपना नहीं होगा पूरा : तृणमूल

विधानसभा चुनाव में भाजपा को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी

निज संवाददाता : पिछले दिनों नेताजी इंडोर स्टेडियम में भाजपा के दिग्गज नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने सांगठनिक बैठक में अपने भाषणों से प्रदेश के कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने की पूरजोर कोशिश की। अपने भाषणों में उन्होंने आगामी 2026 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार की, और कहा कि इस बार तृणमूल का जाना तय है। भाजपा के संगठनात्मक नेतृत्व सम्मेलन में शाह ने कहा कि दीदी, आपका समय पूरा हो गया है। 2026 में (पश्चिम बंगाल में) भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं यहां बैठे हजारों मंडल अध्यक्षों से वादा करता हूं कि जैसे ही तृणमूल सरकार यहां से जाएगी, हम अपने कार्यकर्ताओं के हत्यारों को पाताल से ढूंढ़कर सजा देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री यहीं नहीं रुके। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा कभी भी वांछनीय नहीं है। दीदी, अगर हिम्मत है तो हिंसा और धांधली के बिना चुनाव कराकर देखें। बंगाल की जनता आपकी जमानत जब्त कर लेगी। इधर दूसरी ओर तृणमूल ने भी शाह की इस टिप्पणी के बदले में उन पर हमला बोला। तृणमूल भवन में दो सांसदों सागरिका घोष और काकली घोष दस्तीदार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय चुनाव आयोग की है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय बलों की होती है। इसे एक संकेत के रूप में लेते हुए, तृणमूल नेता ने सवाल उठाया कि क्या गृह मंत्री शाह ने स्वीकार किया है कि उनके हाथों में केंद्रीय बल हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं? साथ ही, तृणमूल कांग्रेस ने शाह के इस दावे को खारिज कर दिया है कि 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा सत्ता पर कब्जा कर लेगी। बारासात के सांसद काकोली ने दावा किया है कि भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों को उनके हक के पैसे से जबरन वंचित कर रही है। और 2026 में, तृणमूल कांग्रेस 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 250 सीटों का आंकड़ा पार करके सत्ता पर कब्जा करेगी। यानी भाजपा को 50 सीटें भी नहीं जीत पायेगी।

बच्चों के लिए विशेष शिविर

निज संवाददाता : विवेकानन्द केन्द्र कन्याकुमारी की बंगाल प्रान्त की विवेकानन्द नगर कार्यस्थान द्वारा बच्चों के लिए एक दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सीकर नागरिक परिषद, कोलकाता के सहयोग से सीकर भवन में किया गया। शिविर की शुरुआत मेहुल पाठक द्वारा शांति पाठ से हुई, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। इसके पश्चात नगर प्रमुख वनिता झारखंडी ने सभी का स्वागत करते हुए शिविर की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। प्रारंभिक सत्र में बच्चों ने शांति पाठ, सूर्य नमस्कार और जन्मदिन के श्लोकों का अभ्यास किया। इस अवसर पर बंगाल प्रान्त की प्रान्त सह प्रमुख मालविका चटर्जी ने श्लोकों के गूढ़ अर्थों को सरलता से समझाते हुए बच्चों को इस अवसर को आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता से जोड़ने की प्रेरणा दी। सीकर नागरिक परिषद की सुनीता लोहिया ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय और आवश्यक हैं। इसके पश्चात 'जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है।' गीत को सभी ने उत्साह और ओज के साथ गाया, जिससे देशभक्ति की भावना सजीव हो उठी। इसके बाद बच्चों ने अपने अनुभव और प्रेरणादायी प्रसंग साझा किए, जो अत्यंत मार्मिक और उत्साहजनक रहे।शिविर में मुकुल भट्टाचार्य और आशा बसाक के निर्देशन में बच्चों ने योगाभ्यास किया, जिसमें विशेष रूप से सूर्य नमस्कार को सम्मिलित किया गया। इस सत्र में राधिका शर्मा, सिमरन सिंह और मेहुल पाठक का विशेष सहयोग रहा। प्रान्त के कार्यपद्धति प्रमुख श्यामसुंदर जायसवाल ने बच्चों के लिए विविध प्रकार के खेलों का आयोजन किया, जिससे उनके मानसिक, शारीरिक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहन मिला। प्रान्त अधिकारी अरविन्द सिंह ने भी बच्चों का उत्साह बढाया।शिविर के अंतिम चरण में सभी प्रतिभागियों ने संस्कार वर्ग में सम्मिलित होकर देश और समाज के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। समापन मिता दे के शांति मंत्र के साथ हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को पाठ्य सामग्री और स्वामी विवेकानन्द की पुस्तक भेंट की गई।

पेज 1 का शेष

मातम में बदला...

जश्न के दौरान अचानक एक कार तेज गति से आई और करीब 50 लोगों को टक्कर मार दी। स्वाभाविक रूप से, ईपीएल चैंपियन के विजय जुलूस के आसपास एक अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल, लिवरपूल लंबे समय के बाद चैंपियन बने थे। जुलूस के दौरान उनके आसपास एक अलग उन्माद पैदा हो गया था। आईपीएल चैंपियन को फुटबॉलर और कोच समेत सभी को हुड वाली बस में बिठाकर शहर की सड़कों पर घुमाना था। चैंपियन टीम का स्वागत करने के लिए कई लोग मैदान पर आए थे। लेकिन तभी आपदा आ गई। बाद में पता चला कि 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें चार बच्चे भी थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी चिंता जताई। हालांकि, पुलिस कार्रवाई से स्थिति पर काबू पा लिया गया। 53 वर्षीय ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पेरिस सेंट-जीन की जीत के जश्न पर आते हैं। इतिहास में पहली बार उन्होंने चैंपियंस लीग की जीत का स्वाद चखा है। लेकिन उनका जश्न भी फीका पड़ गया। पेरिस में पीएसजी के प्रशंसकों ने विजय जुलूस निकाला। वहां क्लब के प्रशंसक नाच रहे थे, गा रहे थे और संगीत बजा रहे थे। वे जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। नतीजतन, भारी ट्रैफिक जाम हो गया। एक मोटरसाइकिल सवार की कार की चपेट में आने से मौत हो गई।

इसके अलावा, भीड़ में एक 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। उसकी जान चली गई। बाद में पता चला कि इस तरह की पागलपन भरी घटना के कारण 550 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, म्यूनिख स्टेडियम में, जहां पीएसजी इंटर मिलान को 5-0 से हराकर चैंपियन बना था, वहां भी दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पीएसजी के प्रशंसक सुरक्षा की अनदेखी करते हुए फेंसिंग फांदकर मैदान में घुस गए। उन्होंने मैदान पर कब्जा कर लिया। वे इतने उन्मादी थे कि कुछ ने घास उखाड़ दी, कुछ ने जाल ले लिए और कुछ ने तो जमीन ही खोद दी। जर्मन पुलिस उनसे निपटने में असमर्थ थी। हालांकि उस दिन कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ।और सबसे दुखद परिणाम आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का विजय जुलूस था। आईपीएल खिताब जीतने के अगले दिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की शादी की पार्टी आयोजित की गई। आईपीएल के 18 साल के इतिहास में पहली बार बेंगलुरु चैंपियन बना। और इसलिए उन्माद स्पष्ट था, क्योंकि वे चैंपियन टीम को देखने वाले थे। जब स्टेडियम में आरसीबी वंदना हो रही थी, तब बाहर भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। 50 से अधिक घायल हो गए। एक समय तो यह आशंका भी जताई जा रही थी कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बुधवार 4 जून को स्टेडियम में प्रवेश के लिए पास दिए गए। इसके बारे में विज्ञापन दिए गए। विजेता टीम को देखने की उम्मीद में कई समर्थक सुबह से ही मौजूद थे। कई मुफ्त पास लेने के लिए बेताब थे। तभी बवाल मच गया। भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई। कुछ वीडियो वायरल हुए। वहां, बीमारों को एंबुलेंस में अस्पताल ले जाते देखा गया। एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को गोद में लेकर दौड़ता हुआ दिखाई दिया।

बताया गया कि स्टेडियम परिसर में करीब पांच हजार सुरक्षा गार्ड थे। इतनी भारी सुरक्षा मौजूदगी के बावजूद सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैसे हुई। सवाल यह है कि जब स्टेडियम के बाहर शोक संतप्त लोगों की चीखें गूंज रही थीं, तो अंदर आरसीबी टीम के लिए जीत का जश्न मनाया जा रहा था। क्या क्रिकेटरों तक कोई खबर नहीं पहुंची? ऐसी अनचाही घटना के बाद भी प्रशासन ने जश्न जारी रहने कैसे दिया? दरअसल, हजारों सवालों की भीड़ के कारण कभी-कभी खेल ही रक्तरंजित हो जाता है। दुनिया में चाहे कहीं भी हो, यह कतई वांछनीय नहीं है।

Page-13_Layout 1 6/7/2025 2:13 PM Page 1

वर्णमाला का सहज पाठ

बच्चे के भविष्य के शैक्षिक क्षेत्र के दायरे को आकार देती है शिक्षा

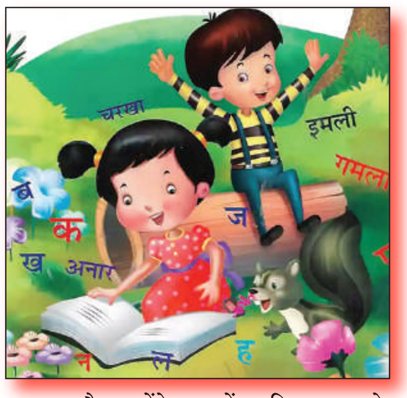

नुपुर मित्रा

शिक्षा बच्चे के भविष्य के शैक्षिक क्षेत्र के दायरे को आकार देती है। बच्चों को पढ़ाना समाज में एक आवश्यक गतिविधि मानी जाती है। बंगाल भी इसका अपवाद नहीं है। लेकिन माता-पिता बच्चे के भविष्य या उसकी नींव बनाने से ज्यादा इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें कितनी जल्दी स्मार्ट बनाया जा सकता है। आजकल परिवार आमतौर पर छोटे होते हैं। अतीत का बाल शिक्षा वातावरण आज की सपाट संस्कृति में लुप्त हो रहा है। समय के साथ-साथ, बच्चों के पढ़ने के तरीके में भी विघटन जुड़ गया है, जो पुरानी परम्पराओं को तोड़ रहा है। मदनमोहन तर्कालंकार बंगाल में बच्चों की पाठ्यपुस्तक लिखने वाले पहले प्रमुख व्यक्ति थे। मदनमोहन तर्कालंकार द्वारा लिखित पहली प्राथमिक बच्चों की पाठ्यपुस्तक 1849 में प्रकाशित हुई थी। विद्यासागर की वर्ण परिचय (भाग एक) 1855 में प्रकाशित हुई थी। विद्यासागर को आधुनिक बांग्ला वर्णमाला का निर्माता कहा जाता है। वे वह व्यक्ति थे जिन्होंने वर्णमाला में सुधार किया। विद्यासागर ने गांव जाते समय पालकी में यात्रा करते हुए वर्ण परिचय की एक पांडुलिपि बनाई थी। बंगाली घरों में, बच्चा वर्णमाला को पहचानने का पहला पाठ इसी पुस्तक से सीखता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। जीवन बदल गया, समय बदल गया, लेकिन श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा बनाई गई वर्ण परिचय' वहीं बनी हुई है। बाद के वर्षों में, बच्चों के पहले पाठों में नई सामग्री जोड़ी गई है। लेकिन यह किताब नहीं बदली है। भाषा शिक्षा के साथ-साथ वे विद्यार्थियों को नैतिकता और मूल्य भी सिखाना चाहते थे। उन्होंने वर्णपरिचय के प्रथम भाग की प्रस्तावना में अपने विचार और तर्क व्यक्त किये। और दूसरे भाग में जुड़े हुए अक्षरों का पाठ है। उन्होंने पाठ में जाति पहचान के दोनों भागों को उसी प्रकार व्यवस्थित किया। और अन्य पांच बंगाली बच्चों की तरह, बालक रवींद्रनाथ की वर्णमाला की कक्षाएं भी जोड़ासांको में बचपन में विद्यासागर के वर्ण परिचय से शुरू हुईं। इसी किताब से ''पानी गिरने और पत्तियों के हिलने'' की लय उनके दिमाग में अंकित हो गई। इजी रीडिंग का जन्म उनके स्थायी प्रभाव से हुआ। स्वयं रवींद्रनाथ टैगोर को भी वर्णमाला सीखते समय यह पुस्तक पढ़नी पड़ी थी। इसका प्रमाण उनके अपने लेखन में है। विद्यासागर महाशय ने हमें हमारी जाति से परिचित कराया। रवि टैगोर ने उन पत्रों को माधुर्य और ध्वनि का जादू दिया। सहज पाठ 1930 के बैशाख महीने में प्रकाशित हुआ था। सबसे अच्छा संयोजन रवींद्रनाथ टैगोर का सहज पाठ (भाग एक) है। इन सबके बावजूद सहज पाठ आज भी प्रासंगिक है। यहां के बच्चों के स्वभाव ने ग्रामीण बंगाल की छवि का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यदि आप इसका गहराई से अध्ययन करेंगे तो यह किसी उपन्यास से कम नहीं लगेगा। रवींद्रनाथ बच्चों को सरल भाषा में लय के माध्यम से वर्णमाला से नए तरीके से परिचित कराना चाहते थे। यह पुस्तक बच्चों को मानवीय बनना सिखाती है, जिसकी छत्रछाया में रवींद्रनाथ युवा पाठकों को जीवन की शिक्षा देना चाहते थे। रवींद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही सचेत रूप से कहानियों के माध्यम से सरल पाठों के माध्यम से बच्चों के मन में मानवता के बुनियादी पाठों को डालने का प्रयास किया।

नेताजी के परिवार ने किया दावा

विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी सुभाषचंद्र बोस की मौत

- अब नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 'रहस्यमय मौत' को लेकर नए सिरे से उठा सवाल
- नेताजी के नाम पर किसी और की अस्थियां इतने लंबे समय तक पूरी दुनिया के सामने क्यों?

निज संवाददाता : महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 'लापता' होने का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। ताइहोकू विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत को लेकर विवाद जारी है। हालांकि परिवार के एक हिस्से ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन कई लोग इसे स्वीकार करने से हिचक रहे हैं। अब नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 'रहस्यमय मौत' को लेकर नए सिरे से सवाल उठाया गया है। यह सवाल खुद नेताजी के परिवार ने उठाया है।

नेताजी के बड़े भाई शरत चंद्र बोस के परिवार ने पूछा है कि जिनकी (नेताजी) मृत्यु ताइहोकू विमान दुर्घटना में हुई नहीं, उस 'फर्जी' दुर्घटना में नेताजी की तथाकथित अस्थि होने की बात कैसे आई? परिवार का दावा है कि सुभाषचंद्र बोस की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। उस विवादास्पद अध्याय को साबित करने के लिए ताइवान सरकार की 1956 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। लंदन से एकत्र दो शोधकर्ताओं की रिपोर्ट को नेताजी के परदादा शरत चंद्र बोस के सबसे बड़े बेटे अशोक नाथ बोस के वंशजों ने प्रकाशित किया है। बीते 29 मई को रिपोर्ट जारी की गई और घोषणा की गई कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी।

शोधकर्ता और लेखक सैकत नियोगी और सौम्ब्रत दासगुप्ता की पहल पर ताइवान सरकार की रिपोर्ट कोलकाता लाई गई। इस दिन नेताजी की दो पोतियों, अशोक नाथ बोस की बेटी जयंती रक्षित, तापती घोष और नेताजी के पोते और अशोक नाथ बोस के बेटे आर्य बोस की रिपोर्ट कोलकाता प्रेस क्लब में प्रकाशित हुई। इस दिन रिपोर्ट की प्रतियां भी वितरित की गईं। दोनों युवा शोधकर्ताओं के अलावा न्यायाधीश बिप्लब रॉय भी वहां मौजूद थे। नेताजी के नाम पर किसी और की अस्थियां इतने लंबे समय तक पूरी दुनिया के सामने क्यों रहीं? 2022 में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की बेटी अनीता बसु पाफ ने मांग की थी कि नेताजी की अस्थियां भारत वापस लाई जाएं। लेकिन क्या वो अस्थियां वाकई नेताजी की हैं? गौरतलब है कि अशोक नाथ बसु महान पलायन के दौरान नेताजी के साथी सैनिकों में से एक थे। इस बैठक में नेताजी पर शोध करने वाले दो लोग क्रमशः सैकत नियोगी और सौम्यब्रत दासगुप्ता मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी।

इस संबंध में उन्होंने लंदन अभिलेखागार से बरामद एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की। तो जब नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, तो फिर रेंकोजी मंदिर में उनकी तथाकथित अस्थियों को वापस लाने की मांग केंद्र से क्यों की जा रही है? इस दिन नेताजी के परदादा शरत चंद्र बोस के बड़े बेटे के परिवार ने सवाल उठाए। यह रिपोर्ट कैसे सामने आई? नेताजी पर शोध करने वाले का कहना है कि शोध के लिए उन्होंने विभिन्न देशों में नेताजी पर रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। इस रिपोर्ट का स्रोत उस खान से मिला। शोधकर्ता ने यह भी कहा कि नेताजी की मौत के दिन ताइवान के ताइहोकू में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। ताइवान सरकार ने एक रिपोर्ट के जरिए इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद शोधकर्ता ने आरोप लगाया कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने रिपोर्ट मिलने के बावजूद इसे सार्वजनिक नहीं किया। इसके उलट, भविष्य में नेताजी पर जो आयोग चलाए गए, वे भी गुमराह करने वाले थे। प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद एक अन्य शोधकर्ता सौम्ब्रत दासगुप्ता ने कहा-साठ के दशक में ताइवान सरकार से ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद भी भारत सरकार ने इसे छुपाया। इससे साबित होता है कि नेताजी की अस्थियों और विमान दुर्घटना को लेकर कितनी बड़ी साजिश रची गई थी।

गांवों की राजनीति और 2027 का पंचायत महाकुंभ

किशन मिश्रा

> नेताओं और निर्वाचन आयोग की इस सक्रियता से साफ है कि पंचायत चुनाव को लेकर सियासी मशीनरी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है।

कहा जाता है कि देश की आधी से अधिक आबादी गावों में बसती है। सत्ता के खेल में गांव का मत ही राजनीतिक कप्तान और पार्टी तय करती है। इस कारण पार्टियों का सारा ध्यान गांव की राजनीतिक के ईर्दगिर्द ही घूमती है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। लगभग 57,691 ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, 826 ब्लॉक प्रमुख, 3,200 जिला पंचायत सदस्य और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं।

पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे आने के बाद ही प्रदेश की सियासी तस्वीर साफ होगी। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही अधिसूचना जारी करने की संभावना है। ऐसे में राजनीतिक दल भी अपनी-अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। पंचायत चुनाव से न केवल दलों की लोकल पकड़ का पता चलेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनकी रणनीतियों की दिशा भी तय होगी। उत्तर प्रदेश के गांवों में पंचायत चुनाव को लेकर जो सरगर्मी दिख रही है, उससे यह साफ हो गया है कि ये चुनाव प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। पंचायत चुनाव तीन स्तरों पर होते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा और सियासी रसगुल्ले गांव के प्रधान चुनाव को लेकर होती है, क्योंकि ग्राम प्रधान सीधे गांव की राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। नेताओं और निर्वाचन आयोग की इस सक्रियता से साफ है कि पंचायत चुनाव को लेकर सियासी मशीनरी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। पिछले पंचायत चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि पंचायत चुनावों में सत्ताधारी दल का ही दबदबा रहता है।

2021 के पंचायत चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, आम आदमी पार्टी और कई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। कुल 3050 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर हुए चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी खासा दम दिखाया। भाजपा ने 768 सीटें जीतीं, सपा ने 759, बसपा ने 319, कांग्रेस 125, आरएलडी 69 और आम आदमी पार्टी 64 सीटों पर जीत हासिल की। निर्दलीयों की संख्या 944 रही। भाजपा ने निर्दलीयों को अपने साथ जोड़कर 67 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर ली, जबकि सपा महज पांच जिलों में ही अध्यक्ष बना सकी। यह आंकड़ा यह बताता है कि पंचायत स्तर पर भी सत्ता का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है।पंचायत चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है, क्योंकि इस चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी संख्या की सीटें शामिल होती हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग दो तिहाई विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाकों से आती हैं, इसलिए पंचायत चुनाव का नतीजा सीधे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ताकत पर प्रभाव डालता है। राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद गहन मंथन करते हैं। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय ताकत, वोट प्रतिशत, पिछली बार की तुलना में वोटों में बढ़ोतरी या कमी, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में पंचायत चुनावों का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इससे दलों की लोकल स्तर पर पकड़ का पता चलता है।

पंचायत चुनाव से पार्टी का बूथ स्तर तक संगठन मजबूत होता है। गांवों के छोटे-छोटे चुनाव भी बड़े चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिस पार्टी के पास मजबूत ग्राम स्तर की पकड़ होती है, उसके लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतना आसान होता है। इसलिए दल पंचायत चुनाव को हल्के में नहीं लेते और पूरे जोर-शोर से चुनाव लड़ते हैं।अनुप्रिया पटेल ने यह भी बताया कि पंचायत चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहते हैं। गठबंधन में रहते हुए यह संभव नहीं था कि सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ पाएं, इसलिए अकेले चुनाव लड़ना जरूरी था। उन्होंने कहा कि संगठन को पंचायत चुनाव के अनुसार मजबूत करना होगा। पंचायत चुनाव में हर स्तर पर संगठन को तैयार करने की कवायद चल रही है। पार्टी बूथ स्तर पर भी मजबूत हो रही है ताकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पूरी मदद मिल सके।राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति की जमीन तैयार करते हैं। गांव की राजनीति से जुड़ी दलों की पकड़ मजबूत होने पर विधानसभा चुनाव में भी उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। पंचायत चुनाव में मिली सफलता से नेताओं को यह भी समझने में मदद मिलती है कि किस क्षेत्र में उनकी पार्टी की पकड़ कमजोर है और वहां वे अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं।

इसके अलावा, पंचायत चुनाव से दलों को जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को समझने में भी मदद मिलती है।इस चुनाव का परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी मिजाज का आईना होगा। जो पार्टी पंचायत चुनाव में सफल होगी, उसकी सियासी पकड़ मजबूत होगी और वह विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। इसलिए 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में खासा उत्साह और संघर्ष देखा जा रहा है। यह चुनाव सिर्फ ग्रामीण नेतृत्व चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य की सियासत के लिए मजबूत आधार बनाने का जरिया बनेंगे। इस चुनाव के परिणाम पूरे प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे और तय करेंगे कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में होगी।

Page-14_Layout 1 6/7/2025 2:18 PM Page 1

ज्योतिष

जानें अपना राशिफल

मेष
किसी से प्रभावित होकर काम करने वाला समय हो सकता हैं, किसी विदेश यात्रा करने पर विचार हो सकता हैं, पूरी नैतिकता से काम करने की आवश्यकता है, मन शान्त रखें।

वृषभ
समस्या का समाधान मिलने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता हैं प्रयास करें, अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है।

मिथुन
रणनीति बनाकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई आपका समय खराब कर सकता है सावधान रहें, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, मन शान्त रखें। गहरे वस्त्र धारण न करें।

कर्क
तनाव भरा समय हो सकता हैं इसलिए शान्ति दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है, किसी के बहकावे में आने से बनता काम बिगड़ सकता हैं सावधान रहें। बिना काम बाहर न जाएं।

सिंह
गुमराह होने वाला समय हो सकता हैं इसलिए जो भी काम कर रहे हैं, सोच समझकर ही करें। किसी के बहकावे में आने से बनता काम बिगड़ सकता हैं सावधान रहें। मन वश में रखें।

कन्या
हैसियत दिखाने वाला समय हो सकता हैं, कोई वाहन खरीदने का विचार हो सकता हैं। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

तुला
समझौता करने वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है। अपने परिवार को प्रसन्न रखें, मन वश में रखें।

वृश्चिक
प्रेरणा लेकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करें। अपनी बुद्धिमानी दिखाने की आवश्यकता है, मन चंचल रहेगा।

धनु
मार्गदर्शन वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करें। किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, मन शान्त रखें।

मकर
सशक्त समय हो सकता है, कोई रुका हुआ जमीन का काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करें। किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, मन में उत्साह रहेगा। सफेद वस्त्र धारण न करें।

कुंभ
गलतफहमी वाला समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं सावधान रहकर ही करें। किसी के बहकावे में आने से बनता काम बिगड़ सकता हैं सावधान रहें। मन वश में रखें।

मीन
सुरक्षित समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा। किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है। अपने परिवार को प्रसन्न रखें। मन शान्त रखें।

वास्तु शास्त्र के कुछ उपायों को अपनाने से चमकेगा व्यवसाय, आएगी खुशहाली

निज संवाददाता : हर इंसान की चाह होती है उसकी आमदनी की कोई सीमा नहीं हो। उसका व्यवसाय हमेशा आगे बढ़ता रहे। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो व्यक्ति ज्योतिषों के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनी दुकान, बिजनेस की जगह, फैक्टरी, ऑफिस आदि में करना चाहिए। इससे आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होगा और आपको लाभ कराएगा। आइए जानें मुख्य दरवाजे से लेकर बैठने की सीट तक क्या वास्तु उपाएं आपके बिजनेस को चमकाएंगे। रिटेल शॉप में उत्तर की तरफ हो एंट्री आपके रिटेल की शॉप की एंट्री की दिशा बहुत जरूरी है। इसके जरिए ही पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होती है। एंट्री को उत्तर या पूर्व की ओर रखना शुभ माना जाता है, जो समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। मेन एंट्रेस में कोई रुकावट न हो, अच्छी रोशनी हो और यह बहुत सुंदर और आकर्षित हो।

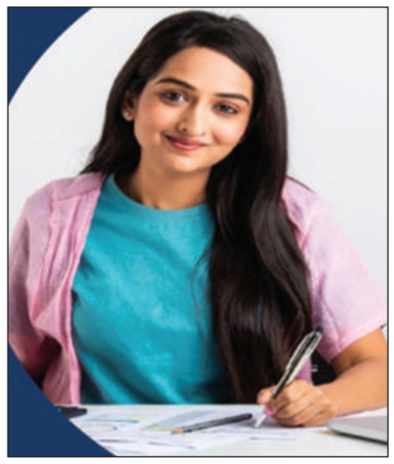

सुबह शंख बजाएँ

दुकान पर सुबह शंख बजाएं या मोबाइल पर शंख ध्वनि सुनें। दुकान की उत्तर दिशा में मिट्टी के बर्तन में कुछ छुहारे रखें। दुकान के काउंटर पर एक फेंगशुईवाली बिल्ली रखें, जो लगातार अपना हाथ हिलाती रहती है। दुकान की उत्तर पूर्व दिशा में रखे लोहे के ताले-चाभी वहां से हटा दें। दुकान के दक्षिण पूर्व दिशा में लाल रंग के फूलदान रख दें। दुकान में रखे हुए सामान को इधर से उधर अदला-बदली कर दें। अपनी गद्दी पर कुर्सी के नीचे एक पीला कपड़ा बिछाएं तथा एक पीपल का पत्ता रखें, जिसे हर दिन बदलते रहें।

इस दिशा में हो कैश काउंटर

वास्तु में कैश रखने की भी एक महत्वूपर्ण दिशा है। वास्तु के अनुसार उत्तर, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में रखा धन और धन को खींचता है। इस जगह कैश रखने से आपकी लाइफ में धन की वृद्धि होती है।

नई गाड़ी के डैशबोर्ड में रखनी चाहिए भगवान की मूर्ति

निज संवाददाता : आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा, जो अपनी नई गाड़ी में भगवान की मूर्ति या तस्वीर लगाते हैं। जिससे कि उनकी गाड़ी की सुरक्षा बनी रहे और यात्रा मंगलमय हो। वाहन में भगवान की मूर्ति रखने का वास्तु के मुताबिक भी विशेष महत्व होता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक किसी भी वाहन में देवता की प्रतिमा रखने से पहले कुछ नियमों और सुझावों का पालन करना जरूरी होता है। वहीं वास्तु में नए वाहन के डैशबोर्ड में कुछ विशेष भगवानों की मूर्ति या प्रतिमा रखने की सलाह दी जाती है। नई गाड़ी के डैशबोर्ड पर किस भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि नए वाहन में किस देवता की मूर्ति रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक वाहन में शुभता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हनुमानजी, गणेश जी, मां दुर्गा और आदियोगी की मूर्ति रखना उत्तम माना जाता है।

गणेश जी की मूर्ति

कार के डैशबोर्ड पर गणेश जी की मूर्ति रखना चाहिए। इसको शुभ और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, वह सभी बाधाओं और संकटों को दूर करने वाले देवता हैं।

हनुमान जी की मूर्ति

अगर आप भी वाहन दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आपको गाड़ी के डैशबोर्ड में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति या तस्वीर रखना शुभ माना जाता है। वहीं भगवान हनुमान को बल, बुद्धि और विजय का प्रतीक माना जाता है। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर निकलते हैं, तो हनुमान जी का स्मरण आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाता है।

मां दुर्गा की मूर्ति

कार के डैशबोर्ड में मां दुर्गा की मूर्ति रखना चाहिए। मां दुर्गा शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा को संकटों का नाश करने वाली माना जाता है और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। महिलाएं अपनी गाड़ी में मां दुर्गा की मूर्ति रखना शुभ मानती हैं, क्योंकि इससे महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होती है। वहीं मां दुर्गा की कृपा से वाहन चलाने के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से भी सुरक्षा मिलती है। इसलिए गाड़ी की डैशबोर्ड पर मां दुर्गा की छोटी सी मूर्ति सामने रखनी चाहिए।

अध्यात्म

सिंहस्थ 2028 : उज्जैन को मिला विकास का महाघोष

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया 864 करोड़ की परियोजनाओं का भूमिपूजन

अजय कुमार मोहता

उज्जैन : प्राचीन संस्कृति की पुनर्स्थापना और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा अंगारेश्वर महादेव मंदिर परिसर से सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का शुभारंभ किया गया। ₹864 करोड़ की लागत से क्षिप्रा नदी पर 29 किलोमीटर लंबे घाटों और 21 नए पुलों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत उत्सव है। शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक दोनों किनारों पर बनने वाले घाटों की लंबाई 29 किलोमीटर होगी, जिन पर सिंहस्थ के दौरान 24 घंटे में करीब 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे।सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवी अहिल्याबाई होल्कर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन शासन और सेवा का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई ने संपूर्ण शासन को भगवान महादेव को समर्पित कर दिया था। उनके कार्यों में नर्मदा जैसी सादगी और गंगा जैसी पवित्रता थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि घाट निर्माण के साथ-साथ क्षिप्रा नदी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा गंभीर नदी डैम के नीचे दूषित जल को फिल्टर कर पुनः प्रवाहित किया जाएगा। साथ ही सिलारखेड़ी परियोजना अंतर्गत वर्षा जल को संग्रहित कर वर्ष भर क्षिप्रा में स्वच्छ जल प्रवाहित किया जाएगा।

परिवहन और अधोसंरचना को भी मिला विस्तार

सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि ₹1018 करोड़ की लागत से रतलाम-नागदा रेलवे लाइन को फोरलेन करने की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे आगामी सिंहस्थ में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।

घाट नहीं, संस्कृति का गौरव

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंतहरि गिरी जी महाराज ने घाट निर्माण को संस्कृति के पुनर्जागरण की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु घाटों का विस्तार आवश्यक था और सरकार ने इसे साकार कर दिखाया है।

सिंहस्थ : संस्कृति, सुविधा व समर्पण का संगम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल एक सिंहस्थ का आयोजन नहीं, बल्कि उज्जैन को वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाना है। मां क्षिप्रा का आशीर्वाद और संत समाज का मार्गदर्शन इस कार्य को दिव्यता प्रदान कर रहा है।

Page-15_Layout 1 6/7/2025 2:24 PM Page 1

4 साल से माता-पिता के शवों के साथ रह रही थी महिला

दिल दहलाने वाली दुखद कहानी

निज संवाददाता : यह वाकई में दिल दहला देने वाली और एक दुखद कहानी है। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई अपने ही माता-पिता के साथ इतना भयानक कृत्य कैसे कर सकता है। लंदन की वर्जीनिया मैककुलॉ ने पैसों की खातिर अपने मां-बाप की न सिर्फ बेरहमी से जान ली, बल्कि 4 साल तक उनके शवों को घर में ही छिपाकर रखा, जो उसकी क्रूरता और निर्दयता को दर्शाता है।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 36 साल की वर्जीनिया ने जून 2019 में अपनी मां लोइस और पिता जॉन मैककुलॉ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दोनों की उम्र करीब 70 साल थी। इसके पीछे महिला के सिर पर भारी कर्ज और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी के पर्दाफाश होने का डर बताया गया है। वर्जीनिया को आशंका थी कि अगर उसके माता-पिता सच जान गए, तो वह फंस जाएगी, और इसी डर के कारण उसने यह खौफनाक कदम उठाया।यही नहीं, निर्दयी बेटी ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की आड़ में माता-पिता के बैंक अकाउंट्स से पैसे निकालने और पेंशन लेने का सिलसिला जारी रखा।

वहीं, दोनों डेडबॉडी को घर में ही छिपाकर चार साल तक अपने माता-पिता के नाम से मैसेज करती रही, और लोगों को यह कहकर गुमराह करती रही कि दोनों टूर पर हैं।कोर्ट ने वर्जीनिया को 36 साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, इस मामले में सबसे ज्यादा पीड़ा और पछतावा उनकी बड़ी बहन लुईस हॉपकिंस के हिस्से आया, जो अब भी इस सच्चाई से उबर नहीं पाई हैं। हाल ही में लुईस ने एक पॉडकास्ट से बातचीत में बताया कि वह 1997 में ही अपना घर छोड़ चुकी थीं। 2018 तक परिवार से पूरी तरह अलग हो गईं।लुईस अपराधबोध होकर कहती हैं, मैं यही सोचती हूं कि काश घर में होती, तो शायद यह सब कुछ नहीं होता। मेरे मम्मी-पापा सड़ते रहे, मेरे लिए इससे भयावह बात और कुछ नहीं। उन्होंने कहा, मैंने बहन माफ तो कर दिया, पर जीवन में कभी उसका चेहरा

वर्जीनिया को आशंका थी कि अगर उसके माता-पिता सच जान गए, तो वह फंस जाएगी, और इसी डर के कारण उसने यह खौफनाक कदम उठाया

नहीं देखूंगी।कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के अनुसार, वर्जीनिया ने पहले पिता को जहर देकर मार डाला। अगली सुबह जब मां को पता चला, तो उनकी भी हत्या कर दी। महिला का कहना है कि जब उसकी मां रेडियो सुन रही थी, तभी उसने हथौड़े से जानलेवा हमला किया। लेकिन जब हथौड़ा बेअसर रहा, तो चाकू घोंपकर जान ले ली।

महिला ने पहले पति को मारा, फिर मां को मैसेज भेजा

'मैंने कुछ बुरा किया है'

कोर्ट ने महिला को उम्रकैद की सजा दी लेकिन महिला खुद को बचाने के लिए मानसिक बीमारी का हवाला देने लगी

लंदन : जीवन में प्यार और रिश्ते कभी-कभी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब मन में शक और भ्रम आ जाए तो वे बर्बाद भी हो सकते हैं। एक ऐसा ही मामला इंग्लैंड के बाल्टनसबरो में सामने आया है, जो रिश्तों की जटिलता और मानसिक उलझनों को दर्शाता है। यहां की रहने वाली एक महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी। इसके बाद महिला ने अपनी मां को मैसेज भेजकर पूछा, 'मैंने कुछ बुरा कर दिया?' महिला का नाम क्रिसिन केक्कोनन (37 साल) है, जिसने अपने पति हेनरी (41 साल) की चाकू मारकर हत्या कर दी। जब यह मामला लोगों के सामने आया तो सबके होश उड़ गए। हाल ही में कोर्ट ने इस मामले में क्रिसिन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि क्रिस्टीन ने हेनरी के पास बिस्तर के किनारे चाकू छुपा रखा था। यह बात साफ करती है कि यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि यह सोच-समझकर किया गया कृत्य था। बता दें कि 9 मई 2024 की शाम बाल्टनसबरो में क्रिसिन और उनके पति हेनरी अपने घर में थे। शाम 4 से 4:20 के बीच क्रिसिन ने हेनरी के गले में चाकू मार दिया। इसके ठीक एक मिनट बाद यानी 4 बजकर 21 पर उसने अपनी मां को मैसेज किया, 'मां, मैंने कुछ बुरा किया। पुलिस बुलाओ, जल्दी।' फिर उसने कहा, 'प्लीज, अभी मदद चाहिए।' ऐसे में पति की हत्यारन क्रिसिन के पापा ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। 15 मिनट में पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन हेनरी को बचा नहीं सके। पुलिस को घर में एक चाकू मिला, जो बिस्तर के पास छिपा था। क्रिसिन को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का इल्ज़ाम लगा। कोर्ट में मामला पहुंचा तो क्रिसिन एक अलग ही कहानी बयां करने लगी। उसने बताया कि उसे दिमागी बीमारी है, जिससे कभी-कभी उसे कुछ याद नहीं रहता। उसने जानबूझकर हेनरी को नहीं मारा लेकिन कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी। जज जूलियन लैम्बर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'चाकू छिपाने से लगता है तुमने सोच-समझकर ऐसा किया।' उन्होंने क्रिसिन की मानसिक बीमारी की बात को ठोस कारण मानने से इनकार कर दिया और कहा, 'शायद तुम्हे खुद नहीं पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया।' कोर्ट में हेनरी के दोस्तों, पड़ोसियों और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स ने गवाही दी कि हेनरी हमेशा दयालु और देखभाल करने वाले पति थे। उन्होंने कभी अपनी पत्नी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। बल्कि हेनरी हमेशा अपनी पत्नी की भलाई को अपने फायदे से ऊपर रखते थे। ऐसे में क्रिस्टीन ने खुद को मानसिक रूप से परेशान और शिकार बताने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इसे बहाना माना और कहा कि मानसिक बीमारी का हवाला देकर इतना बड़ा अपराध नहीं छुपाया जा सकता। ब्रिस्टल की अदालत ने उसे हत्या का दोषी बताया। बीते 23 मई 2025 को इस मामले का फैसला आया, जिसमें जज ने क्रिसिन को उम्रकैद की सजा दी। उसे कम से कम 15 साल जेल में रहना होगा।बता दें कि मृतक हेनरी के पिता ओलावी फिनलैंड में रहते हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा, 'मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह 9 बजे पुलिस आई और बताया कि हेनरी मर गया। मेरा दिल टूट गया' ओलावी ने कहा कि वो क्रिसिन से नफरत नहीं करते, 'गुस्सा बेकार है।' लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्रिसिन खुद को बेगुनाह क्यों कह रही थी। वहीं, हेनरी की सौतेली बहन हेल्मीना ने कहा, 'मैं अपने भाई से कभी नहीं मिली। मैं उसके गेम्स देखती थी और उसे बहुत अच्छा भाई मानती थी। अब वो चला गया और मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं देगा।' उसने बताया कि पापा का फोन आया, 'हेनरी मर गया।' वो रो पड़ी और बोली, 'मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला।' पुलिस ऑफिसर लोरेट स्पायरेनबर्ग ने कहा, 'क्रिसिन ने हेनरी के परिवार को बहुत दुख दिया। उसने कहा वो बेगुनाह है, लेकिन ये गलत था। हेनरी को उसने मारा, जिस पर वो भरोसा करता था।' उन्होंने कहा, 'कोर्ट से सजा मिली, लेकिन हेनरी वापस नहीं आएगा।'

अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का खाटू में द्वितीय अग्र विभूति अलंकरण समारोह 12 को

तैयारियां जोरों पर

निज संवाददाता : अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के आगामी 12 जून को बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में होने जा रहे द्वितीय अग्र विभूति अलंकरण समारोह को लेकर तैयारियां जोरो से चल रही हैं। इस आयोजन में जहां लगभग 500 समाज बंधुओं के आने की संभावना बताई जा रही है तो वहीं इस पूरे आयोजन में संस्था द्वारा डेलीगेट कार्ड एवं अग्रिम पंजीयन के माध्यम से आने वाले समाज बंधुओं को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाएगी एवं कार्यक्रम को लेकर जहां 12 जून को सुबह उद्घाटन सत्र के साथ ही अग्रवाल समाज की अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली 37 महान विभूतियों का अलंकरण के माध्यम से सम्मान किया जाएगा तो वहीं भारतीय संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अग्रवाल समाज के विद्यार्थियों का भी सम्मान होगा। कोलकाता में संपन्न हुए प्रथम अग्र अलंकरण 2024 से भी ज्यादा अग्र बंधुओं ने द्वितीय अग्र अलंकरण के 37 क्षेत्रों के लिए अलग -अलग क्षेत्रों में अपना आवेदन प्रेषित किया है। उत्साहवर्धन स्वरूप अग्र कुल के प्रतिभावान सदस्यों के वरीयता के आधार पर आवेदन को 'अग्र गौरव सम्मान' से नवाजे जाने का निर्णय भी लिया गया है एवं उक्त अवसर पर सभी समाज बंधुओं को गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में मंच पर बुला कर सम्मानित किया जाएगा।

उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष श्री राज कुमार मित्तल के दिशा निर्देशन एवं संस्था

की मथुरा एवं मथुरा महानगर जिला इकाई के आतिथ्य में किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन की समस्त प्रदेश इकाईयां एवं द्वितीय अग्र विभूति अलंकरण समारोह आयोजन समिति के सदस्य दिन-रात मेहनत कर कार्यक्रम के सफल आयोजन की तैयारियों में लगे हुए हैं तथा पूरे कार्यक्रम को लेकर संस्था के सम्माननीय सदस्यों में उत्साह देखा जा रहा है। इस अवसर पर खाटू धाम राजस्थान के विभिन्न भवनों को भी आगंतुक समाज बंधुओं के लिए आरक्षित किया गया है एवं अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित द्वितीय अग्र विभूति अलंकरण समारोह 2025 कार्यक्रम स्थल श्याम अर्पण 'छत्तीसगढ़ भवन' कोतवाली रोड खाटू श्याम जी सीकर (राजस्थान) में होगा।

आयोजन को सफल बनाने में राष्ट्रीय संरक्षक अजय कांत गर्ग, संस्थापक कोषाध्यक्ष गणेश भरतीया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री पवन मित्तल, राष्ट्रीय संयोजिका महिला इकाई सुशीला फरमानिया के मार्गदर्शन में एवं मथुरा, मथुरा महानगर जिला इकाई के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य जुटे हुए हैं। अग्र अलंकरण 2025 कार्यक्रम के संरक्षक कृष्ण कन्हैया गोयल एवं राष्ट्रीय संयोजिका, अग्र अलंकरण उमा बंसल के मार्गदर्शन में 37 विभूतियों का चयन कर सूची भी घोषित की जा चुकी हैं एवं सम्माननीय प्रायोजक परिवार एवं चयनित विभूति परिवारों से आने वाले प्रतिनिधियों की सूची केंद्रीय मुख्यालय द्वारा मांगी गई है। पूरे आयोजन को लेकर जहां 12 जून के उद्घाटन सत्र में देश की प्रतिष्ठित राजनैतिक एवं सामाजिक हस्तियां इस कार्यक्रम की शोभा होंगी तो वही आगंतुक अतिथियों में प्रमुख रूप से लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री वृज मोहन अग्रवाल, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर श्री गणेशी लाल, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री दामोदर अग्रवाल, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर नरेश बंसल एवं जयपुर मालवीय नगर के सम्माननीय विधायक श्री काली चरण सराफ एवं अन्य समाज की प्रमुख हस्तियों के भी आने का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है तथा 12 जून एवं 13 जून के कार्यक्रम को लेकर आगंतुक समाज बंधुओं के लिए राजस्थान के परम्परा के अनुरूप सुंदर भोजन व्यवस्था एवं हाइटी के लिए भी व्यवस्था हो चुकी हैं तथा बाबा खाटू श्याम के भी दर्शन का लाभ समाज बंधुओं को इस दौरान मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के केंद्रीय मुख्यालय ने सभी सम्माननीय सदस्यों एवं समाज बंधुओं को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है।

रेलवे का बड़ा फैसला, सियालदह दक्षिण शाखा को मिलीं कई नई ट्रेनें

निज संवाददाता: भारतीय रेलवे में सियालदह में यात्रियों की भी बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने भीड़ से निपटने के लिए रेलवे सियालदह की दक्षिणी शाखा पर नई ट्रेनें चलाएगा। रेलवे ने बालीगंज-नामखाना और बालीगंज-कैनिंग शाखाओं पर विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। नया फैसला 5 जून से लागू हो गया। इसके अलावा, भारतीय रेलवे यात्रियों की मांग के अनुपालन में सियालदह-कोलकाता-लालगोला मार्ग पर 11 मेमू के चरित्र में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। पता चला है कि नामखाना लोकल शाम 6.35 बजे सोनारपुर से रवाना होगी। बालीगंज ट्रेन सुबह 5.12 बजे नामखाना से रवाना होगी। ट्रेन सुबह 8.04 बजे बालीगंज से कैनिंग के लिए रवाना होगी। बालीगंज लोकल सुबह 9.40 बजे कैनिंग से रवाना होगी। सोनारपुर

लोग स्टेशन पर शौचालय का इस्तेमाल कर फिर से ट्रेन पकड़ सकेंगे

लोकल सुबह 11.25 बजे बालीगंज से रवाना होगी।इस बीच, पूर्व रेलवे ने सियालदह, कोलकाता और लालगोला के बीच चलने वाली 11 मेमू ट्रेनों को ईएमयू सेवाओं में बदलने की घोषणा की थी। इसे 4 जून से लागू किया जाना था। इस घोषणा के बाद, लालगोला ट्रेन के दैनिक यात्री नाराज थे। उनका आरोप था कि इस लंबी यात्रा में मेमू ट्रेन में शौचालय हैं। ईएमयू में शौचालय नहीं होने से परेशानी होगी। हालांकि रेलवे ने कहा था कि लालगोला की संशोधित रेक कृष्णानगर में आधे घंटे के लिए रुकेगी। जहां लोग स्टेशन पर शौचालय का इस्तेमाल कर फिर से ट्रेन पकड़ सकेंगे। हालांकि, यात्री इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यात्रियों ने लालगोला ट्रेन रोकने की धमकी दी। इसके बाद यात्रियों के दबाव के आगे रेलवे ने अपना फैसला बदल दिया। रेलवे 10 जून को हावड़ा स्टेशन परिसर से फेरीवालों को हटा देगा। रेलवे ने कहा कि यात्रियों के हित में यह निष्कासन जरूरी है। हावड़ा स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों पर रोक के कारण फेरीवाले यात्रियों की आवाजाही में अत्यधिक कठिनाई पैदा कर रहे हैं। नतीजतन, इन्हें हटाना अत्यावश्यक हो गया है। दूसरी तरफ रेलवे के इस फैसले से आम लोगों ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि नयी ट्रेनें शुरू होने से सियालदह दक्षिण शाखा में दैनिक यात्रियों समेत अन्य मुसाफिरों को भी लाभ होगा।

गंभीर समाचार

RNI No. WBHIN/2014/59321,
ISSN No. 2456/3005 Kolkata

कोलकाता, 10 जून 2025

बार्सिलोना ने ला लीग जीतकर अर्जित की रिकॉर्ड राशि

कोच हांसी फ्लिक के नेतृत्व में बार्सिलोना ने रचा इतिहास

निज संवाददाता : बार्सिलोना ने एस्पानयोल को 2-0 से हराकर अपना 28वां ला लीग खिताब हासिल किया है। स्पेनिश सुपर कप और कोपा डेल रे में जीत के साथ, कैटलन दिग्गजों ने ऐतिहासिक तिगुनी जीत हासिल की है। यह 36 वर्षों में उनकी पहली तिगुनी जीत है। कोच हांसी फ्लिक के नेतृत्व में, बार्सिलोना ने इस सीजन में इतिहास रचा है। लामिन यमल के शानदार गोल और फ़र्मिन लोपेज़ के अंतिम मिनटों में असाधारण फिनिश ने ला लीगा खिताब सील कर दिया। टीम ने एक सीजन में चिर प्रतिद्वंद्वी रियल मैड्रिड के खिलाफ चार एल क्लासिको मैच जीतकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है।ला लीगा का राजस्व वितरण मॉडल अद्वितीय है, जिसमें चैंपियनों के लिए कोई निश्चित पुरस्कार राशि नहीं है। इसके बजाय, लीग के शासी निकाय 20 क्लबों के बीच उनके अंतिम स्थान के आधार पर टेलीविजन अधिकार राजस्व वितरित करते हैं। 2024-25 सीज़न के लिए, कुल 343.5 मिलियन आवंटित किए जाएंगे।चैंपियन के रूप में, बार्सिलोना पूल का 17 फीसदी प्राप्त करेगा, जो लगभग 58.4 मिलियन होगा। उपविजेता रियल मैड्रिड को 15 फीसदी (51.5 मिलियन) मिलेगा। अन्य टीमों के लिए राजस्व हिस्सेदारी उत्तरोत्तर घटती जाएगी, सबसे निचली टीम को केवल 0.25 फीसदी (0.9 मिलियन) मिलेगा।ला लीगा राजस्व के अलावा, बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप से 9 मिलियन और कोपा डेल रे से 1.2 मिलियन अर्जित किए हैं। घरेलू प्रतियोगिताओं से उनकी कुल कमाई 60 मिलियन और 90 मिलियन के बीच होने का अनुमान है।

बार्सिलोना ने इंटर मिलान के खिलाफ यूईएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में पहुंचने से कम से कम 83 मिलियन भी अर्जित किए हैं। हालांकि, क्लब को पूरी राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी अधिकार राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिक्स्थ स्ट्रीट को जाएगा, एक अमेरिकी निवेश फर्म जिसने बार्सिलोना के भविष्य के टीवी अधिकारों का एक हिस्सा खरीदा है। इसके बावजूद, बार्सिलोना की सीजन की कमाई उन्हें अगले सीजन के लिए एक मजबूत टीम बनाने में सक्षम करेगी, जो उनके पेशेवरवाद और वित्तीय प्रबंधन का प्रदर्शन करेगी।

कोलकाता फुटबॉल लीग 2025 का आगाज जल्द

निज संवाददाता : कोलकाता फुटबॉल लीग पर से पर्दा उठ गया है। पहली बार कोलकाता फुटबॉल लीग के प्रीमियर डिवीजन मैचों के लिए ड्रॉ प्रतिष्ठित कलकत्ता रोइंग क्लब में आईएफए कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया। प्रीमियर डिवीजन में प्रतिस्पर्धा करने वाली टीमों के प्रतिनिधि, प्रीमियर और प्रथम डिवीजन लीग समितियों के सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रीमियर डिवीजन के ड्रॉ में कोलकाता फुटबॉल के दिग्गज पूर्व फुटबॉलर शामिल हुए, जिनमें भास्कर गांगुली, अतनु भट्टाचार्य, जमशेद नासिरी, प्रशांत बनर्जी, मनोरंजन भट्टाचार्य, मानस भट्टाचार्य, अमित भद्र, आलोक मुखर्जी, शिशिर घोष, संजय सेन, दीपेंदु विश्वास, अल्विटो डीकुन्हा, रहीम नबी, मेहताब हुसैन और सुब्रत पाल शामिल थे। इस कार्यक्रम में अन्य उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में राहुल तोदी (प्रबंध निदेशक, साची स्पोर्ट्स), तमाल घोषाल (अध्यक्ष-साची स्पोर्ट्स), अजीत बंद्योपाध्याय (आईएफए अध्यक्ष), सुब्रत दत्ता (आईएफए-चेयरमैन), अनिर्बान दत्ता (आईएफए-सचिव), राकेश झा (आईएफए-संयुक्त सचिव), मोहम्मद जमाल, सुदेशना मुखर्जी और सुफल रंजन गिरि, कार्यकारी सचिव शामिल थे।

आरसीबी की जीत पर ऋषि सुनक ने भी मनाया जश्न

पत्नी के साथ चीयर करने पहुंचे अहमदाबाद

निज संवाददाता : यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का फाइनल मैच देखा। वह अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ मैच में शामिल हुए और आरसीबी के लिए उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। सुनक विराट कोहली के बड़े प्रशंसक हैं और उन्होंने बताया कि उन्हें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक हस्ताक्षरित बल्ला उपहार में दिया है। उन्होंने आरसीबी के इंग्लिश खिलाड़ियों फिल सॉल्ट और लियाम लिविंगस्टोन के अच्छे प्रदर्शन की सराहना की और आरसीबी को ट्रॉफी जीतते हुए देखकर खुशी जताया। सुनक की उपस्थिति ने मैच में सेलिब्रिटी अपील को बढ़ा दिया और खेल के प्रति उनकी दृश्यमान जुड़ाव ने दर्शकों को आकर्षित किया। वह स्टेडियम के इलेक्ट्रिक माहौल से प्रभावित हुए और कहा कि मैंने कभी भी इस तरह के क्रिकेट का अनुभव नहीं किया है। फाइनल मैच में सुनक के पास आईसीसी के वाइस चेयरमैन जय शाह भी मैच का लुत्फ उठाते नजर आए। सुनक ने अपनी पत्नी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की, जिसमें कैप्शन था 'चलो, @RCBTweets 'जिससे आरसीबी के प्रति उनका समर्थन दिखाया गया।

उज्बेकिस्तान और जॉर्डन पहली बार विश्व कप में

शुभ्रांशु रॉय

दो एशियाई देशों, उज्बेकिस्तान और जॉर्डन ने 2026 विश्व कप में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पहली बार पुरुषों के विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है। गत गुरुवार को, उज्बेकिस्तान ने एशियाई क्वालीफायर के तीसरे दौर में ग्रुप ए में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ 0-0 से ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के परिणामस्वरूप, एक मैच शेष रहते हुए ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ने चार अंकों से विश्व कप के लिए स्थान हासिल किया।जापान और ईरान के बाद उज्बेकिस्तान विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली एशियाई क्षेत्र की पाँचवीं टीम बन गई। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा सहित तीन मेजबान देशों सहित कुल आठ टीमों के बीच विश्व कप में जगह बनाई। उज्बेकिस्तान के डिफेंडर अब्दुकादिर खुसानोव इस साल जनवरी में इंग्लिश दिग्गज मैनचेस्टर सिटी में शामिल हुए। टीम के कप्तान एल्डोर शोमुरोदोव इतालवी क्लब रोमा के लिए खेलते हैं। राष्ट्रीय टीम के कोच पूर्व मिडफील्डर तैमूर कपाडज़े हैं, जिन्होंने देश के लिए 119 मैच खेले हैं।1991 में पूर्व सोवियत संघ के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला उज्बेकिस्तान रूस और यूक्रेन के बाद विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला तीसरा पूर्व सोवियत गणराज्य है। दूसरी ओर, जॉर्डन ने भी एक मैच शेष रहते विश्व कप में जगह पक्की कर ली है। टीम ने ओमान को 3-0 से हराकर इराक से चार अंक आगे निकल गई है। अंतिम मैच में उनका सामना इराक से होगा।पूर्व मोरक्को के स्टार फुटबॉलर जमाल सेलामी टीम के प्रभारी हैं। जॉर्डन के फुटबॉल में यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि उन्होंने विश्व कप में जगह पक्की कर ली है। दक्षिण कोरिया ने भी आज विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। वे इराक को 2-0 से हराकर लगातार 11वीं बार फीफा विश्व कप में खेलेंगे। टीम का नेतृत्व इंग्लिश क्लब टोटेनहम हॉटस्पर के स्टार फॉरवर्ड सोन ह्युंग-मिन कर रहे हैं।

नजरुल इस्लाम की कविताओं को मो. स्पोर्टिंग क्लब के टेंट में मिली जगह

सम्राट मिश्रा

26 मई को बंगाल के 11वें सबसे बुजुर्ग और विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम के 126वें जन्मदिन के अवसर पर मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और छायानॉट की संयुक्त पहल पर क्लब टेंट में चेतना नजरुल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब के पदाधिकारी, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी, पत्रकार, शोधकर्ता और कलाकार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत छायानॉट के कलाकारों द्वारा एक नजरुल गीत से हुई। काजी नजरुल इस्लाम का फुटबॉल के प्रति प्रेम जगजाहिर है। एक समय में वे कोलकाता के मैदान में नियमित रूप से आते थे। 1934 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब कोलकाता फुटबॉल लीग जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना, जो 1911 में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट के मोहन बागान की ब्रिटिश सैन्य टीम को हराकर आईएफए शील्ड जीतने के बाद किसी भी भारतीय टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। और उस सफलता के सम्मान में, नज़रुल ने मुबारकबाद नामक एक कविता लिखी। इस कविता के माध्यम से उन्होंने न केवल फुटबॉल के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया, बल्कि धर्म या जाति से परे पूरे युवा समाज को जागृत करना चाहते थे। आज कविता को फ्रेम करके मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के टेंट में स्थापित किया गया। मोहम्मडन के उपाध्यक्ष मोहम्मडन कमरुद्दीन पहली बार क्लब में नजरुल जयंती मनाने को लेकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि अगले साल इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर मनाने की व्यवस्था की जाएगी।

स्वामी मोहता पब्लिशिंग हाउस के लिए, प्रकाशक, मुद्रक अजय कुमार मोहता द्वारा अरिहंत मुद्रा, 61, सूर्यसेन स्ट्रीट, कोलकाता-700009 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादकीय कार्यालय :** 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, (क्लाइव रो), 5बी मंजिल, रूम नं. 9, कोलकाता-700001, **स्थानीय कार्यालय :** 28-5 कन्वेंट रोड, मौलाली, कोलकाता-700014। **संपादक :** अजय कुमार मोहता, मो. 9830045693, (प्रकाशित रचनाओं के चयन, संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी, सभी कानूनी विवाद के लिए कोलकाता न्याय क्षेत्र)